



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 2019/आषाढ़ 26, 1941

No. 250]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 2019/ASHADHA 26, 1941

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### अधिसूचना

मुंबई, 3 जुलाई, 2019

सं. टीएएमपी/20/2018-डीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा दीनदयाल पत्तन (डीपीटी) के मौजूद दरमानों में तूना पत्तन की प्रशुल्क अनुसूची में अलग से अनुसूची-V अंतर्विष्ट करने के लिए डीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव का इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/20/2018-डीपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास

- - -

आवेदक

### गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

### आदेश

(जून, 2019 के 14वें दिन पारित)

यह मामला दीनदयाल पत्तन (डीपीटी) के मौजूदा दरमानों में तूना पत्तन की प्रशुल्क अनुसूची में अलग से अनुसूची-V अंतर्विष्ट करने के लिए डीपीटी के प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने 21 जून, 2016 के अपने आदेश संख्या टीएएमपी/18/2016-केपीटी के द्वारा दरमानों के सामान्य संशोधन के डीपीटी के प्रस्ताव का निपटान करते हुए संशोधित दरमानों का अनुमोदन किया था। इस प्राधिकरण द्वारा 21 जून 2016 के आदेश द्वारा अनुमोदित संशोधित दरमान और निष्पादन मानक 12 जुलाई 2016 के राजपत्र संख्या 287 में अधिसूचित हुए थे। बाद में 10 अगस्त, 2016 के राजपत्र संख्या 319 में सकारण आदेश अधिसूचित किया गया था। दरमान भारत के राजपत्र में दरमानों और निष्पादन मानकों की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति से प्रभावी हुए यानी 11 अगस्त, 2016 से। दरमानों की वैधता 31 मार्च, 2019 तक निर्धारित की गई थी। डीपीटी के वर्तमान दरमानों की वैधता का 30 सितंबर, 2019 तक विस्तार किया गया है और इसकी सूचना 29 मार्च, 2019 के हमारे पत्र संख्या टीएएमपी/39/2005-विविध के द्वारा डीपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों को दी गई।

2.2. डीपीटी ने अब 13 मार्च, 2018 के अपने पत्र के द्वारा दीनदयाल पत्तन (डीपीटी) के मौजूदा दरमानों में तूना पत्तन की प्रशुल्क अनुसूची में अलग से अनुसूची-V अंतर्विष्ट करने के लिए डीपीटी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। डीपीटी द्वारा रखे गए मुद्दों का सारांश निम्नवत् है:-

- (i). पहले तूना पत्तन के दरमान अलग से होते थे और दरों का निर्धारण पोतों की किस्म, प्रहस्तित किये जाने वाले कार्गो की किस्म, अपेक्षित ड्राफ्ट आदि को ध्यान में रखकर निर्धारित किये जाते थे। तथापि, डीपीटी के दरमानों के संशोधन (11 अगस्त, 2016 से प्रभावी) में अध्याय-I सामान्य निबंधन और शर्तें तथा शर्त संख्या 1.2 टिप्पणी (xv) निम्नवत् अनुबद्ध करती है:-

*“कांडला दरें तूना पत्तन पर लागू होंगी”*

इसके परिणामस्वरूप तूना पर लागू योग्य पत्तन प्रभारों में अत्यधिक वृद्धि हो गई।

- (ii). साल्या सेलिंग वैसल्स आनर्स एसोसिएशन (एसएसवीओए) से डीपीटी के तूना पत्तन प्रभारों की समीक्षा के लिए 09 सितंबर 2016 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। एसोसिएशन ने बताया है कि नए दरमानों के अनुसार विभिन्न प्रकार के पत्तन प्रभारों में सिवा भारतीय जलयात्रा पोतों (भारतीय कंट्री क्राफ्ट) के अन्य पोतों के लिए लगभग 22% से 36% वृद्धि हो गई है, जलयात्रा पोतों के लिए पत्तन प्रभार 700% तक बढ़ गए हैं जो भारतीय जलयात्रा पोतों के प्रति अन्याय है।
- (iii). इसके अतिरिक्त, एसोसिएशन ने निवेदन किया है कि इतने अत्यधिक प्रभार कमजोर उद्योग द्वारा वहन नहीं किये जा सकते और इससे व्यापार के साथ-साथ भारतीय जलयात्रा पोत उद्योग भी प्रभावित होगा।
- (iv). प्राधिकरण ने एसएसवीओए के अभ्यावेदन को डीपीटी की टिप्पणियों के लिए 12 सितंबर, 2016 के अपने पत्र संख्या टीएएमपी/18/2016-केपीटी के द्वारा डीपीटी को भेजा।

[तथापि, इस संबंध में हमें डीपीटी से कोई उत्तर नहीं मिला।]

- (v). मैसर्ज अदानी कांडला बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एकेबीटीपीएल) ने भी कांडला दरों को तूना पत्तन पर लागू करने और इस प्रकार संदेय लाइसेंस शुल्क में अत्यधिक वृद्धि के प्रति अभ्यावेदन दिया है। मैसर्ज एकेबीटीपीएल ने अभ्यावेदन दिया है कि कांडला दरों को तूना दरों में लागू करने के कारण लाइसेंस शुल्क में 2700% की अत्यधिक वृद्धि हो गई है, जिससे उनकी सुविधाएं अव्यवहारिक हो गई हैं।
- (vi). प्राधिकरण ने अपने 21 सितंबर, 2016 के पत्र संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी के द्वारा एकेबीटीपीएल के 16 अगस्त, 2016 के तूना पत्तन दरों के संबंध में तत्कालीन मौजूदा दरमानों के, डीपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित, अध्याय-V को विलुप्त करने के बारे में अभ्यावेदन को डीपीटी को अग्रपिष्ट किया और प्रयोजनीय दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए तूना पत्तन पर भूमि के किरायों के संबंध में उपयुक्त प्रस्ताव

दायर करने का अनुरोध किया। फिर भी, प्राधिकरण ने 10 अक्टूबर, 2017 के ई-मेल द्वारा मैसर्ज एकेवीटीपीएल से 27 सितंबर, 2017 को इसी मामले में प्राप्त ई-मेल की प्रति अग्रेषित की और अनुरोध किया कि तूना पत्तन पर भूमि के किरायों के संबंध में उपयुक्त प्रस्ताव दायर करें।

(vii). तूना पत्तन के लिए निम्नलिखित आधार पर समीक्षा करना उचित है:-

- (क). घाट प्रभारों में लगभग 200%, बर्थ किराया प्रभार में 150% और टून पत्तन की पत्तन देयताओं में 500% की वृद्धि हुई है जो अत्यधिक ऊँची है।
- (ख). डीपीटी द्वारा तूना पर तलकर्षण पर कोई व्यय नहीं किया गया है।
- (ग). तूना पर न्यूनतम कर्मचारी तैनात हैं और इस प्रकार, मानवशक्ति पर लागत काफी कम है।
- (घ). तूना पर पशुधन का प्रहस्तन होता है जिससे घाट आदि को मुश्किल से ही कोई क्षति होती है।
- (ङ). टून बांडी और निकटवर्ती अन्य गांवों की जीविका तूना से पशुधन के निर्यात पर निर्भर है।
- (च). मशीनीकृत क्राफ्ट स्वामी अमीर नहीं है और वे बैंक/वित्तीय संस्थानों से ऋण पर ही निर्भर हैं।

(viii). तदनुसार, तूना पत्तन के दरमानों की समीक्षा करने के लिए यातायात प्रबंधक, उप-संरक्षक, मुख्य अभियंता और वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को मिलाकर एक समिति का गठन किया गया।

(ix). समिति ने 22 नवंबर, 2016 को हुई अपनी बैठक में (अनुलग्नक क पर प्रति संलग्न) मत व्यक्त किया कि डीपीटी तूना पत्तन के लिए तलकर्षण अथवा नौसंचालन सहायकों पर कोई व्यय नहीं करता है अतः डीपीटी के लिए निर्धारित दरें तूना पत्तन पर लागू नहीं हो सकतीं।

(x). तूना पत्तन के पोत संबंधी प्रभारों के बारे में, समिति ने, विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया कि सभी पोत संबंधी प्रभारों, जो 2011 में अनुमोदित किये गए थे, पुरानी दरों से वृद्धि की जाए, जो 100% थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनुरूप उपयुक्त वृद्धि हो और तदनुसार दर निर्धारित की जाए।

(xi). तूना पत्तन के कार्गो संबंधी प्रभारों के बारे में समिति ने चर्चा की कि डीपीटी ने उस पत्तन पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन पर जैसे सड़के, बर्थ, बार्ज जेटी, पृष्ठ क्षेत्र, प्रकाश आदि, काफी राशि का निवेश किया है और इस प्रकार कार्गो संबंधी प्रभारों को कम करना उपयुक्त नहीं है। तथापि, जैसा पत्तन प्रयोक्ताओं ने, नामतः मैसर्ज एसएसवीओए, अनुरोध किया है, 'पशुधन' और कंट्री क्राफ्ट द्वारा प्रहस्तित कार्गो की दर कम करने के बारे में अनुकूलतापूर्वक विचार किया जा सकता है और इसे 2011 की दर को दी जाने वाली वृद्धि के आधार पर निकाला जा सकता है।

(xii). इसके अतिरिक्त, समिति ने सिफारिश की है कि भंडारण प्रभारों को दो श्रेणियों में बाटा जा सकता है अर्थात् पक्का प्लाट और कच्चा प्लाट। पक्का प्लाट के लिए कांडला पत्तन की दरें लागू होंगी और कच्चे प्लाटों के लिए तूना पत्तन क्षेत्र के लिए मूल्यांकक द्वारा दिये गए नवीनतम मूल्यांकन और 20 जनवरी, 2016 को हुई भूमि आबंटन समिति (एलएसी) में अनुमोदित दरें लागू होंगी। मूल्यांकक द्वारा निकाली गई उच्चतम दर पर सुविचार के लिए एलएसी द्वारा संस्तुति नीचे सारणी में दी जाती है:

क्र.सं.	विवरण	सीआरजैड जोन	किस प्रयोजन के लिए उपयुक्त	विकसित/ अविकसित	उच्च ज्वार/ क्रीक क्षेत्र	मूल्यांकन	पट्टा के भूमि के लिए (-) घटाएं (25%)	अंतिम मूल्यांकन के @ 6% पर पट्टा किराया राशि (रु.) प्रति वर्ग मीटर
1	तूना में बार्ज प्रहस्तन जेटी को जाने वाली पट्टा सड़क के पूर्व की	सीआरजैड -III	नमक उत्पादन,	अविकसित,	खुली अविकसित	₹.2,645/-	1,983.75	119.03

	ओर पड़ने वाली भूमि (एचएच 8क से तूना तक 10 कि.मी. लंबी)		सीएफएस, टैंक फार्म उद्योग, भंडागार	परंतु 10 कि.मी. सड़क से पहुंच	भूमि			
2	संकरी खाड़ी के किनारे से आधा किलो मीटर दूर की भूमि	सीआरजैड-III	भांडागारों नमक उत्पादन, सीएफजैड, टैंक फार्म के लिए उपयुक्त	अविकसित	खुली भूमि	₹.2,300/-	1,725.00	103.50
3	बार्ज प्रहस्तन जेडी की संकरी खाड़ी से आधे किलो मीटर के भीतर भूमि जिसका कोई जलाग्र क्षेत्र नहीं।	सीआरजैड-II	भांडागारों सीएफजैड, टैंक फार्म के लिए उपयुक्त	अविकसित	उच्च ज्वार क्षेत्र	₹.1,955/-	1,466.25	87.98
4	जलाग्र वाली भूमि और बार्ज प्रहस्तन जेटी से आधे किलो मीटर तक अर्थात् उत्तर की ओर	सीआरजैड-I	जेटी संभरण प्रचालन और सीएफजैड के लिए उपयुक्त	अविकसित	उच्च ज्वार क्षेत्र	₹.1,725/-	1,293.75	77.63 #

[# डीपीटी द्वारा प्रस्तावित 84.03 रु. पत्तन द्वारा 77.63 रु. और उस पर 2013 से 2016 तक 2% लागू करके निकाला गया है।]

[डीपीटी ने बाद में 11 अप्रैल, 2018 के अपने पत्र द्वारा स्पष्ट किया कि तूना पत्तन के कच्चा प्लाटों के भंडारण प्रभारों का प्रस्ताव करते समय, संशोधित एलपीजी 2014 के अंतर्गत मूल्यांकन द्वारा दिये गए नवीनतम भू-मूल्यांकन पर दर निर्धारण के लिए विश्वास किया गया। फिर भी, प्रस्तावित दर प्रशुल्क नीति 2015 के अंतर्गत कार्गो संबंधी प्रभारों के अंतर्गत कवर्ड है।]

- (xiii). पत्तन ने बताया है कि एकेबीटीपीएल द्वारा संदेय तूना स्थित भूमि का लाइसेंस शुल्क 208 के आदेश के अनुसार 9.00 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष था। इसे दरमानों के संशोधन पर अर्थात् 11 अगस्त, 2016 को, बढ़ाकर 302.40 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष किया गया। अब समिति की सिफारिश पर लाइसेंस शुल्क 84.03 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष किया गया है। उक्त आंकड़ों को नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:-

**(कुल क्षेत्र 1066345.007 वर्ग मीटर)**

दरमान संशोधन से पूर्व, 2011 के दरमानों के अनुसार, लाइसेंस शुल्क	दरमानों के संशोधन पर 2016 के दरमान के अनुसार लाइसेंस शुल्क	समिति द्वारा संस्तुत दर (2016 को)
प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष	प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष	प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष
9.00 #	302.40 @	84.03 \$

- (xiv). तूना पत्तन पर लागू की गई घटी दरों को वित्तीय प्रभाव कार्गो संबंधी और पोत संबंधी प्रभारों से राजस्व में लगभग 129.53 लाख रु. (यानी घटौती) पड़ेगा। जहां तक मैसर्ज एकेबीटीपीएल से वसूले जाने वाले लाइसेंस शुल्क का संबंध है, इसे प्रशुल्क दिशानिर्देश 2015 के अनुसार एआरआर में सुविचार में नहीं लिया गया है, क्योंकि यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना है, इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं।

[प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यकारी दिशानिर्देश के खंड 2.9 के अनुसार महापत्तन न्यास संबंधित परिवहन के लिए प्रस्तावित दरमानों में प्रशुल्क की प्रत्येक मद की अनुमानित आय का विस्तृत विवरण खंड 2.8 के अनुसार, तैयार करेंगे और यह प्रस्तावित करेंगे कि दरमानों के प्रशुल्क मदों के अब तक निर्धारित राजस्व का योग खंड 2.7 में निर्धारित वार्षिक राजस्व मांग की सीमा के अंदर है और यह व्यवसायगत चार्टरित लेखाकार/लागत और प्रबंधन लेखाकार के द्वारा प्रमाणित हो। इस प्रकार प्राधिकरण के दिशानिर्देश पत्तन से लाइसेंस शुल्क से राजस्व आकलन की अपेक्षा नहीं रखते।

[डीपीटी द्वारा प्रशुल्क नीति 2015 के अंतर्गत लाइसेंस (भंडारण) शुल्क के लिए पिछले प्रशुल्क संशोधन में आकलित एआरआर 24.11 लाख रु. है। आकलित कुल राजस्व 83.551.58 लाख रु. है जिसमें डीपीटी द्वारा तब प्रस्तावित लाइसेंस (भंडारण) शुल्क शामिल है।]

(xv). प्रस्ताव को 26 दिसंबर, 2017 को हुई बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा गया और डीपीटी के न्यासी मंडल ने निम्नलिखित अनुमोदन किया।

(क). तूना पत्तन के लिए अलग प्रशुल्क दर को डीपीटी के दरमान की अनुसूची-V के रूप में जोड़ा जाए, जैसा अनुलग्नक घ में प्रस्तुत है और प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

(ख). वर्तमान अध्याय V का नाम अध्याय Vक रखा जाए।

2.3. संक्षेप में, डीपीटी ने डीपीटी के वर्तमान दरमान में निम्नलिखित अध्याय-V तूना पत्तन की दरें को अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव किया है।

#### अध्याय V – तूना पत्तन की दर

क्र.सं.	विवरण		विदेशगामी पोत (अमरीकी डॉलर में)	तटीय पोत (रु. में)
क.	अनुसूची 1 – पत्तन देयताएं			
1	10 जीआरटी व उससे अधिक के पोतों (मछली पकड़ने की नावों को छोड़कर)	दर प्रति जीआरटी या उसका एक भाग	0.0978	1.3687
2	सेलिंग पोत 10 जीआरटी व उससे अधिक के पोत (मछली पकड़ने की नावों को छोड़कर)	दर प्रति जीआरटी या उसका एक भाग	0.0587	1.1732
ख.	अनुसूची II – बर्थ किराया प्रभार			
1	10 जीआरटी से अधिक के पोत	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसका एक भाग	0.0025	0.0391
ग.	अनुसूची III – बीचिंग प्रभार			
1	बीचिंग प्रभार	दर प्रति एनआरटी प्रति एमटीएच या उसका एक भाग	0.0196	0.3911
	लंगरगाह प्रभार			
	सागरगामी मशीनीकृत नोदक पोत			
	(क). कांडला ओटीबी		*	*

	(ख). भीतरी लंगरगाह (पोत जीआरटी)	दर प्रति 1 घंटा या उसका एक भाग #	0.0010	0.0255
			<b>विदेशगामी पोत (रु. में)</b>	<b>तटीय पोत (रु. में)</b>
<b>घ.</b>	<b>अनुसूची IV – घाटशुल्क प्रभार</b>			
<b>क.</b>	<b>तरल (बल्क में)</b>			
1	कच्चे तेल को छोड़कर बल्क में पीओएल उत्पाद	एम.टी. या उसका भाग	50.00	50.00
2	बंकर सहित अन्य तरल कार्गो	एम.टी. या उसका भाग	50.00	30.00
<b>ख.</b>	<b>शुष्क कार्गो</b>			
1	सल्फर सहित उर्वरक और कच्चा माल	एम.टी. या उसका भाग	33.60	20.16
2	खाद्यन्न, अनाज, दालें और तिलहन	एम.टी. या उसका भाग		
	(i). बल्क		15.00	9.00
	(ii). ब्रेक बल्क		9.00	5.40
3	सीमेंट और क्लिंकर	एम.टी. या उसका भाग	22.50	13.50
4	अयस्क और खनिज (हर प्रकार के)	एम.टी. या उसका भाग	16.88	10.13
5	ग्रेनाइट और मार्बल	एम.टी. या उसका भाग	22.50	13.50
6	धातुएं (फेरस/नान फेरस तथा धातु कबाड, पाइप, पिग लौह, कॉयल शीट व कोयला सहित)	एम.टी. या उसका भाग	37.50	22.50
7	पशु मुर्गे, भेड़ और बकरा सहित	प्रत्येक	6.52	3.91
8	पशु (उक्त को छोड़कर)	प्रत्येक	15.64	9.39
9	पशु उत्पाद अस्थि चूर्ण खल तथा चर्म	एम.टी. या उसका भाग	9.78	5.87
10	खली और चारा	एम.टी. या उसका भाग	15.00	9.00
11	रद्दी कागज़ और अखबारी कागज़	एम.टी. या उसका भाग	30.00	18.00
12	निर्माण सामग्री और बालु	एम.टी. या उसका भाग	16.88	10.13
13	कोयला और कोक (जलावन सहित)	एम.टी. या उसका भाग	25.20	15.12
14	लकड़ी, टिम्बर और बांस	एम.टी. या उसका भाग**	30.00	18.00

15	जूट व जूट उत्पाद तथा कॉयूर उत्पाद	एम.टी. या उसका भाग	22.50	13.50
16	कपास और कपास कबाड़	एम.टी. या उसका भाग	22.50	13.50
17	लवण	एम.टी. या उसका भाग	15.00	9.00
18	शर्करा	एम.टी. या उसका भाग	15.00	9.00
19	एस्बस्टॉस	एम.टी. या उसका भाग	-	-
20	संश्लेषित रेजिन और काष्ठ लुगदी	एम.टी. या उसका भाग	45.00	27.00
21	शस्त्र, गोला, बारूद विस्फोटक और रक्षा भंडार	एम.टी. या उसका भाग	97.50	58.50
22	शुष्क रसायन सोडा ऐश एचडीपीई आदि सहित	एम.टी. या उसका भाग	22.50	13.50
23	अन्य अनिर्दिष्ट सामान	एम.टी. या उसका भाग	52.50	31.50
<b>ड.</b>	<b>अनुसूची V – किराया शुल्क</b>			
1	खुले स्थान हेतु	दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका भाग प्रति माह		
	(i) कच्चा प्लॉट	या उसका भाग (रु. में)		84.03
	(ii) पक्का प्लॉट			432.00
2	क्रवर्ड स्थान हेतु			837.00
3	ऑन बोर्ड टिम्बर भंडारण	दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका भाग प्रति माह या उसका भाग (रु. में)		1.96
<b>च.</b>	<b>अनुसूची VI – ट्राली किराया प्रभार</b>	दर प्रति दिर या उसका भाग (रु. में)		19.55

[# पत्तन ने तूना पत्तन के भीतरी लंगरगाह के लिए लंगरगाह प्रभारों की उगाही यूनिट निर्धारित नहीं की है। चूंकि तूना पत्तन के भीतरी लंगरगाह के लिए लंगरगाह प्रभारों की प्रस्तावित दर वही है जो अनुसूची 3.3 –लंगरगाह प्रभार अनुसूची के अंतर्गत 2016 दरमान आदेश में कांडला भूमि के लिए है, उसी यूनिट को उक्त सारणी में प्रस्तावित किया गया है।

\* जहां तक कांडला ओटीवी के लिए लंगरगाह प्रभारों का संबंध है, डीपीटी ने बाद में 20 नवंबर, 2018 के ई-मेल में स्पष्ट किया कि इसे शून्य समझा जाए।

\*\* जहां तक, काष्ठ, टिम्बर और बांस के घाटशुल्क प्रभारों का संबंध है, डीपीटी ने बाद में 30 नवंबर, 2018 के अपने ई-मेल में स्पष्ट किया कि उक्त मद के लिए उगाही यूनिट को क्यू.एम पढ़ा जाए, न कि एमटी अथवा उसके एक भाग, जैसा 2016 में अनुमोदित किया गया है।]

2.4. इस पृष्ठभूमि में, डीपीटी ने तूना पत्तन के लिए जैसा अध्याय-V ऊपर पैरा 2.3 में दिया गया है, प्रस्तावित दरमान अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। परिणामस्वरूप, तूना/टेकरा स्थित एकेबीटीपीएल द्वारा प्रचालित शुष्क बल्क टर्मिनल पर डीपीटी द्वारा प्रदान की जा रही नौचालन संबंधी सेवाओं के प्रशुल्क से संबंधित मौजूदा अध्याय V को अध्याय V के रूप में नाम रखे जाने का प्रस्ताव किया है।

3.1. डीपीटी ने तूना पत्तन के दरमानों और तूना पत्तन के पट्टा किरायों की समीक्षा के लिए तूना भूमि की दर संरचना के नियतन के साथ तूना पत्तन पर पत्तन संपदा की भूमि मूल्यांकन रिपोर्ट, 26 दिसंबर, 2017 के बोर्ड अनुमोदन की प्रति और डीपीटी के वर्तमान दरमानों में अंतर्विष्ट करने के लिए प्रारूप अध्याय-V तूना पोर्ट दर की प्रति के साथ समिति की 22 नवंबर, 2016 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति भी प्रस्तुत की है।

3.2. यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि 20 जनवरी, 2016 के एलएसी के कार्यवृत्त के पहले पैरा में यह दर्ज है कि एलएसी संस्तुति करती है कि पट्टा भूमि और फ्रीहोल्ड भूमि के बीच अंतर को देखते हुए मूल्यांकन 2012 (रिपोर्ट 2013 में प्रस्तुत) को समीक्षा के लिए मूल्यांकक को लौटा दी जाए। तदनुसार, इस मामले को डीपीटी द्वारा, डीपीटी के 28 दिसंबर, 2015 के पत्र के द्वारा, मूल्यांकक को भेजा गया। एलएसी के कार्यवृत्त बताते हैं कि, मूल्यांकक ने संशोधित मूल्यांकन रिपोर्ट 19 जनवरी, 2016 को प्रस्तुत की। 2016 मूल्यांकन रिपोर्ट का आगे कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त, एलएसी के कार्यवृत्त से यह देखा जाता है कि वर्ष 2012 में किये गए मूल्यांकन (रिपोर्ट 2013 में प्रस्तुत) पर एलएसी ने सुविचार किया। डीपीटी द्वारा 2012 मूल्यांकन रिपोर्ट ही प्रस्तुत की है। डीपीटी ने 19 जनवरी, 2016 की संशोधित मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत नहीं की है।

4.1. यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि, 21 जून, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2016-डीपीटी के द्वारा डीपीटी के वर्तमान दरमान अनुमोदित किये गए थे, तत्कालीन दरमानों में तूना पत्तन के पोत संबंधी प्रभार और घाट संबंधी प्रभारों की दरों की अलग से अनुसूची निर्धारित की गई थी।

4.2. उक्त पिछले दरमानों के पिछले संशोधन में, डीपीटी ने तूना पत्तन के लिए दरों की अलग से अनुसूची को समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर पत्तन ने इस आशय की एक टिप्पणी अंतर्विष्ट की कि कांडला पत्तन पर लागू प्रशुल्क संशोधन पूर्व दरमानों में तूना पत्तन की अलग से दर अनुसूची के प्रति कांडला के समान होंगे। डीपीटी ने प्रत्युत्तर दिया कि तूना पत्तन पर सड़कों और रेल पट्टों आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की गई हैं और डीपीटी ने पुष्टि की है कि तूना में प्रदान की गई सेवाएं, अवसंरचना, उपस्कर और सुविधाएं कांडला प्रभाग में प्रदत्त सेवाओं के तुल्य हैं। बाद में, डीपीटी ने यह भी बताया है कि कांडला पत्तन दरों को तूना पत्तन पर लागू करने के राजस्व प्रभाव को राजस्व आकलन में लिया गया है। पत्तन द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण और औचित्य के आधार पर 21 जून, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2016-केपीटी में तूना पत्तन के लिए कांडला दरों को लागू करने के बारे में डीपीटी की प्रस्तावित टिप्पणी को सामान्य निबंधन और शर्तों के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 1.2 (xv) के रूप में अनुमोदित किया गया था।

4.3. अब डीपीटी ने तूना पत्तन के लिए अलग से दरमानों का प्रस्ताव किया है।

5. डीपीटी के 13 मार्च, 2018 के प्रस्ताव का अवलोकन करने पर डीपीटी को हमारे 27 मार्च, 2018 के पत्र के द्वारा कुछेक मुद्दों पर 06 अप्रैल, 2018 तक सूचना/स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया। डीपीटी ने अपने 11 अप्रैल, 2018 के पत्र द्वारा एक अनुस्मारक के पश्चात्, अपना उत्तर दिया। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण और डीपीटी के उत्तर का सारांश नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:

क्र.सं.	प्राधिकरण द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	डीपीटी का उत्तर
(i).	(क). डीपीटी का विषयक प्रस्ताव पोत संबंधी प्रभारों तथा तूना पत्तन के किरायों की अलग से दरों के अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव से संबंधित है। जैसा डीपीटी भली भांति जानता है कि	प्राधिकरण द्वारा 18.01.2011 के आदेश संख्या टीएएमपी/61/2009-केपीटी के द्वारा प्राधिकरण ने पहले के दरमानों के सामान्य संशोधन का अनुमोदन किया था और



<p>पोत संबंधी प्रभार, कार्गो संबंधी प्रभार और विविध प्रभार प्रशुल्क नीति 2015 द्वारा शासित होते हैं। जबकि, कच्चे भू-खंडों और पक्के भू-खंडों के संशोधित किराया निर्धारण के लिए पत्तन ने संशोधित भू-नीति दिशानिर्देश (एलपीजी) 2014 का अनुपालन किया है और भू-मूल्यांकन रिपोर्ट, एलएसी की बैठक कार्यवृत्त और डीपीटी के न्यासी मंडल का अनुमोदन प्रस्तुत किया है जो संशोधित एलपीजी, 2014 के अंतर्गत किरायों के संशोधन की पूर्वापेक्षाएं हैं।</p> <p>(ख). डीपीटी के प्रशुल्क नीति 2015 द्वारा शासित पोत संबंधी सेवाओं, कार्गो संबंधी सेवाओं, तथा विविध सेवाओं तथा संशोधित एलपीजी 2014 द्वारा शासित किरायों के निर्धारण को मिलाने के पूर्वोक्त प्रस्ताव के संदर्भ में यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि यह दोनों ही दिशानिर्देश दरों के निर्धारण के लिए भिन्न कार्यप्रणाली अपनाते हैं। अधिक तर्कसंगत है कि प्रशुल्क नीति 2015 के अंतर्गत पोत संबंधी प्रभारों, कार्गो संबंधी प्रभारों तथा विविध प्रभारों के संशोधन का आवर्तन प्रत्येक तीन वर्ष है। 21 जून, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/81/2016-केपीटी के अंतर्गत इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वर्तमान दरमानों की वैधता 31 मार्च, 2019 है। डीपीटी ने मौजूदा दरमानों में प्रस्तावित दर को तूना पत्तन के साथ अध्याय V- जोड़ने का प्रस्ताव किया है जो 31 मार्च, 2019 तक वैध है। तथापि, जहां तक किरायों के संशोधन का संबंध है, संशोधित एलपीजी 2014 के खंड 13(ग) के अनुसार दरमानों (किरायों) का संशोधन प्रत्येक पांच वर्ष में होता है।</p> <p>(ग). अन्य संगत भाग वार्षिक वृद्धि से संबंधित है। डीपीटी के मौजूदा दरमानों के अध्याय- 1.2- सामान्य निबंधन और शर्तों की टिप्पणी (viii) (क) और (ख) के अनुसार, जो प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 2.8, 2.9 और 3.2 से प्रवाहित होती है, मौजूदा दरमानों में निर्धारित दरें प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित निष्पादन मानकों की प्राप्ति के अधीन 100% डब्ल्यूपीआई वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। जबकि, संशोधित एलपीजी 2014 के अंतर्गत पत्तन, पत्तन के न्यासी मंडल के अनुमोदन पर किरायों में न्यूनतम 2% की वार्षिक वृद्धि मांग सकता है।</p> <p>(घ). प्रशुल्क नीति 2015 और संशोधित एलपीजी 2014 में उक्त अंतर को ध्यान में रखते हुए डीपीटी स्पष्ट करे कि डीपीटी का तूना पत्तन के प्रस्तावित किरायों का सामान्य दरमानों के साथ जोड़े जाने का प्रस्ताव संशोधित एलपीजी 2014 के उपबंधों का अनुपालन करेगा।</p>	<p>उसमें अलग से एक अध्याय था- अध्याय-V तूना पत्तन की दरें जिसमें निम्नलिखित अनुसूचियां शामिल थीं:-</p> <p>अनुसूची - I : पत्तन देयताएं</p> <p>अनुसूची - II : बर्थ किराया प्रभार</p> <p>अनुसूची - III : बीचिंग प्रभार</p> <p>अनुसूची - IV : घाटशुल्क प्रभार</p> <p>अनुसूची - V : किराया शुल्क</p> <p>अनुसूची - VI : ट्राली किराया प्रभार</p> <p>पूर्वोक्त दरों को प्राधिकरण ने प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए अनुमोदित किया था।</p> <p>वर्तमान प्रस्ताव में, तूना पत्तन के कच्चे भूखंड के भंडारण प्रभार दरों का प्रस्ताव करते समय केवल दरों के निर्धारण के लिए, तूना पत्तन क्षेत्र के लिए मूल्यांक द्वारा दिये गए नवीनतम मूल्यांकन और एलएसी के अनुमोदन पर विश्वास किया था। फिर भी, वह प्रशुल्क दिशानिर्देश 2015 के सिद्धांतों के अनुसार दरमानों के सामान्य संशोधन में कार्गो संबंधी प्रभार ऋवर होते हैं इसलिए प्रस्ताव किया गया है। अतः तूना पत्तन के कच्चे भू-खंड के लिए भंडारण प्रभारों के प्रस्ताव में संशोधित एलपीजी, 2014 के उपबंधों का सहयोजन नहीं है और इसलिए संशोधित एलपीजी 2014 के उपबंधों का अनुपालन अपेक्षित नहीं है।</p> <p>यह बताया जाता है कि तूना पत्तन के कच्चे भू-खंड की भंडारण प्रभार दरों के संशोधन का प्रस्ताव अर्थात् भंडारण स्थल को कार्गो भंडारण के लिए आवरित किया जाएगा और प्रभारों की उगाही कार्गो के ठहराव के आधार पर की जाएगी। इसलिए इस स्थान का एलपीजी 2014 के अनुसार किराये तथा लाइसेंस आधार पर भूमि का आबंटन नहीं किया जाता है। अतः तूना स्थित कच्चे भू-खंड के लिए प्रस्तावित भंडारण प्रभार दरें एलपीजी 2014 के अंतर्गत नहीं आतीं जबकि ये प्रशुल्क दिशानिर्देश 2015 के सिद्धांतों के अनुरूप दरमानों के सामान्य संशोधन के अंतर्गत आती हैं। इसलिए इन्हें अलग नहीं किया जा सकता।</p>
<p>(ii). डीपीटी तूना पत्तन के किरायों के संशोधन के प्रस्ताव को तूना पत्तन के दरमानों के सामान्य संशोधन से डिलिंक करने पर सुविचार करके इस संबंध में अलग से एक प्रस्ताव प्रस्तुत करे। वास्तव में, विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) ने प्रशुल्क</p>	

	दिशानिर्देश 2005 के अंतर्गत पहले सामान्य दरमानों का एक भाग के रूप में पोत परिवहन मंत्रालय का एक भाग के रूप में लाइसेंस शुल्क (भंडारण प्रभार) को पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एलपीजी 2014 जारी करने के बाद एलपीजी 2014 का अनुपालन करते हुए सामान्य दरमानों से डीलिक करने का प्रस्ताव दायर किया था। तदनुसार प्राधिकरण ने इस बारे में वीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर एलपीजी 2014 के अंतर्गत 15 जनवरी 2016 को आदेश संख्या टीएमपी/48/2018-वीपीटी अनुमोदित किया।	
(iii).	उक्त बिंदुओं के आलोक में, डीपीटी से अपना स्पष्टीकरण देने और हर हाल में 06 अप्रैल, 2018 तक प्रत्युत्तर देने का अनुरोध किया गया।	अतः प्राधिकरण से एक बार फिर से अनुरोध है कि एमपीटी अधिनियम 1963 की धारा 48, 49 व 50 के अनुसार इस कार्यालय के 13 मार्च, 2018 के पत्र संख्या एफए/सीओएसटी/92 के द्वारा दायर अनुलग्नक-घ पर रखे प्रस्ताव को अनुमोदित करने का कष्ट करें।

6. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, डीपीटी के 13 मार्च, 2018 के प्रस्ताव की एक प्रति हमारे 18 अप्रैल, 2018 के पत्र के द्वारा डीपीटी द्वारा अपने 20 मार्च, 2018 के ई-मेल में दिये गए सुझावानुसार, संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। हमने सिवाए 7 मई, 2018 के ई-मेल द्वारा एकेबीटीपीएल की टिप्पणियों के अन्य किसी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। एकेबीटीपीएल से प्राप्त टिप्पणियां फीड बैक सूचना के तौर पर, डीपीटी को भेज दी गई थीं। डीपीटी ने अदानी कांडला बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड की टिप्पणियों पर 21 मई, 2018 के ई-मेल से प्रत्युत्तर दिया।

7. डीपीटी ने एकेबीटीपीएल की टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां देते समय 21 दिसंबर, 2016 के पत्र संख्या टीएमपी/42/2009-केपीटी का हवाला दिया जिसके द्वारा एकेबीटीपीएल के 16 अगस्त, 2016 का अभ्यावेदन भेजा गया था और कहा कि प्राधिकरण ने डीपीटी को तूना भूमि के पट्टा किराये के संशोधन का प्रस्ताव दायर करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्यात्मक स्थिति संदर्भ हेतु प्रस्तुत है:-

(i). एकेबीटीपीएल ने अपने 16 अगस्त 2016 के पत्र में भूमि के लाइसेंस शुल्क पर विभेदी राशि के भुगतान के बारे में अभ्यावेदन दिया था। एकेबीटीपीएल के मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं:-

एकेबीटीपीएल रियायत करार के भाग 9.1 की ओर ध्यानाकर्षित करते हुए बताया था कि जबकि रियायत की पूरी अवधि के लिए जलाग्र क्षेत्र का लाइसेंस शुल्क 8 करोड़ रु. स्थिर है, भूमि के लाइसेंस शुल्क का परिकलन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रचलित दरमानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

इस परियोजना के लिए अधिसूचित भूमि के लिए शुल्क अध्याय V, अनुसूची V – खुले स्थान के लिए क्रमांक 1 पर किराया शुल्क था। अब, नए दरमान के अनुसार, उक्त मद अब प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है, और न ही डीपीटी के नए दरमानों में कोई सम्मेल्य मद उपलब्ध है। यहां तक कि, अन्यथा भी, हस्ताक्षरित रियायत करार को देखते हुए कांडला भूमि के डीपीटी के दरमान तूना शुल्क बल्क टर्मिनल पर लागू नहीं होते। इस विचार को 2 नवंबर, 2010 की प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या 285 के खंड 11 (viii) (ग) में स्पष्ट किया गया है, जिसे तुरंत संदर्भ के लिए नीचे पुनर्उद्धृत किया जा रहा है:-

“(ग) कांडला पोर्ट ट्रस्ट के विद्यमान एसओआर (180 दिनों से अधिक समय तक अधिभोग के संबंध में 105 रु. प्रति वर्ग मीटर) में विहित सामान्य नौभार संबंधी भंडारण प्रभार को दर के आधार पर कांडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा 902600 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्र संबंधी अनुज्ञाप्ति शुल्क रु. 10.50 प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह प्राक्कलित किया गया है। मार्गदर्शिकाओं में यह अपेक्षित है कि भूमि संबंधी

अनुज्ञप्ति शुल्क पत्तन न्यासों के दरों के मान के अनुसार परिकलित किया जाए। यह बताना अनावश्यक है कि सुसंगत भूमि के लिए यथा अनुज्ञेय दरों का ध्यान रखा जाए। पोर्ट का वर्तमान प्रस्ताव तूना के निकट टेकरा के पास शुष्क थोक टर्मिनल जो कांडला की खाड़ी के पश्चिमी मुहाने पर 17 किलो मीटर का होगा, उस पर लागू होने वाले अद्यतन टैरिक नियत करने से संबंधित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट की वर्तमान दरों के मान में अध्याय V के अधीन तूना के लिए पृथक दरें विहित की गई हैं। अनुसूची V के क्रमांक (i) खुले स्थल के लिए रु. 7.50 प्रति 10 वर्ग मीटर प्रतिमाह विनिर्दिष्ट करता है। कांडला भूमि के लिए निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क अपनाते हुए कांडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्राकलित अनुज्ञप्ति शुल्क परिकलित किया गया है जिसे तूना के दरमान में विहित विनिर्दिष्ट दर के संदर्भ में तदनुसार आशोधित किया जाता है।"

उपरोक्त के अतिरिक्त, लाइसेंस शुल्क को 81 लाख रु. प्रति वर्ष स्थिर रखा गया है और इस प्रकार इसे रियायत करार के अनुसार स्थिर जलाग्र प्रभागों के समान 30 वर्ष की पूरी रियायत अवधि के दौरान बढ़ाया नहीं जा सकता।

- (ii). इसे पश्चात् एकेबीटीपीएल ने 27 सितंबर, 2017 को अनुस्मारक दिया।
- (iii). उक्त के प्रत्युत्तर में प्राधिकरण ने अपने 21 सितंबर, 2016 और 10 अक्टूबर, 2016 के पत्रों के द्वारा एकेबीटीपीएल के क्रमशः 16 अगस्त, 1961 और 27 सितंबर, 2017 के पत्रों की प्रतियां यह कहते हुए डीपीटी को भेजी कि एकेबीटीपीएल से प्राप्त अभ्यावेदन तूना पत्तन की दरों से संबंधित मौजूदा दरमानों का अध्याय-V को डीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित विलुप्त करने से उठा है। अतः डीपीटी को ग्राह्य दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए तूना पत्तन स्थित भूमि के किरायों का उपयुक्त प्रस्ताव दायर करने का अनुरोध किया गया था।

8. इस मामले में संयुक्त सुनवाई डीपीटी परिसर में 11 जून, 2018 को आयोजित हुई। डीपीटी ने अपने प्रस्ताव का पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया। संयुक्त सुनवाई में डीपीटी और संबंधित प्रायोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों ने अपने-अपने निवेदन रखे।

9. जैसा संयुक्त सुनवाई में स्वीकार किया गया, एकेबीटीपीएल ने 15 जून, 2018 के अपने पत्र के द्वारा आगे और लिखित निवेदन रखे। एकेबीटीपीएल से प्राप्त लिखित निवेदनों को फीड बैक सूचना के तौर पर हमारे 22 जून, 2018 के पत्र के द्वारा अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया। इसके बाद 28 जून, 2018 और 13 जुलाई, 2018 को अनुस्मारक भेजे गए। डीपीटी ने 21 जुलाई, 2018 को प्रत्युत्तर दिया।

10. 13 मार्च, 2018 के प्रस्ताव की आरंभिक संवीक्षा के आधार पर डीपीटी को हमारे 28 जून, 2018 के पत्र के द्वारा कुछेक मुद्दों पर सूचना/स्पष्टीकरण, भेजने का अनुरोध किया गया। इसके बाद 13 जुलाई, 2018 को एक अनुस्मारक भेजा गया। डीपीटी ने 21 जुलाई, 2018 और तत्पश्चात् 18 अक्टूबर तथा 19 नवंबर, 2018 तथा 20 नवंबर, 2018 के ई-मेलों द्वारा हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण का उत्तर दिया। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण और डीपीटी का उत्तर नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:-

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	डीपीटी का उत्तर
I.	<b>सामान्य:</b>	
(i).	यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि 20 जनवरी, 2016 के एलएसी के कार्यवृत्त के पहले पैरा में यह दर्ज है कि एलएसी संस्तुति करती है कि पट्टा भूमि और फ्रीहोल्ड भूमि के बीच अंतर को देखते हुए मूल्यांकन 2012 (रिपोर्ट 2013 में प्रस्तुत) को समीक्षा के लिए मूल्यांकन को लौटा दी जाए। तदनुसार, इस मामले को डीपीटी द्वारा, डीपीटी के	19.01.2016 की संशोधित रिपोर्ट शीघ्र ही भेज दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, एलएसी द्वारा सुविचारित भू-मूल्यांकन मूल्यांकक की 19.01.2016 की संशोधित मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें 2012 की संशोधित दरों और वृद्धि के साथ 2016 के लिए दरें निकाली गई हैं।

	<p>28 दिसंबर, 2015 के पत्र के द्वारा, मूल्यांकक को भेजा गया। एलएसी के कार्यवृत्त बताते हैं कि, मूल्यांकक ने संशोधित मूल्यांकन रिपोर्ट 19 जनवरी, 2016 को प्रस्तुत की। 2016 मूल्यांकन रिपोर्ट का आगे कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त, एलएसी के कार्यवृत्त से यह देखा जाता है कि वर्ष 2012 में किये गए मूल्यांकन (रिपोर्ट 2013 में प्रस्तुत) पर एलएसी ने सुविचार किया। डीपीटी द्वारा 2012 मूल्यांकन रिपोर्ट ही प्रस्तुत की है। डीपीटी ने 19 जनवरी, 2016 की संशोधित मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत नहीं की है।</p> <p>डीपीटी मूल्यांकन रिपोर्ट 2016 की प्रति भेजे। डीपीटी यह भी पुष्टि करें कि क्या डीपीटी द्वारा नियुक्त एलएसी द्वारा सुविचारित भू-मूल्यांकन 2012 मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है या 2016 की मूल्यांकन पर एलएसी की रिपोर्ट में 2012 का संदर्भ दिया गया है। यदि 2012 की मूल्यांकन रिपोर्ट पर सुविचार किया गया है तो डीपीटी वर्ष 2018 में दर निकालने के लिए भू-मूल्यांकन रिपोर्ट 2012 की प्रासंगिकता का परीक्षण करें।</p>	<p>[बाद में, डीपीटी ने अपने 18 अक्टूबर, 2018 के पत्र के द्वारा 19 जनवरी, 2018 के पत्र के द्वारा 19 जनवरी 2016 की संशोधित मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति भेज दी है।]</p> <p>जैसा वांछा की गई है, 19 जनवरी, 2016 की संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत है। अतः प्राधिकरण से एक बार फिर से अनुरोध है कि एमपीटी अधिनियम 1963 की धारा 48, 49 व 50 के अनुसार इस कार्यालय के 13 मार्च, 2018 के पत्र संख्या एफए/सीओएसटी/92 के द्वारा दायर अनुलग्नक घ पर रखे प्रस्ताव को अनुमोदित करने का कष्ट करें।</p>
(ii).	<p>डीपीटी ने 20 जनवरी, 2016 को आयोजित हुई एलएसी की बैठक के कार्यवृत्त के अनुलग्नक—IV की प्रति नहीं भेजी है। इसके अतिरिक्त, डीपीटी ने एलएसी के कार्यवृत्त में उल्लिखित अनुलग्नक I से III भी प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये हैं। डीपीटी एलएसी की 20 जनवरी, 2016 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुलग्नक I से IV के प्रत्येक की प्रति प्रस्तुत करें।</p>	<p>एलएसी की 20.01.2016 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त के निम्न अनुलग्नक I - IV की प्रतियां संलग्न की जाती है।</p> <p>अनुलग्नक -I: तूना, भारपर और किदना गांवों के लिए गुजरात सरकार के रेडि-रैक्नर में उल्लिखित दरें।</p> <p>अनुलग्नक -II: किदना गांव में सरकार द्वारा बेची गई भूमि की उच्चतम दर।</p> <p>अनुलग्नक -III: सभी चारों श्रेणियों के लिए मूल्यांकक द्वारा अपनायी गई कार्यप्रणाली अपनाते हुए बाजार मूल्य और पट्टा किराया।</p> <p>अनुलग्नक -IV: 01.01.2012 के संशोधित भू-नीति दिशानिर्देश 2014 के 13 (ग) में उल्लिखित विभिन्न कारकों के अनुसार बाजार मूल्य और पट्टा किराया दर्शाने वाला विवरण</p>
II	<b>तूना पत्तन के लिए प्रस्तावित किराया शुल्क</b>	
(i).	<p>डीपीटी का प्रस्ताव बताता है कि कच्चे भू-खंड के लिए प्रस्तावित दर डीपीटी द्वारा तूना पत्तन के दरों की समीक्षा के लिए नियुक्त की गई समिति की संस्तुति और डीपीटी के बोर्ड के अनुमोदन पर आधारित है। न तो समिति की रिपोर्ट में, न ही एलएसी की रिपोर्ट में न ही एलएसी की रिपोर्ट में और न ही बोर्ड अनुमोदन के कार्यवृत्त में कच्चा प्लॉट के लिए 84.03 रु. वर्ग/मीटर/वर्ष का उल्लेख है। डीपीटी ने समिति/ एलएसी की संस्तुति का स्पष्टतया हवाला देते हुए कच्चे भू-खंड के लिए</p>	<p>एलएसी की 20.01.2016 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार पृष्ठ 5 पर अंतिम पैरा पुनरुद्धर्त किया जाता है:</p> <p>“उक्त सभी पर सुविचार करते हुए, एलएसी ने विस्तार से चर्चा और विचार-विमर्श करके समिति मूल्यांकन रिपोर्ट में मूल्यांकक द्वारा उल्लिखित उच्चतम दर जैसी ऊपर पृष्ठ 3 में (ii) पर दर्शायी गई है, पर सुविचार करने अर्थात् वर्ष 2012 में निकटवर्ती किदना गांव में सरकार द्वारा विक्री का वास्तविक लेनदेन, तूना भूमि, केवल भूमि के लिए, के लिए, जहां है जैसी है, आधार पर, दर निकालने की संस्तुति करती है, जो नीचे दी जा रही है:-</p>

84.03 रु./वर्ग मीटर/ वर्ष की दर बतायी है और उसके लिए बोर्ड के अनुमोदन का भी हवाला दिया है।

क्र.सं.	विवरण	सीआरजैड जोन	किस प्रयोजन के लिए उपयुक्त	विकसित/ अविकसित	उच्च ज्वार/ कीक क्षेत्र	मूल्यांकन	पट्टा के भूमि के लिए (-) घटाएं (25%)	अंतिम मूल्यांकन के @ 6% पर पट्टा किराया राशि (रु.) प्रति वर्ग मीटर
1	*	सीआर जैड-III	नमक उत्पादन, सीएफएस, टैंक फार्म उद्योग, भंडागार	अविकसित, परंतु 10 कि.मी. सड़क से पहुंच	खुली अविकसित भूमि	2645	1983.75	119.03
2	**	सीआर जैड-III	भांडागारों नमक उत्पादन, सीएफजैड, टैंक फार्म के लिए उपयुक्त	अविकसित	खुली भूमि	2300	1725.00	103.50
3	***	सीआर जैड-II	भांडागारों सीएफजैड, टैंक फार्म के लिए उपयुक्त	अविकसित	उच्च बार क्षेत्र	1955	1466.25	87.98
4	****	सीआर जैड-I	जेटी संभरण प्रचालन और सीएफजैड के लिए उपयुक्त	अविकसित	उच्च बार क्षेत्र	1725	1293.75	77.63

- \* तूना में बार्ज प्रहस्तन जेटी को जाने वाली पहुंच सड़क के पूर्व की ओर पड़ने वाली भूमि (एचएच 8 क से तूना तक 10 कि.मी. लंबी)
- \*\* संकरी खाड़ी के किनारे से आधा किलो मीटर दूर की भूमि
- \*\*\* बार्ज प्रहस्तन जेटी की संकरी खाड़ी से आधे किलो मीटर के भीतर भूमि जिसका कोई जलाग्र क्षेत्र नहीं।
- \*\*\*\* जलाग्र वाली भूमि और बार्ज प्रहस्तन जेटी से आधे किलो मीटर तक अर्थात् उत्तर की ओर

मैसर्ज एकेबीटीपीएल को आवरित प्रस्तावित भूमि श्रेणी 4 के अंतर्गत आती है यानी जलाग्र वाली भूमि और बार्ज प्रहस्तन जेटी से आधे किलो मीटर तक

		<p>अर्थात् उत्तर की ओर और इसका पट्टा किराया 2012 में 77.63 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष था तथा 2% वार्षिक वृद्धि को सुविचार में लेते हुए वर्ष 2016 के लिए दर 84.3 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष निकलती है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, 27.01.2016 को आयोजित हुई समिति की बैठक के कार्यवृत्त के पृष्ठ 2 के पैरा 2 के अनुसार, यह संस्तुति दी गई है कि “कच्चे भू-खंड के लिए दर तूना पत्तन क्षेत्र में मूल्यांकक द्वारा दिये गए नवीनतम मूल्यांकन और एलएसी के अनुमोदन के अनुसार होगी।”</p> <p>यह भी कि डीपीटी के न्यासी मंडल ने 26.12.2017 को आयोजित हुई बैठक के संकल्प संख्या 109 ने प्रस्ताव को अनुमोदित करने का संकल्प किया।</p> <p>(i). “तूना पत्तन के लिए अलग से प्रशुल्क दर को डीपीटी के दरमानों में अनुसूची V के रूप में जोड़ने के लिए (अनुलग्नक 60 पर रखी है) और एमपीटी अधिनियम 1964 की धारा 48, 49 और 50 के अंतर्गत महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना;...”</p> <p><b>ड. अनुसूची V- किराया शुल्क</b></p> <p>1. खुले स्थान के लिए</p> <table border="1"> <tr> <td>(i) कच्चा भूखंड</td><td>10 प्रति वर्ग मीटर या उसका एक भाग प्रति माह या उसका एक भाग (रु. में)</td><td>84.03 रु.*</td></tr> </table> <p>इस प्रकार, उपरोक्त से यह अर्थ लगाया जा सकता है कि 84.03 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर एलएसी की 20.1.2016 को हुई बैठक में संस्तुत तथा समिति द्वारा 27.11.2016 को हुई बैठक में संस्तुत और 26.12.2017 को हुई बोर्ड की बैठक केवीआर संख्या 109 द्वारा अनुमोदित है।</p> <p>[* डीपीटी द्वारा प्रस्तुत परिकलन के अनुसार दर 84.03 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है न कि 84.03 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति माह या उसका एक भाग।]</p>	(i) कच्चा भूखंड	10 प्रति वर्ग मीटर या उसका एक भाग प्रति माह या उसका एक भाग (रु. में)	84.03 रु.*
(i) कच्चा भूखंड	10 प्रति वर्ग मीटर या उसका एक भाग प्रति माह या उसका एक भाग (रु. में)	84.03 रु.*			
(ii).	ऊपर (i) के अतिरिक्त प्रस्ताव में दी गई निम्नलिखित दरें मेल नहीं खाती हैं अथवा सही नहीं की जा सकती।				
(क).	2011 दरमानों के अनुसार दरमानों के संशोधन से पूर्व 13 मार्च, 2018 के प्रस्ताव के पैरा 13 के अंतर्गत सारणी में दी गई लाइसेंस शुल्क की 4.00 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर 18.01.2011 के आदेश संख्या टीएएमपी/61/2009-केपीटी में अनुमोदित दर से मेल नहीं खाती। 2011 के आदेश में निर्धारित दर तूना स्थित कच्चे भू-खंड के लिए 7.50 रु. वर्ग मीटर प्रति वर्ष है।	<p>तूना स्थित कच्चे भू-खंड की दर 18.01.2011 के आदेश संख्या टीएएमपी/61/2009-केपीटी के अनुसार 2011 में अनुमोदित दर 7.50 रु. प्रति 10 मीटर या उसके एक भाग प्रति भाग या उसके एक भाग पर है न कि 7.50 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर अथवा उसके एक भाग प्रति वर्ष या उसके एक भाग के लिए।”</p> <p>इसके अतिरिक्त, जहां तक 2011 दरमान के अनुसार दरमान संशोधन से पूर्व लाइसेंस शुल्क की दर 13.03.2018 के प्रस्ताव के पैरा 13 के अंतर्गत 2011 के आदेश में 7.50 रु. प्रति 10 मीटर या उसका एक भाग प्रति माह या उसके एक भाग की अनुमोदित दर को सुविचार में लेते हुए “9 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष” की यह दर वार्षिक आधार पर निकाली गई है।</p> <p>(7.50/10x 12 माह = 9.00 p.a.)</p>			

(ख).	13 मार्च, 2018 के प्रस्ताव के पैरा 13 की सारणी में दर्शाए गए 2016 दरमान के अनुसार तूना पत्तन स्थित कच्चे भूखंड के लिए “302.40 रु. प्रति वर्ग मीटर वर्ष” की लाइसेंस शुल्क की दर 21.06.2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2016-केपीटी में अनुमोदित दर से मेल नहीं खाती। 2016 आदेश में अनुमोदित कच्चे भूखंड की दर स्लैब वार है और उगाही का आधार 10 वर्ग मीटर प्रति वर्ष था। कृपया संलग्न अनुलग्नक देखें।	13 मार्च, 2018 के प्रस्ताव के पैरा 13 की सारणी में दर्शाये गए 2016 दरमान के अनुसार तूना पत्तन स्थित कच्चे भूखंड के लिए “302.40 रु. प्रति वर्ग मीटर वर्ष” की लाइसेंस शुल्क की दर भी अनुसूची 2.5 लाइसेंस सामान्य कार्गो पर भंडारण शुल्क (क) से वार्षिक आधार पर निकाली गई थी। 180 दिन से अधिक की अवधि के लिए खुले स्थान के लिए “252.00 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर या उसके एक भाग के लिए प्रति माह या उसके एक भाग के लिए” अर्थात् “252/10x12 माह = 302.40 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष” है।																																															
(ग).	13 मार्च 2018 के प्रस्ताव के पैरा 13 के अंतर्गत उक्त सारणी में 84.03 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की प्रस्तावित दर न तो एलएसी की सिफारिश मिलती है और न ही दरमान में प्रस्तावित दर से/ इसके अतिरिक्त, पैरा 13 की सारणी में 84.03 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष का प्रस्ताव है जबकि प्रारूप दरमान में 84.03 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति दिन है। डीपीटी से परीक्षण का अनुरोध किया जाता है और सही स्थिति के अनुरूप आवश्यक संशोधन करे।	कृपया पैरा II (i) ऊपर में प्रस्तुत स्पष्टीकरण देखें। इसके अतिरिक्त, पैरा 13 की सारणी में “84.03 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष” की प्रस्तावित दर पर सुविचार किया जाए। तदनुसार आशोधित प्रारूप दरमान प्रस्तुत है।																																															
(iii).	<p>डीपीटी ने बताया है कि पक्के भूखंड के लिए, डीपीटी के वर्तमान दरमान में निर्धारित किराया का प्रस्ताव किया जाता है। डीपीटी के मौजूदा दरमान में पक्का प्लांट में सामान्य कार्गो के लिए लाइसेंस (भंडारण) शुल्क स्लैब-वार निर्धारित है। इसी प्रकार, स्लैब वार लाइसेंस (भंडारण) शुल्क कवर्ड स्थान के साथ-साथ खुले स्थान के लिए भी निर्धारित है, जैसा नीचे दिया गया है:-</p> <p><b>2.5. सामान्य कार्गो पर लाइसेंस (भंडारण) शुल्क</b></p> <p><b>(क). खुले स्थान के लिए:</b></p> <table><tr><td>अधिवास की अवधि</td><td>दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका एक भाग प्रति माह या उसका एक भाग</td></tr><tr><td></td><td>पक्का भूखंड (सीमेंट डालकर) (रु. में)</td></tr><tr><td>0 – 60 दिन</td><td>144.00</td></tr><tr><td>61 – 90 दिन</td><td>288.00</td></tr><tr><td>91 – 180 दिन</td><td>360.00</td></tr><tr><td>180 दिन से अधिक</td><td>432.00</td></tr></table> <p><b>(ख). कवर्ड स्थान के लिए</b></p>	अधिवास की अवधि	दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका एक भाग प्रति माह या उसका एक भाग		पक्का भूखंड (सीमेंट डालकर) (रु. में)	0 – 60 दिन	144.00	61 – 90 दिन	288.00	91 – 180 दिन	360.00	180 दिन से अधिक	432.00	<p>प्रस्तावित प्रारूप दरमान में खुले स्थान और कवर्ड स्थान दोनों के लिए पक्के भूखंड पर सामान्य कार्गो के लिए स्लैब-वार लाइसेंस (भंडारण) शुल्क अंतर्विष्ट करते हुए आवश्यक सुधार कर दिया गया है। डीपीटी द्वारा प्रारूपदरमानों में प्रस्तावित स्लैब-वार दर इस प्रकार है:-</p> <p style="text-align: right;">(in ₹)</p> <table><tr><th rowspan="2">अनुसूची V किराया शुल्क</th><th colspan="2">दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका एक भाग प्रति माह या उसका एक भाग</th></tr><tr><th>कच्चा भूखंड</th><th>पक्का भूखंड</th></tr><tr><td colspan="3"><b>खुले स्थान के लिए</b></td></tr><tr><td>0 – 60 दिन</td><td>23.34</td><td>144.00</td></tr><tr><td>61 – 90 दिन</td><td>6.68</td><td>288.00</td></tr><tr><td>91 – 180 दिन</td><td>58.35</td><td>360.00</td></tr><tr><td>180 दिन से अधिक</td><td>70.03</td><td>432.00</td></tr><tr><td colspan="3"><b>कवर्ड स्थान के लिए</b></td></tr><tr><td>0 – 60 दिन</td><td colspan="2">279.00</td></tr><tr><td>61 – 90 दिन</td><td colspan="2">558.00</td></tr><tr><td>91 – 180 दिन</td><td colspan="2">697.50</td></tr><tr><td>180 दिन से अधिक</td><td colspan="2">837.00</td></tr></table>	अनुसूची V किराया शुल्क	दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका एक भाग प्रति माह या उसका एक भाग		कच्चा भूखंड	पक्का भूखंड	<b>खुले स्थान के लिए</b>			0 – 60 दिन	23.34	144.00	61 – 90 दिन	6.68	288.00	91 – 180 दिन	58.35	360.00	180 दिन से अधिक	70.03	432.00	<b>कवर्ड स्थान के लिए</b>			0 – 60 दिन	279.00		61 – 90 दिन	558.00		91 – 180 दिन	697.50		180 दिन से अधिक	837.00	
अधिवास की अवधि	दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका एक भाग प्रति माह या उसका एक भाग																																																
	पक्का भूखंड (सीमेंट डालकर) (रु. में)																																																
0 – 60 दिन	144.00																																																
61 – 90 दिन	288.00																																																
91 – 180 दिन	360.00																																																
180 दिन से अधिक	432.00																																																
अनुसूची V किराया शुल्क	दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका एक भाग प्रति माह या उसका एक भाग																																																
	कच्चा भूखंड	पक्का भूखंड																																															
<b>खुले स्थान के लिए</b>																																																	
0 – 60 दिन	23.34	144.00																																															
61 – 90 दिन	6.68	288.00																																															
91 – 180 दिन	58.35	360.00																																															
180 दिन से अधिक	70.03	432.00																																															
<b>कवर्ड स्थान के लिए</b>																																																	
0 – 60 दिन	279.00																																																
61 – 90 दिन	558.00																																																
91 – 180 दिन	697.50																																																
180 दिन से अधिक	837.00																																																

	<table><tr><td>अधिवास की अवधि</td><td>दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका एक भाग प्रति माह या उसका एक भाग (रु. में)</td></tr><tr><td>0 – 60 दिन</td><td>279.00</td></tr><tr><td>61 – 90 दिन</td><td>558.00</td></tr><tr><td>91- 180 दिन</td><td>697.50</td></tr><tr><td>180 दिन से अधिक</td><td>837.00</td></tr></table>	अधिवास की अवधि	दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका एक भाग प्रति माह या उसका एक भाग (रु. में)	0 – 60 दिन	279.00	61 – 90 दिन	558.00	91- 180 दिन	697.50	180 दिन से अधिक	837.00	<p>बाद में, डीपीटी 19 नवंबर, 2018 के अपने ई-मेल के द्वारा 2011 आदेश के अनुसार तूना पत्तन के लिए लागू लाइसेंस (भंडारण) शुल्क की दर की और डीपीटी द्वारा तूना पत्तन के लिए अब प्रस्तावित दर तुलनात्मक प्रस्तुत की।</p> <p>इसके अतिरिक्त, डीपीटी ने अपने 20 नवंबर, 2018 के ई-मेल के द्वारा उक्त प्रस्तावित दर निकालने का आधार प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है:</p> <p>कच्चे भूखंड के लिए 84.03 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष दर एलएसी द्वारा यथा संस्तुत तथा डीपीटी के न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित, को परिवर्तित करके 70.03 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति माह कर दिया गया है ताकि इसे कार्गो के भंडारण के लिए मौजूदा यूनिट दर के समान लाया जाए अर्थात् लाइसेंस शुल्क यानी 84.03 रु. X 10/12= 70.03 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति माह।</p> <p>[डीपीटी द्वारा 70.03 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति माह की दर 180 दिन से अधिक अवधि के अंतिम स्लैब के लिए प्रस्तावित की गई है।]</p> <p>कच्चे भूखंडों के लिए ठहराव अवधि के विभिन्न खंडों के लिए उसी तर्ज पर जैसी कांडला दरों के लिए है, स्लैब दरें प्रस्तावित की हैं यानी</p> <p>( रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति माह या उसके एक भाग पर)</p> <table><tr><th>अधिवास की अवधि</th><th>कांडला दर</th><th>प्रस्तावित तूना दर</th></tr><tr><td>0 – 60 दिन</td><td>84.00</td><td>23.34</td></tr><tr><td>61 – 90 दिन</td><td>168.00</td><td>46.68</td></tr><tr><td>91 – 180 दिन</td><td>210.00</td><td>58.35</td></tr><tr><td>180 दिन से अधिक</td><td>252.00</td><td>70.03</td></tr></table>	अधिवास की अवधि	कांडला दर	प्रस्तावित तूना दर	0 – 60 दिन	84.00	23.34	61 – 90 दिन	168.00	46.68	91 – 180 दिन	210.00	58.35	180 दिन से अधिक	252.00	70.03
अधिवास की अवधि	दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका एक भाग प्रति माह या उसका एक भाग (रु. में)																										
0 – 60 दिन	279.00																										
61 – 90 दिन	558.00																										
91- 180 दिन	697.50																										
180 दिन से अधिक	837.00																										
अधिवास की अवधि	कांडला दर	प्रस्तावित तूना दर																									
0 – 60 दिन	84.00	23.34																									
61 – 90 दिन	168.00	46.68																									
91 – 180 दिन	210.00	58.35																									
180 दिन से अधिक	252.00	70.03																									
(iv).	डीपीटी वर्तमान दरमानों में निर्धारित शब्दावली कार्गो के भंडारण के लिए सामान्य कार्गो पर लाइसेंस (भंडारण) शुल्क है। इसलिए डीपीटी तूना पत्तन के लिए अध्याय – V में निर्धारित शब्दावली को “किराया शुल्क” से “लाइसेंस (भंडारण) शुल्क” करने पर सुविचार करे ताकि यह डीपीटी दरमानों के मौजूदा निर्धारण के अनुरूप हो जाए।	तूना पत्तन के लिए अध्याय—V में निर्धारित शब्दावली को डीपीटी दरमानों में निर्धारित के अनुरूप आशोधित कर दिया गया है।																									
III.	<b>दरमान:</b>																										
(i).	इस प्राधिकरण द्वारा 2011 के आदेश में अनुमोदित दरमानों में तूना पत्तन के लिए दरें निर्धारित करते हुए अलग से अध्याय V रखा था। इसमें निर्धारित प्रशुल्क को शासित करने वाली कुछ सोपाधिकताएं भी थीं। तूना पत्तन के लिए अलग से दर का प्रस्तावित अध्याय V में पत्तन ने उनमें से किसी भी सोपाधिकता का प्रस्ताव नहीं किया है। डीपीटी से अनुरोध है कि वह परीक्षण करे और 2011 के आदेश में तूना पत्तन के लिए अलग से प्रशुल्क की उगाही को शासित करने वाली उन सोपाधिकताओं का प्रस्ताव न करने के कारण बताएं।	<p>तूना पत्तन के लिए अलग दर के प्रस्तावित अध्याय – V को तूना पत्तन के लिए अलग से प्रशुल्क की उगाही को शासित करने वाली उन सोपाधिकताओं को अंतर्विष्ट करते हुए आशोधित कर दिया गया है।</p> <p>[डीपीटी द्वारा अंतर्विष्ट करने के लिए प्रस्तावित तूना पत्तन की सोपाधिकताओं पर आगामी पैराओं में चर्चा की जाएगी।]</p>																									



(क).	दिनांक 18.01.2011 के आदेश संख्या टीएमपी/61/2009-केपीटी में तूना पत्तन के लिए अनुमोदित दरें, 21 जून, 2016 के आदेश संख्या टीएमपी/81/2016-केपीटी के द्वारा पिछले संशोधित दरमानों के अनुसार दरें और डीपीटी द्वारा अब प्रस्तावित दरों की तुलना देते हुए एक विवरण तथा 2011 की दर में और अब प्रस्तावित दरों में प्रतिशत वृद्धि सहित तुलनात्मक दर हमारे द्वारा की गई है जो संलग्न अनुलग्नक में दी गई है। डीपीटी इसे देख ले और पुष्टि करे कि यह सही है।	यह पुष्टि की जाती है कि संलग्न अनुलग्नक सही है।
(ख).	पोत संबंधी प्रभारों (पत्तन देयताएं, बर्थ किराया और बीचिंग प्रभार) और कार्गो संबंधी प्रभारों (पशुधन और पशु उत्पादों पर घाट शुल्क) के लिए कांडला की तुलना में प्रस्तावित घटी दरों के कारण बताया जाए।	पोत संबंधी प्रभारों (पत्तन देयताएं, बर्थ किराया और बीचिंग प्रभार) और कार्गो संबंधी प्रभारों (पशुधन और पशु उत्पादों पर घाट शुल्क) के लिए कांडला की तुलना में प्रस्तावित घटी दरों के कारण 13.3.2018 के प्रस्ताव के पैरा 7.7 से 11 में पहले ही दे दिए गए हैं [पैरा 2.2 (ii) में पहले चर्चा हो चुकी है।]
(ii).	संयुक्त सुनवाई में डीपीटी ने बताया है कि तूना पत्तन की प्रस्तावित दरों पर कार्गो संबंधी और पोत संबंधी प्रभारों से 129.83 लाख रु. के अतिरिक्त राजस्व होने का अनुमान है। डीपीटी बताए कि 2016 के पिछले दरमान का संशोधन करते समय तूना पत्तन का क्या राजस्व आकलित किया गया था। यूनिट दर, यातायात 2016 आदेश के दौरान आकलित आय और अब प्रस्तावित दर पर प्रत्येक प्रशुल्क मद से आकलित आय बताये हुए 126.33 लाख रु. की अतिरिक्त आय की गणना प्रस्तुत करे। डीपीटी से अनुरोध है कि वह यह पुष्टि करे कि विषयक प्रस्ताव से अतिरिक्त वार्षिक राजस्व पिछले प्रशुल्क आदेश में रह गए 700.26 लाख के विभेदी एआरआर के भीतर ही है और यह भी पुष्टि करे कि प्रत्याशित कुल राजस्व 84,251.84 लाख रु. के कुल आकलित एआरआर के भीतर ही है।	तूना पत्तन को लागू धटी दरों का वित्तीय प्रभाव लगभग 126.53 लाख रु. है और इसे 13.03.2018 के प्रस्ताव के पैरा 14 में दर्शाया गया है, अतः तूना पत्तन की प्रस्तावित दरों पर 129.63 लाख रु. पर कोई अतिरिक्त राजस्व नहीं है। 2016 के दरमानों के पिछले संशोधन में तूना पत्तन से आकलित में तूना पत्तन से आकलित राजस्व 253.34 लाख रु. था। 2011 दरमानों के अनुसार 2016 दरमानों के अनुसार और यथाप्रस्तावित दरमानों का विवरण प्रस्तुत है।  इसलिए, प्राधिकरण को एक बार फिर से यह अनुरोध किया जाता है कि अनुलग्नक-1 के रूप में रखे तूना पत्तन के प्रस्तावित आशोधित दरमानों को एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 48, 49 और 50 के अंतर्गत अनुमोदित करने का कष्ट करें।

11. लाइसेंस (भंडारण) शुल्क की आशोधित दरें और सामान्य टिप्पणियां, जो नई जोड़ी गई हैं, डीपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित, नीचे दी जा रही है:-

(रु. में)

अनुसूची V – किराया शुल्क	दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका भाग प्रति माह या उसका भाग	
	कच्चा भूखंड	पक्का भूखंड
<b>खुले स्थान के लिए</b>		
0 – 60 दिन	23.34	144.00
61 – 90 दिन	46.68	288.00
91 – 180 दिन	58.35	360.00
180 दिन से अधिक	70.03	432.00
<b>क्वर्ड स्थान के लिए</b>		
0 – 60 दिन		279.00
61 – 90 दिन		558.00
91 – 180 दिन		697.50
180 दिन से अधिक		837.00

**सामान्य टिप्पणियां:**

- (i). जहां कोई विशिष्ट दर उपलब्ध नहीं है, सदृश्य मदों के लिए कांडला के लिए निर्धारित दर लागू होगी, बशर्ते तूना पत्तन दर प्रदत्त सेवाएं/सुविधाएं कांडला के समान हों।
- (ii). तूना में सेवाएं प्रदान करने के अनुबंध और शर्तें समान हो जैसी कांडला स्थित सदृश सेवाएं निर्धारित है बशर्ते तुलनीय सेवाएं/सुविधाएं प्रदान की जाएं।
- (iii). बिल की कुल राशि को अगले उच्च रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

12.1. उपरोक्त के पश्चात्, डीपीटी को हमारे 13 दिसंबर, 2018 के द्वारा 15 दिसंबर, 2018 तक निम्नलिखित मुद्दों पर और अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया:

- (i). डीपीटी का प्रस्ताव तूना पत्तन के लिए प्रस्तावित संशोधित प्रशुल्क की प्रभावी तारीख के बारे में मौन है। डीपीटी स्पष्ट करे कि क्या तूना पत्तन के लिए प्रस्तावित संशोधित प्रशुल्क को डीपीटी के दरमानों के पिछले सामान्य संशोधन की तारीख से यानी 11 अगस्त, 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जायेगा या डीपीटी द्वारा विषयक प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश की तारीख से उत्तरव्यापी प्रभाव से प्रभावी किया जाएगा।
- (ii). (क). 13 मार्च, 2018 के मूल प्रस्ताव में, क्रमांक (ड) पर तूना पत्तन के लिए प्रस्तावित दर का नाम "किराया शुल्क" रखा गया है, जैसा कि डीपीटी के न्यासी मंडल ने अनुमोदित किया है और जैसा इस प्राधिकरण द्वारा 2011 में अनुमोदित संशोधन पूर्व दरमानों में प्रचलित है।  
डीपीटी द्वारा 11 अप्रैल, 2018 के अपने पत्र में दिये गए स्पष्टीकरण के आलोक में यह मद कार्गो संबंधी प्रभार है यानी कार्गो के भंडारण के लिए भंडारण स्थान का आबंटन करना और यह भी कि पत्तन ने अपने 21 जुलाई 2018 के संशोधित प्रस्ताव में कार्गो के ठहराव के लिए स्लैब-वार दर का प्रस्ताव किया है, पत्तन परीक्षण करे और स्पष्ट करे कि क्या नाम को "कार्गो भंडारण के लिए किराया शुल्क" के रूप में आशोधित किये जाने की जरूरत है।
- (ख). मौजूदा दरमानों में, अनुसूची 2.5 के अंतर्गत कांडला प्रभाग के लिए सामान्य कार्गो हेतु लाइसेंस (भंडारण) शुल्क निर्धारित करते समय दर को शासित करने वाली विभिन्न सोपाधिकताएं नियत की गई हैं। पत्तन परीक्षण करे कि क्या तूना पत्तन के कार्गो भंडारण के लिए किराया शुल्क की उगाही के लिए भी तत्संबंधी सोपाधिकताएं शासित की जानी हैं।

12.2. प्रत्युत्तर में, डीपीटी ने 19 दिसंबर, 2018 के अपने पत्र के द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए:

- (i). जहां तक तूना पत्तन की प्रस्तावित संशोधित दर की प्रभावी तारीख ऊपर 12.1 (i) का संबंध है, पत्तन ने बताया है कि मामले को भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) की भेजा गया है और उनकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने वाली है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया इस मामले को अभी रोके रखा जाए। जैसे ही आईपीए की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, प्राधिकरण को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।
- (ii). ऊपर 12.1 (ii) (क) के संबंध में, प्रस्तावित सेवा के नाम को "सामान्य कार्गो पर लाइसेंस (भंडारण) शुल्क" के रूप में आशोधित किया जाये।
- (iii). ऊपर 12.1 (ii) (ख) के संबंध में, अनुसूची 2.5 के अंतर्गत कांडला प्रभाग के लिए "सामान्य कार्गो हेतु लाइसेंस (भंडारण) शुल्क" के अंतर्गत मौजूदा दरमानों में सोपाधिकताएं को तूना पत्तन के कार्गो भंडारण के लिए नियत किया जा सकता है।

12.3. तथापि, चूंकि डीपीटी से ऊपर पैरा 12.2 (i) के संबंध में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ इसलिए डीपीटी के साथ 25 जनवरी, 2019, 07 मार्च, 2019 और 01 अप्रैल, 2019 के अनुस्मारकों के साथ कार्रवाई की गई।

12.4. प्रत्युत्तर में, डीपीटी ने 06 जून, 2019 के आदेश ई-मेल के द्वारा बताया कि बोर्ड ने 28 मई, 2019 को हुई अपनी बैठक में संकल्प संख्या 22 के द्वारा तूना पत्तन की प्रस्तावित संशोधित दर की प्रभावी तारीख 11 अगस्त, 2016 अनुमोदित की है यानी डीपीटी के दरमानों के पिछले सामान्य संशोधन की प्रभावी तारीख। डीपीटी द्वारा बोर्ड के संकल्प की प्रति भी भेजी है।

13. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए मतों का सार उनको पृथक् रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

14. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के आधार पर निम्नलिखित सूचना उभर कर सामने आती है:

- (i). डीपीटी का प्रस्ताव इस प्राधिकरण के 21 जून, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2016-केपीटी द्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) के दरमानों के पिछले सामान्य संशोधन में तूना पत्तन के भंडारण प्रभारों सहित पोत संबंधी प्रभारों (वीआरसी) और कार्गो संबंधी प्रभारों (सीआरसी) में अत्यधिक वृद्धि के मद्देनजर संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों द्वारा किये गए अभ्यावेदन से प्रवाहित हुआ है। उक्त दरमानों में संशोधन के दौरान, डीपीटी ने इस प्राधिकरण द्वारा 18 जनवरी, 2011 के आदेश संख्या टीएएमपी/61/2009-केपीटी द्वारा डीपीटी के दरमानों में तूना पत्तन के लिए तब अभिभावी अलग से दरमानों को विलुप्त करने का प्रस्ताव किया था। पत्तन ने, 2016 के संशोधन के दौरान, कांडला पत्तन की दरों को तूना पत्तन को लागू करने का प्रस्ताव सामान्य टिप्पणियों के अंतर्गत एक टिप्पणी निर्धारित करके किया।

इस प्राधिकरण ने 18 जनवरी, 2011 के आदेश संख्या टीएएमपी/61/2009-केपीटी के द्वारा अनुमोदित डीपीटी के दरमान पोत संबंधी प्रभारों, घाटशुल्क प्रभारों, किराया शुल्क और ट्राली किराया प्रभारों को तूना पत्तन के लिए अध्याय-V के अंतर्गत अलग से निर्धारित थे जैसा कि क्राफ्टों की किस्म, प्रहस्तित किये जा रहे कार्गो की किस्म और तूना पत्तन में ड्राफ्ट की अपेक्षा को ध्यान में रखकर डीपीटी द्वारा तब प्रस्ताव किया गया था।

वर्ष 2016 में प्रशुल्क नीति 2005 के अंतर्गत डीपीटी के पिछले सामान्य संशोधन के दौरान, पत्तन के तूना पत्तन की अलग दे दरसूची को समाप्त करने का प्रस्ताव किया। पत्तन ने इसके स्थान पर यह कहते हुए कि टिप्पणी अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव किया कि कांडला पत्तन पर लागू प्रशुल्क तूना पत्तन पर भी लागू होंगे। डीपीटी के प्रस्ताव के संशोधन के दौरान जो 21 जून, 2016 के आदेश के रूप में परिणत हुआ, प्रस्तावित टिप्पणी के संदर्भ में डीपीटी को विशिष्ट रूप से यह औचित्य बताने का अनुरोध किया गया था कि क्या तूना पत्तन पर प्रदान की जा रही सेवाएं डीपीटी के कांडला प्रभाग के समान हैं। इस संदर्भ में डीपीटी ने तब स्पष्ट किया था कि तूना पत्तन पर सड़क और रेल पहुंच जैसी सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और यह भी स्पष्ट किया था कि तूना में प्रदान की जा रही सेवाएं, अवसंरचना, उपस्कर और सुविधाएं कांडला प्रभाग में प्रदत्त की जा रही के तुल्य हैं। पत्तन द्वारा दिये गए औचित्य प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर तूना पत्तन के लिए अध्याय- V में तब प्रचलित दरों की अलग से अनुसूची को विलुप्त कर दिया, जैसा डीपीटी ने प्रस्ताव किया था और डीपीटी द्वारा कांडला दरों के तूना पत्तन पर लागू करने की टिप्पणी को सामान्य निबंधन व शर्त क्रमांक 1.2 में टिप्पणी संख्या (xv) के रूप में निर्धारित किया गया था। डीपीटी का वर्तमान प्रस्ताव वापस लौटने का है और कुछेक प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों द्वारा किये गए अभ्यावेदन के आधार पर तूना पत्तन के लिए अलग से दर अनुसूची निर्धारित करने का है।

अदानी कांडला बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एकेबीटीपीएल), डीपीटी के तूना पत्तन पर बल्क टर्मिनल प्रचालक (अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 द्वारा शासित) द्वारा किया गया निवेदन कि 2016 के आदेश में अनुमोदित दरमानों में तूना पत्तन की दर गलती से छूट गई है, वास्तव में सही नहीं है। जैसा कि पूर्व के पैरा में चर्चा की गई है और 21 जून, 2016 के प्रशुल्क आदेश के पैरा 20 (xii) (ग) में बताए गए कारणों से डीपीटी द्वारा प्रस्तावित तूना पत्तन के लिए तब की दर अनुसूची को संशोधित दरमान में हटा दिया गया है सामान्य निबंधन और शर्तों के क्रमांक 1.2 की टिप्पणी संख्या (xv) को यह कहते हुए जोड़ा गया था कि पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित डीपीटी के दरमानों में कांडला दरें तूना पत्तन के लिए भी निर्धारित की गई है।

- (ii). अब, डीपीटी के वर्तमान प्रस्ताव पर आते हैं साल्या सेलिंग वैसल्स आनर्स एसोसिएशन (एसएसवीओए) द्वारा तूना पत्तन के पत्तन प्रभागों की समीक्षा के लिए डीपीटी को दिये गए अभ्यावेदन के आधार पर, कांडला प्रभाग की दरों को तूना पत्तन पर लागू करने के कारण तूना पत्तन पर इंडियन सेलिंग पोतों के पत्तन प्रभागों में अत्यधिक वृद्धि होने को देखते हुए और जून 2016 के आदेश में अनुमोदित दरमानों के अनुसार तूना पत्तन के लाइसेंस शुल्कों में अत्यधिक वृद्धि के बारे में एकेबीटीपीएल द्वारा उठाये गए मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए, डीपीटी ने डीपीटी के वर्तमान दरमानों में अध्याय- V के रूप में तूना पत्तन के लिए अलग से प्रशुल्क अनुसूची अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव दायर किया है। यह जून 2016 के आदेश से पहले जनवरी 2011 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधन पूर्व दरमानों में की गई व्यवस्था का अनुपालन करने के बारे में है।

यद्यपि डीपीटी के वर्तमान दरमान 31 मार्च, 2019 तक वैध है, डीपीटी ने डीपीटी के वर्तमान दरमान में तूना पत्तन के लिए दरों की अलग से अनुसूची के लिए इस प्राधिकरण का अनुमोदन चाहने के अपने प्रस्ताव को निम्नलिखित कारणों से उचित बताया है:-

- (क). घाट प्रभागों में लगभग 200%, बर्थ किराया प्रभाग में 150% और टून पतृतन की पत्तन देयताओं में 500% की वृद्धि हुई है जो अत्यधिक ऊँची है।
- (ख). डीपीटी द्वारा तूना पर तलकषण पर कोई व्यय नहीं किया है।
- (ग). तूना पर न्यूनतम कर्मचारी तैनात हैं और इस प्रकार, मानवशक्ति पर लागत काफी कम है।
- (घ). तूना पर पशुधन का प्रहस्तन होता है जिससे घाट आदि को मुश्किल से ही कोई क्षति होती है।
- (ङ). तूना बांडी और निकटवर्ती अन्य गांवों की जीविका तूना से पशुधन के निर्यात पर निर्भर है।
- (च). मशीनीकृत क्राफ्ट स्वामी अमीर नहीं है और वे बैंक/वित्तीय संस्थानों से ऋण पर ही निर्भर हैं।

प्रयोक्ता संघ और एकेबीटीपीएल द्वारा किये गए अभ्यावेदनों को देखते हुए डीपीटी ने डीपीटी के तूना पत्तन के दरमानों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जिसमें यातायात प्रबंधक, उप-संरक्षक, मुख्य अभियंता और वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी थे। डीपीटी द्वारा वर्तमान प्रस्ताव तूना पोर्ट की दरों की समीक्षा के लिए डीपीटी द्वारा गठित समिति की संस्तुति और डीपीटी के न्यासी बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर दायर किया गया है।

इस प्रकार डीपीटी द्वारा ऊपरी बतायी गई स्थिति को ध्यान में रखकर प्रशुल्क नीति 2018 के अंतर्गत डीपीटी के वर्तमान दरमानों में तूना पत्तन के लिए दरों की समीक्षा के लिए दायर वर्तमान प्रस्ताव पर सुविचार का मामला बनता है, यद्यपि डीपीटी के वर्तमान दरमान 30 सितंबर 2019 तक वैध हैं। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि हाल ही में, इस प्राधिकरण ने मरमुगाव पत्तन न्यास (एमओपीटी) और डीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर दरमानों के प्रचलन में रहने के दौरान अपने-अपने दरमानों में कुछ मर्दों के लिए दरों का संशोधन किया है।

इस मामले में डीपीटी परिसर में 11 जून, 2018 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। हमारे 28 जून, 2018 के पत्र के द्वारा उनके प्रस्ताव के संदर्भ में सूचना/स्पष्टीकरण 5 जुलाई, 2018 तक मांगा गया था। निरंतर अनुवर्तन के पश्चात्, पत्तन ने वांछित सूचना/स्पष्टीकरण, आशोधन प्रारूप दरमान और सोपाधिकताओं के साथ, अपने 21 जुलाई, 2018 के और बाद में 18 अक्टूबर, 2018 तथा 19 नवंबर, 20 नवंबर, 30 नवंबर, 2018, 19 दिसंबर, 2018 और 6 जून, 2019 के ई-मेल द्वारा प्रस्तुत की। इस मामले को पत्तन द्वारा पूरी सूचना दिये जाने के पश्चात् ही इस प्राधिकरण द्वारा संसाधित किया जा सकता था जो अंत में 06 जून, 2019 को प्राप्त हुई।

डीपीटी का प्रस्ताव प्रशुल्क नीति 2015 के अंतर्गत दायर किया गया है और पूरा संसाधन प्रशुल्क नीति 2015 के अंतर्गत किया गया है जो 26 दिसंबर 2018 से प्रभावी नई प्रशुल्क नीति 2018 के जारी होने तक वैध थी। एमओएस द्वारा जारी प्रशुल्क नीति 2018 की संरचना कुछेक छोटे-मोटे संशोधनों के सिवा प्रशुल्क नीति 2015 के समान ही है। चूंकि प्रशुल्क 2015 का 26 दिसंबर, 2018 से प्रशुल्क नीति, 2018 द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है, इस मामले को इस प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क नीति 2018 के अधीन अंतिम रूप दिया जाता है।

- (iii). इस मामले का विश्लेषण आरंभ करने से पूर्व, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि, कच्चे भूखंड के लिए लाइसेंस (भंडारण) शुल्क प्रस्तावित दर निकालने के लिए, पत्तन ने भूमि के मूल्यांकन के लिए संशोधित भू-नीति दिशानिर्देश (एलपीजी) 2014 में निर्धारित विभिन्न विधियों का अनुपालन किया है।

इस संबंध में, डीपीटी ने स्पष्ट किया है कि, केवल कच्चे भूखंड की दर निर्धारण के लिए, पत्तन ने अधिकृत भू-मूल्यांकक द्वारा दी गई भू-मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा किया है जिसे एलएसी ने अनुमोदित किया है। पत्तन ने साफ तौर पर बताया है कि तूना पत्तन के कच्चे भूखंड के लाइसेंस (भंडारण) शुल्क के संशोधन का प्रस्ताव सीआरसी के अंतर्गत आता है। पत्तन कार्गो के भंडारण के लिए भंडारण स्थान आवरित करता है और कार्गो के ठहराव के आधार पर प्रभारों की उगाही की जाती है। पत्तन से साफ तौर पर बताया है कि यह संशोधित एलपीजी 2014 के अनुसार यह पट्टे और लाइसेंस आधार पर भू आबंटन नहीं होता, अतः तूना स्थित कच्चे भूखंड के लिए प्रस्तावित भंडारण प्रभार संशोधित एलपीजी 2014 के अंतर्गत नहीं आते। पत्तन ने यह भी जोर देकर कहा है कि कच्चे भूखंड के लिए चाही गई दरें प्रशुल्क दिशानिर्देश 2015, जिसे प्रशुल्क नीति 2018 के रूप में संशोधित कर दिया गया है, के सिद्धांतों के अधीन दरमानों के सामान्य संशोधन के अंतर्गत कवर्ड होती हैं।

जहां तक एकेबीटीपीएल द्वारा उठायी गई आपत्तियों का संबंध है, कि लाइसेंस के प्रचलन में रहने के दौरान मौजूदा परियोजना के लिए प्रशुल्क नीति 2015 और एलपीजी 2014 के दो दिशानिर्देशों को जोड़ रहा है इसलिए डीपीटी का प्रस्ताव अतर्कसंगत, अविवेचित, कानूनी रूप से अमान्य और अनुचित है, पत्तन ने दोहराया है कि यह दो दिशानिर्देशों अर्थात् प्रशुल्क नीति 2015 और एलपीजी 2014 को मिलाना नहीं है। एकेबीटीपीएल ने प्रस्तावित लाइसेंस (भंडारण) शुल्क निकालने के लिए डीपीटी द्वारा सुविचारित भूमि के मूल्यांकन पर भी आपत्ति की है। पत्तन ने साफ तौर पर यह बताया है कि वर्तमान प्रस्ताव केवल प्रशुल्क नीति 2015 के दायरे के भीतर रहते हुए ही बनाया गया है, जिसे प्रशुल्क नीति 2018 द्वारा संशोधित किया गया है, और उसी ढांचे में रखा गया है। तूना पत्तन के कच्चे भूखंड के लाइसेंस (भंडारण) शुल्क का प्रस्ताव करते समय, दरों के निर्धारण के लिए ही, तूना पत्तन पर भूमि की दरों की समीक्षा के लिए पत्तन द्वारा गठित समिति द्वारा तूना पत्तन क्षेत्र में मूल्यांकक द्वारा प्रस्तुत नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा किया है तथा एलएसी द्वारा अनुमोदित है। यह दरें प्रशुल्क नीति 2015 के सिद्धांतों के अनुरूप दरमानों के सामान्य संशोधन के कार्गो संबंधी प्रभारों के अंतर्गत कवर्ड होती हैं और इसलिए उक्त दरों का प्रस्ताव करते समय डीपीटी ने एलपीजी 2014 को लागू नहीं किया है। पत्तन ने आगे और स्पष्ट है कि वर्तमान प्रस्ताव एलपीजी 2014 के दायरे से बाहर है और इसका उससे कोई संबंध नहीं है।

21 जुलाई, 2018 के संशोधित प्रस्ताव में, डीपीटी ने कार्गो के ठहराव के लिए 0-60 दिन, 61-90 दिन, 91-180 दिन और 180 दिन से अधिक दिनों के लिए स्लैब-वार लाइसेंस (भंडारण) शुल्क का प्रस्ताव किया है। डीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित दर डीपीटी की दलील को सुदृढ़ता प्रदान करती है कि कार्गो के ठहराव की अवधि से संबद्ध लाइसेंस (भंडारण) शुल्क दरें दरमानों के सामान्य संशोधन के एक भाग के रूप में कार्गो संबंधी प्रभारों के अंतर्गत आती हैं। उक्त स्थिति को देखते हुए और डीपीटी द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण और औचित्य को ध्यान में रखकर, यह प्राधिकरण डीपीटी के पूरे प्रस्ताव पर प्रशुल्क नीति 2018 के अंतर्गत सुविचार करता है। प्रशुल्क नीति 2015 और संशोधित प्रशुल्क नीति 2018 पत्तन को पहले ही यह शिथिलता देती हैं कि दरमानों में प्रस्तावित दरें एआरआर के भीतर ही हों।

- (iv). (क). डीपीटी द्वारा प्रस्तावित तूना पत्तन के लिए दरों की अनुसूची पत्तन द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर आधारित है।
- (ख). समिति ने वीआरसी यानी पत्तन देयताएं, बर्थ किराया प्रभार, तूना पत्तन के लिए बीचिंग प्रभारों की सिफारिश 18 जनवरी, 2011 के इस प्राधिकरण के आदेश में अनुमोदित डीपीटी के सामान्य दरमानों में तूना पत्तन के लिए निर्धारित संशोधन-पूर्व दरों को आधार पर के रूप में लेकर और 2011-2016 तक के 30.35% डब्ल्यूपीआई सूचकांकन को लागू करके की गई है। प्रशुल्क नीति, 2018 महापत्तन न्यासों को एआरआर के भीतर दरमान प्रस्तावित करने की शिथिलता प्रदान करती है।

2011 के आदेश (18 जनवरी, 2011 का आदेश संख्या टीएएमपी/61/2009-केपीटी) में संशोधन-पूर्व दरों, जून 2016 के आदेश में (21 जून 2016 का आदेश संख्या टीएएमपी/18/2016-केपीटी) तूना पत्तन के लिए लागू दरों और डीपीटी द्वारा तूना पत्तन के लिए अब प्रस्तावित दरों के साथ-साथ तूना पत्तन में डीपीटी दर के लागू होने पर 2016 आदेश में प्रतिशत वृद्धि, 2016 के प्रशुल्क आदेश के अनुसार लागू दरों के प्रति तूना पत्तन के लिए अलग से प्रस्तावित दरों में प्रतिशत वृद्धि/घटौती तथा 2011 आदेश के अनुसार तब प्रचलित दर पर प्रतिशत वृद्धि/घटौती को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है।

अनुलग्नक के रूप में संलग्न तुलनात्मक विवरण (कालम 10) से देखा जा सकता है कि जैसा एसएसवीओए ने सही कहा है कि प्रशुल्क आदेश 2016 में कांडला दरों को तूना पत्तन पर लागू करने के लिए टिप्पणी के निर्धारण से वीआरसी में अत्यधिक वृद्धि हो गई अर्थात् पत्तन देयताओं में 901% से 1069% बर्थ किराया प्रभारों में 667% और बीचिंग प्रभारों में 769% वृद्धि हो गई।

डीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित दर को निकालने के लिए 30.35% डब्ल्यूपीआई लागू किया गया है 2011 की तब प्रचलित दर पर वृद्धि जो 10 अगस्त 2016 तक लागू थे और 11 अगस्त 2016 से संशोधित दरमान प्रभावी हो गए थे। वीआरसी में संशोधित प्रस्तावित दर, 2011 के आदेश पर 30.33% से 30.37% वृद्धि होती है। प्रस्तावित दर प्रशुल्क आदेश 2016 के अनुसार लागू दर पर प्रस्तावित दर 83% से 87% घटौती दर्शाती है।

इस प्रस्ताव में यह मान्य करते हुए कि तूना पत्तन के लिए डीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित वीआरसी समिति द्वारा संस्तुत और बोर्ड के अनुमोदन पर आधारित है जो संबंधित संघ द्वारा डीपीटी को कांडला पत्तन की दरों के तूना पत्तन पर लागू करने से हुई अत्यधिक वृद्धि के प्रति किये गए अभ्यावेदनों से प्रवाहित है, यह प्राधिकरण तूना पत्तन के लिए डीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित दर को अनुमोदित करने को प्रवृत्त है। चूंकि प्रस्ताव मौजूद दर को घटाने के लिए है, संशोधित प्रस्तावित दर पर राजस्व के 2016 के आदेश में पिछले प्रशुल्क संशोधन में आकलित एआरआर से बढ़ने की प्रत्याशा नहीं की जाती।

2011 में अनुमोदित डीपीटी के दरमानों में तूना पत्तन के लिए लंगरगाह प्रभारों की दरें निर्धारित नहीं की गई थी। पत्तन ने अब प्रशुल्क आदेश 2016 में अनुमोदित कांडला प्रभाग के भीतरी लंगरगाह की मौजूदा दर के समान दर को तूना पत्तन के लिए लंगरगाह प्रभार के रूप में निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित दर अनुमोदित की जाती है।

- (ग). प्रशुल्क आदेश 2016 के अनुसार लागू दर पर घाटशुल्क (सीआरसी) में संशोधन पूर्व दर वृद्धि अधिकतर मदों के लिए 20% से 233% के बीच और पीओएल उत्पादों के लिए 456% है।

जहां तक सीआरसी का संबंध है, डीपीटी द्वारा गठित कथित समिति ने निर्णय दिया कि पत्तन ने अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन पर जैसे सड़के, बर्थ, बार्ज जेटी, पृष्ठ क्षेत्र, प्रकाश आदि, काफी राशि का निवेश किया है और इस प्रकार कार्गो संबंधी प्रभारों को कम करना उपयुक्त नहीं है। तथापि मैसर्स एसएसवीओए के अनुरोध को देखते हुए पशुधन के लिए घाटशुल्क दर को 2016 के आदेश के अनुसार लागू मौजूदा दर से घटाने का प्रस्ताव है। डीपीटी का प्रस्ताव बताता है कि समिति की सिफारिश के आधार पर पशुधन की संशोधित दर अर्थात् कुक्कुर, भेड़ तथा बकरी सहित पशु (कुक्कुर, भेड़ व बकरी सहित अन्य पशु) और पशु उत्पादों, अस्थिचूर्ण, खाल और चमड़ा के लिए दर 2011 में अनुमोदित घाटशुल्क दर पर 30.35% की डब्ल्यूपीआई वृद्धि दर लागू करके निकाली गई है। घाटशुल्क दर में वृद्धि, पशुधन की उक्त श्रेणियों के लिए 2011 के आदेश की संशोधन पूर्व दरों पर क्रमशः 30.33%, 30.42% और 30.44% निकलती है। 2016 के आदेश के अनुसार लागू मौजूदा दरों की तुलना में डीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित घाटशुल्क दरें कुक्कुर, भेड़ तथा बकरी सहित पशु के लिए 56.56%, पशु (कुक्कुर, भेड़ व बकरी सहित अन्य पशु) के लिए 47.83%, पशु उत्पादों, अस्थिचूर्ण, खाल और चमड़ा के लिए 34.78% की घटौती हुई है। अन्य मदों के लिए डीपीटी ने 2016 के आदेश के अनुसार इस समय लागू घाटशुल्क दर को धारित रखने का प्रस्ताव किया है।

डीपीटी ने तूना पत्तन के लिए अलग से घाटशुल्क अनुसूची शामिल करने का प्रस्ताव किया है जैसा इस प्राधिकरण ने 2011 के आदेश के दरमानों में अनुमोदित की थी। यह मान्य करते हुए कि डीपीटी का प्रस्ताव समिति की सिफारिश पर डीपीटी के न्यासी मंडल के अनुमोदन पर आधारित है, तूना पत्तन के लिए प्रस्तावित घाटशुल्क अनुसूची को डीपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित अनुमोदित की जाती है। चूंकि प्रस्ताव वर्तमान घाटशुल्क दर की 3 मदों में घटौती का है, इसलिए संशोधित प्रस्तावित दर पर राजस्व के 2016 के पिछले प्रशुल्क आदेश में आकलित एआरआर से बढ़ने की प्रत्याशा नहीं है।

- (घ). 2016 में अनुमोदित मौजूदा दरमान टिम्बर ऑन बोर्ड के भंडारण और ट्राली किराया प्रभारों के लिए कोई प्रशुल्क निर्धारित नहीं करते। 2011 में अनुमोदित संशोधन पूर्व दरमानों में तूना पत्तन पर ट्राली प्रभारों के लिए 15 रु. प्रति दिन और टिम्बर ऑन बोर्ड भंडारण के लिए 1.5 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति दिन की दर निर्धारित थी। चालू प्रस्ताव में उक्त दोनों मदों के लिए प्रस्तावित दर क्रमशः 19.55 रु. प्रति प्रति दिन और 1.96 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रतिदिन को डीपीटी द्वारा 30.35% डब्ल्यूपीआई से गुणा करके निकाली गई है जो 2011 की तब प्रचलित दर पर वृद्धि है जैसाकि तूना पत्तन के संशोधित वीआरसी के मामले में किया गया है। प्रस्तावित विविध सेवाओं के लिए है और इससे कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अतः इन दो मदों के लिए प्रस्तावित दर अनुमोदित की जाती है।

- (ड). 2011 के प्रशुल्क आदेश में अनुमोदित दरमान खुले स्थान के लिए किराया प्रभार 7.50 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति माह या उसके एक भाग के लिए (यानी 9.00 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष [अर्थात् 7.50 रु./10 वर्ग मीटर x 12 माह]) था। आवरित स्थान के लिए 2011 आदेश में निर्धारित दर 48 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति माह या उसके एक भाग के लिए अर्थात् 57.60 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष [अर्थात् 48 रु./10 वर्ग मीटर x 12 माह] है।

डीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर 2016 के प्रशुल्क आदेश में अनुमोदित दरमानों में कांडला प्रभाग के लाइसेंस (भंडारण) शुल्क को तूना पत्तन पर लागू करने से खुले स्थान में कच्चे भूखंड में 1020% से 3260% की और खुले स्थान में पक्के भूखंड के लिए 1820% से 5660% तथा आवंटित स्थान के लिए 481% से 1644% तक की अविश्वसनीय वृद्धि हो गई।

2011 के पहले दरमानों में तूना पत्तन के लिए लाइसेंस (भंडारण) शुल्क प्रत्येक खुले स्थान और आवरित स्थान के लिए एकल दर निर्धारित थी, जैसा पहले बताया गया है डीपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित।

डीपीटी ने समिति की संस्तुति के आधार पर खुले क्षेत्र के लिए मूल रूप से प्रस्तावित लाइसेंस (भंडारण) शुल्क को दो श्रेणियों में बांटा अर्थात् कच्चा भूखंड और पक्का भूखंड लाइसेंस (भंडारण) शुल्क का प्रस्ताव खुले के अंतर्गत पक्के भूखंड और आवरित स्थान के लिए डीपीटी द्वारा स्लैब-वार दरें डीपीटी के मौजूदा दरमान में प्रशुल्क आदेश 2016 की अनुसूची 2.5 में निर्धारित लाइसेंस (भंडारण) शुल्क के समान रखे हैं।

जहां तक कच्चे भूखंड का प्रश्न है, डीपीटी ने पहले 84.03 रु. प्रति वर्ग मीटर या उसके एक भाग प्रति वर्ष प्रस्तावित की थी। यह 70.03 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति माह (84.03 रु./12माहx वर्ग मीटर) निकलती है। तत्पश्चात्, डीपीटी ने कांडला के लिए लागू के आधार पर स्लैब-वार दर और उगाही की यूनिट 10 वर्ग मीटर प्रति माह या उसका एक भाग प्रस्तावित की है। डीपीटी द्वारा पहले स्लैब के लिए प्रस्तावित दर 0-60 दिन के लिए 23.34 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति माह या उसके एक भाग पर और 61-90 दिन के लिए 46.68 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति माह या उसके एक भाग पर, 91-180 दिन के लिए 58.35 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति माह या उसके एक भाग पर और 180 दिन से आगे की अवधि के लिए 70.03 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति माह या उसके एक भाग पर रखी हैं। ठहराव की अवधि के विभिन्न खंडों के लिए कच्चे भूखंड के लिए प्रस्तावित स्लैब वार ढांचा उसी सादृश्यता पर आधारित है जैसा कि कांडला प्रभाग के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है।

प्रस्तावित दर पर खुले स्थान के कच्चे भूखंड की दरों में 2016 के आदेश के अनुसार लागू दर पर के प्रति प्रत्येक स्लैब में 72.21% की कमी आती है। खुले स्थान के पक्के प्लॉट और आवरित स्थान के लिए कांडला की दर के समान रखने का प्रस्ताव इस बात को मान्य करते हुए किया गया है कि ऐसा डीपीटी का प्रस्ताव डीपीटी द्वारा तूना पत्तन की दरों की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिश पर आधारित है और इसे डीपीटी के न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है, इसलिए तूना पत्तन के लिए प्रस्तावित संशोधित लाइसेंस (भंडारण) शुल्क अनुमोदित है।

बाद में पत्तन ने सामान्य कार्गो के लिए लाइसेंस (भंडारण) शुल्क के रूप में नाम निर्धारित करने का अनुरोध किया। चूंकि प्रभार कार्गो के भंडारण के लिए हैं, यह यथेष्ट होगा कि यदि इसका नाम "सामान्य कार्गो भंडारण प्रभार" रखा जाए।

प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 2.6 के अनुसार, महापत्तन न्यासों के पास वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर बाजार के अनुरूप दरों के निर्धारण की शिथिलता प्राप्त है और वे सूचकांकित एआरआर की



अधिकतम सीमा के भीतर दरमान निर्धारित कर सकते हैं। 21 जून 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2016-केपीटी के द्वारा डीपीटी के पिछले दरमानों में किये गए संशोधन में, इस प्राधिकरण द्वारा आकलित एआरआर 84,251.84 लाख रु. प्रति वर्ष था और प्रस्तावित दरमानों पर डीपीटी द्वारा आकलित तथा उक्त आदेश द्वारा अनुमोदित राजस्व 83,551.58 लाख रु. था। 700.26 लाख रु. के अंतर को (84,251.84 लाख रु. घटाएं 83,551.58 लाख रु.) इस प्राधिकरण द्वारा आरक्षित छोड़ दिया गया था। जिसे पत्तन को प्रशुल्क मदों और सोपाधिकताओं से देखना होगा जिसके लिए डीपीटी उस समय राजस्व कैप्चर नहीं कर सका।

पत्तन ने तूना पत्तन की प्रस्तावित दरों पर राजस्व में 129.53 लाख रु. प्रति वर्ष की घटौती का आकलन किया है जो वीआरसी में और कुछेक मदों में घाटशुल्क प्रभारों में प्रस्तावित कमी के कारण हुआ है।

जहां तक भंडारण प्रभारों का संबंध है पत्तन ने स्पष्ट किया है कि एआरआर को वित्तीय प्रभाव का कोई आकलन नहीं किया गया है क्योंकि इसे प्रशुल्क नीति, 2015 के अनुसार एआरआर में सुविचारित नहीं किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यकारी दिशानिर्देश महापत्तन न्यासों से प्रस्तावित दरमानों की प्रत्येक प्रशुल्क मद से राजस्व आकलन की अपेक्षा करते हैं। अतः डीपीटी का यह कहना कि प्रशुल्क नीति 2015 भंडारण प्रभारों से राजस्व आकलन की अपेक्षा नहीं रखती ठीक नहीं है। इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि प्रशुल्क संशोधन आदेश में भंडारण प्रभारों से राजस्व आकलन 24.11 लाख रु. था। डीपीटी द्वारा आकलित राजस्व कांडला पत्तन और तूना पत्तन के भंडारण प्रभारों का अलग से आकलन नहीं दर्शाता। अब, पत्तन ने खुले स्थान के पक्के भूखंड और आवरित स्थान के लिए भंडारण प्रभारों को धारित रखते का प्रस्ताव किया है जैसा 2016 के आदेश में है। अतः कोई राजस्व प्रभाव नहीं हो सकता/ जहां तक कच्चे भूखंड के लिए खुले स्थान के भंडारण प्रभारों का संबंध है, डीपीटी ने 2016 के आदेश में लागू दर में कटौती करने का प्रस्ताव किया है। अतः इस परिदृश्य में 2016 के प्रशुल्क आदेश में आकलित राजस्व, जिसमें भंडारण प्रभार भी शामिल हैं, के कम होने की संभावना है न कि बढ़ने की/ इस बात को मान्य करते हुए कि महापत्तन न्यासों के पास वाणिज्य निर्णय के आधार पर बाजार के अनुरूप दरों के निर्धारण की शिथिलता प्राप्त है और वे सूचकांकित एआरआर की अधिकतम सीमा के भीतर दरमान निर्धारित कर सकते हैं। डीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित भंडारण प्रभार को अनुमोदित किया जाता है।

- (च). इस प्रकार संक्षेप में डीपीटी के अध्याय-V के रूप में तूना पत्तन के लिए अलग से दर अनुसूची अंतर्विष्ट करने के प्रस्ताव को, डीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित, अनुमोदित किया जाता है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, तूना/तेकरा स्थित एकेबीटीपीएल द्वारा चालू किये गए शुष्क बल्क टर्मिनल पर डीपीटी द्वारा प्रदान की जा रही नौचालन संबंधी सेवाओं के प्रशुल्क संबंधी वर्तमान अध्याय-V को, डीपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित, अध्याय-V (क) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाता है।

डीपीटी के प्रस्ताव के दिये गए अनुमोदन को देखते हुए, मौजूदा दरमानों में सामान्य निबंधन और शर्तों में निर्धारित मौजूदा टिप्पणी संख्या (xv) निष्फल हो जाती है इसलिए विलुप्त की जाती है।

- (v). एकेबीटीपीएल द्वारा उठाये गए मुद्दों में से एक, यह है कि एलपीजी 2014 नए भू पट्टों के आबंटन और/अथवा समाप्त पट्टों के नवीकरण पर ही लागू होती है जबकि तूना पत्तन पर उन्हें आवरित भूमि पट्टे का नया आबंटन नहीं है अतः डीपीटी द्वारा किया गया मूल्यांकन उन पर लागू नहीं होता। एकेबीटीपीएल ने यह भी उल्लेख किया है कि मूल्यांकन रिपोर्ट में किडना और भारपर गांवों में भू लेन-देन से संकेत लिए हैं जो कि एकेबीटीपीएल के क्षेत्र से 14-18 कि.मी. दूर हैं और तूना और विंडी के निकटवर्ती गांवों को पूर्णतः छोड़ दिया गया है। इस संदर्भ में, जैसा पहले बताया गया है, डीपीटी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि तूना पत्तन के

भंडारण प्रभारों में संशोधन एलपीजी, 2014 के अंतर्गत नहीं आता बल्कि यह प्रशुल्क नीति 2015 के अंतर्गत क्रवर होता है। तूना पत्तन के कच्चे भूखंड की दर निकालने के लिए ही, डीपीटी ने अधिकृत मूल्यांकक द्वारा दिये गए भू-मूल्यांकन पर भरोसा किया है। प्रशुल्क नीति 2015 और 26 दिसंबर, 2018 से प्रभावी प्रशुल्क नीति 2018, महापत्तन न्यासों को एआरआर के भीतर दरमान रखने की शिथिलता प्रदान करती हैं। प्रशुल्क नीति 2015 के अंतर्गत दरमानों के पिछले संशोधन में इस प्राधिकरण द्वारा 84,251.84 लाख रु. प्रति वर्ष 84,251.84 लाख रु. प्रति वर्ष था और प्रस्तावित दरमानों पर डीपीटी द्वारा आकलित तथा उक्त आदेश द्वारा अनुमोदित राजस्व 83,551.58 लाख रु. था। 700.26 लाख रु. के अंतर को (84,251.84 लाख रु. घटाएं 83,551.58 लाख रु.) इस प्राधिकरण द्वारा आरक्षित छोड़ दिया गया था। जिसे पत्तन को प्रशुल्क मदों और सोपाधिकताओं से देखना होगा जिसके लिए डीपीटी उस समय राजस्व कैप्चर नहीं कर सका। जैसा पहले बताया गया है प्रस्तावित प्रशुल्क मद से राजस्व 2016 के प्रशुल्क आदेश में आकलित एआरआर के भीतर है।

(vi). पत्तन ने यह कहते हुए एक टिप्पणी का प्रस्ताव किया है जब कभी कोई विशिष्ट दर उपलब्ध नहीं होगी उस तुल्य मद के कांडला के लिए निर्धारित दर तूना पत्तन पर भी लागू होगी। बशर्ते तूना पत्तन पर प्रदान की जारी सेवाएं/सुविधाएं कांडला के समान हों। डीपीटी द्वारा एक और टिप्पणी प्रस्तावित की है तूना पर सेवाएं प्रदान करने के अनुबंधन और शर्तें कांडला में प्रदान की जा रही तुलनीय सेवाओं/सुविधाओं के समान हैं। प्रस्तावित टिप्पणियां 2011 के इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमानों में तूना पत्तन के लिए यथा निर्धारित है अतः मौजूदा दरमानों में तूना पत्तन की दरों के लिए अलग से अध्याय निर्धारित करते समय अंतर्विष्ट करने के लिए अनुमोदित की जाती हैं।

(vii). (क). एकेबीटीपीएल ने डीपीटी द्वारा प्रस्तावित भंडारण प्रभारों पर आपत्ति की है। एकेबीटीपीएल ने तूना की भू-दरों के निर्धारण के लिए भू-मूल्यांकन रिपोर्ट पर सुविचार करने का विरोध किया है। एकेबीटीपीएल ने मत प्रकट किया है कि जिस भूमि के बाजार मूल्य पर सुविचार किया गया है औद्योगिक विकसित भूमि है जो तेना गांव में नहीं है बल्कि भशपर और किदना में है जो कांडला विशेष आर्थिक जोन के पीछे है और तूना टर्मिनल से 14-18 कि.मी. दूर है। जैसा पहले बताया गया है कि पत्तन ने यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान प्रस्ताव तूना पत्तन के कच्चे भूखंड के लिए भंडारण प्रभारों को प्रस्ताव करने के लिए ही है, इसलिए तूना पत्तन के लिए मूल्यांकक द्वारा दिये गए मूल्यांकन और एलएसी द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है। ये दरें प्रशुल्क नीति 2015 के सिद्धांतों के अनुपालन में दरमानों के सामान्य संशोधन की कार्गो संबंधी सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। इसलिए डीपीटी ने स्पष्ट किया है कि कच्चे भूखंड के भंडारण प्रभारों का प्रस्ताव करते समय एलपीजी 2014 को इसने लागू नहीं किया है। डीपीटी द्वारा दिये गए इस स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाता है। प्रशुल्क नीति, 2015 जिसके अंतर्गत यह प्रस्ताव दायर किया गया है और बाद की प्रशुल्क नीति 2018, प्रशुल्क नीति 2015 को प्रतिस्थापित करती है, महापत्तन न्यासों को यह शिथिलता प्रदान काती है कि वे आकलित अधिकतम एआरआर के भीतर दरमान तैयार कर सकते हैं। जैसा पहले बताया गया है, कच्चे भूखंड की प्रस्तावित दरों पर, इस अधिकरण द्वारा 2016 में अनुमोदित मौजूदा दरमानों के अनुसार लागू दरों में 72.21% की कमी आई है और इसलिए राजस्व आकलन अधिकतम एआरआर भीतर ही है।

(ख). एकेबीटीपीएल ने 26 जून 2012 को बल्क कार्गो टर्मिनल प्रचालन के लिए डीपीटी के साथ 30 वर्ष की अवधि के लिए एक रियायत करार (सीए) पर हस्ताक्षर किये हैं। सीए के भाग 9.1 (क) के अनुसार एकेबीटीपीएल द्वारा भूमि के लिए संदेय लाइसेंस शुल्क 81,23,400 रु. (अर्थात् 902,600 वर्ग मीटर x 0.75 रु. x 12 माह) है। सीए अनुबद्ध करता है कि भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क की राशि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रचलित दरमानों के अनुसार आकलित

की जायेगी। एकेबीटीपीएल ने बताया है कि सीए में 81.23 लाख रु. का लाइसेंस शुल्क 7.50 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर/ माह के लाइसेंस (भंडारण) शुल्क लागू करने पर बनता है जो तब तूना पत्तन पर प्रचलित दर थी। एकेबीटीपीएल का यह मत है कि एकेबीटीपीएल का सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना के लिए आवरित भूमि के लाइसेंस (भंडारण) शुल्क में कोई वृद्धि या तो डब्ल्यूपीआई सूचकांकन के 60% पर होगी या फिर बुनियादी लाइसेंस (भंडारण) शुल्क एलपीजी 2014 में दिये गए अनुसार 2% होगी जैसा रियायत करार के भाग 9.1 (क) में उल्लिखित है। एकेबीटीपीएल ने डीपीटी के पीपीपी मोड के अंतर्गत विकसित की जाने वाली कांडला पत्तन के तूना के निकट तेकरा के पास शुष्क बल्क टर्मिनल के लिए इस प्राधिकरण द्वारा 17 अगस्त 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी की अप्रेंट प्रशुल्क की अधिसूचना से उठे मुद्दों पर इस प्राधिकरण को अनुरोध किया है कि डीपीटी और एकेबीटीपीएल का मार्गदर्शन करें।

एकेबीटीपीएल द्वारा उठाये गए उक्त मुद्दों के संदर्भ में, यह बताया जाता है कि 17 अगस्त, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी के द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अप्रेंट प्रशुल्क के लिए लाइसेंस (भंडारण) शुल्क आकलन के लिए प्रशुल्क नीति 2015 में यथालागू 7.50 रु. प्रति 10 वर्ग मीटर प्रति माह पर विचार करने के कारणों और आधार पर उस आदेश के पैरा 11 (viii) (ग) में विस्तार से चर्चा की गई है। इस प्राधिकरण के समक्ष वर्तमान प्रस्ताव तूना पत्तन के लिए जून 2016 में अनुमोदित मौजूद दरमानों से पहले प्रचलित व्यवस्था के अनुसार एक अलग अध्याय के अंतर्गत दरों को अनुमोदित करने का है। इस प्राधिकरण को तूना पत्तन पर डीपीटी द्वारा संपत्ति के प्रयोग के लिए प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए कॉमन प्रयोक्ता आधार पर और न कि तूना पत्तन पर परिचालन कर रहे किसी वैयक्तिक प्रयोक्ता/बीओटी प्रचालक के लिए प्रतिबंधित, दर को अनुमोदित करना है। एकेबीटीपीएल द्वारा संदर्भित मामला डीपीटी और वैयक्तिक बीओटी प्रचालक अर्थात् एकेबीटीपीएल के बीच हुए सीए से प्रवाहित है। यह प्राधिकरण संबंधित पत्तन न्यास के वैयक्तिक प्रचालक/पट्टाधारक के बीच ही रियायत करार से उठने वाले मामले में हस्तक्षेप नहीं करता क्योंकि यह इसके अधिदेश से इतर है।

यह प्राधिकरण साफ तौर पर यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि डीपीटी द्वारा एकेबीटीपीएल को दी गई बल्क टर्मिनल परियोजना अप्रेंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत इस प्राधिकरण के 17 अगस्त, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी द्वारा नियत अप्रेंट प्रशुल्क पर आधारित है। डीपीटी और एकेबीटीपीएल दोनों ही एमओएस द्वारा जारी अप्रेंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अप्रेंट निर्धारण दिशानिर्देश 2008 के खंड 2.8 और उक्त आदेश के पैरा 11.1 के अनुसार नियत किया गया अप्रेंट प्रशुल्क डब्ल्यूपीआई में परिवर्तन के 60% की सीमा तक वार्षिक सूचकांकन के अधीन रहेगा। जब संशोधित पट्टा किराये अधिसूचित किये जाते हैं तो दिशानिर्देश 2008 में पीपीपी परियोजनाओं के निर्धारित अप्रेंट प्रशुल्क में वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अप्रेंट प्रशुल्क, तथापि, समिति को पूरा करने के लिए अप्रेंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के खंड 2.8 के अनुसार डब्ल्यूपीआई में परिवर्तन के 60% की सीमा तक वार्षिक सूचकांकन के पात्र है।

यहां यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) के अधीन एमओएस द्वारा गठित समिति ने सभी महापत्तन न्यासों को तंगहाल परियोजना पर एक रिपोर्ट दी है और ऐसी तंगहाल परियोजनाओं को उबारने के लिए एक तंत्र बनाया है। एमओएस द्वारा सभी महापत्तन न्यासों को जारी आईपीए समिति रिपोर्ट में अन्य मुद्दे भी हैं। आईपीए रिपोर्ट में निपटान गए मुद्दों में से एक सीए में लाइसेंस शुल्क उपबंधों से संबंधित है। डीपीटी और एकेबीटीपीएल, इसलिए, उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के संदर्भ में मामले का हल तलाश करें।

- (ग). जहां तक एकबीटीपीएल द्वारा संशोधित एलपीजी 2014 के अनुसार पीपीपी परियोजनाओं को यथा लागू डब्ल्यूपीआई के 60% पर तूना शुष्क बल्क टर्मिनल के लिए लाइसेंस (भंडारण) शुल्क में वृद्धि के लिए नई वृद्धि प्रणाली बनने के लिए डीपीटी को उपयुक्त निर्देश जारी करने के अनुरोध का संबंध है, यह उल्लेख करना है कि एक दर निकालने के लिए तूना शुष्क बल्क टर्मिनल के लिए लाइसेंस (भंडारण) शुल्क में वृद्धि के लिए नई वृद्धि प्रणाली बनने के लिए डीपीटी को निर्देश जारी करना इस प्राधिकरण के अधिदेश से इतर है। इस प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क पर वार्षिक प्रशुल्क वृद्धि के लिए वार्षिक वृद्धि के लिए लागू कारक प्रणाली अनुमोदित की जा रही है क्योंकि ऐसा महापत्तन न्यासों/बीओटी प्रचालक और यह प्राधिकरण उसी से शासित हैं।
- (viii). जहां तक प्रस्तावित दर की शासी सोपाधिकताओं का संबंध है, डीपीटी ने कांडला प्रभाग के लिए अनुसूची 2.5 में निर्धारित तथा निर्धारित सोपाधिकताओं को निर्धारित करने की वांछा की है। ऐसा है तो तूना पत्तन के लिए भंडारण प्रभागों की अनुसूची में अंतर्विष्ट किये जाते हैं।
- (ix). साधारणतया इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दर भारत के राजपत्र में दरमानों की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर प्रभावी होती है। तथापि, डीपीटी के न्यासी मंडल ने 28 मई, 2019 को हुई अपनी बैठक में संकल्प संख्या 22 में यह संकल्प किया कि तूना पत्तन के अलग प्रशुल्क को 11 अगस्त 2016 के पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वित किया जाए अर्थात् डीपीटी के दरमानों के पिछले सामान्य संशोधन की प्रभावी तारीख से/ इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पृथक प्रशुल्क को 11 अगस्त 2016 से प्रभावी किया जाता है और डीपीटी के वर्तमान दरमान में अंतर्विष्ट किया जाता है जो 30 सितंबर, 2019 तक वैध हैं।

15.1. परिणाम में और ऊपर दिए गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण डीपीटी के वर्तमान दरमान में तूना पत्तन के लिए निम्नलिखित दरों को अनुमोदित करता है:-

- (i). निम्नलिखित को अध्याय V – डीपीटी के मौजूदा दरमानों में तूना पत्तन की दर:

**“अध्याय V – तूना पत्तन की दर**

क्र.सं.	विवरण	उगाही यूनिट	विदेशगामी पोत (अमरीकी डॉलर में)	तटीय पोत (रु. में)
<b>क.</b>	<b>अनुसूची 1 – पत्तन देयताएं</b>			
1	10 जीआरटी वे उससे अधिक के पोतों (मछली पकड़ने की नावों को छोड़कर)	दर प्रति जीआरटी या उसका एक भाग	0.0978	1.3687
2	सेलिंग पोत 10 जीआरटी वे उससे अधिक के पोतों (मछली पकड़ने की नावों को छोड़कर)	दर प्रति जीआरटी या उसका एक भाग	0.0587	1.1732
<b>ख.</b>	<b>अनुसूची II – बर्थ किराया प्रभार</b>			
1	10 जीआरटी से अधिक के पोत	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसका एक भाग	0.0025	0.0391
<b>ग.</b>	<b>अनुसूची III – बीचिंग प्रभार</b>			
1	बीचिंग प्रभार	दर प्रति एनआरटी प्रति एमटीएच या उसका एक भाग	0.0196	0.3911
<b>घ.</b>	<b>लंगरगाह प्रभार</b>			
	सागरगामी मशीनीकृत बोदक पोत	--	--	--

	भीतरी लंगरगाह (पोत जीआरटी)	दर प्रति 1 घंटा या उसका एक भाग	0.0010	0.0255
<b>ड.</b>	<b>अनुसूची IV – घाटशुल्क प्रभार</b>			
<b>I.</b>	<b>तरल (बल्क में)</b>			
1	कच्चे तेल को छोड़कर बल्क में पीओएल उत्पाद	एम.टी. या उसका भाग	50.00	50.00
2	बंकर सहित अन्य तरल कार्गो	एम.टी. या उसका भाग	50.00	30.00
<b>II.</b>	<b>शुष्क कार्गो</b>			
1	सल्फर सहित उर्वरक और कच्चा माल	एम.टी. या उसका भाग	33.60	20.16
2	खाद्यन्न, उनाज दाले और तिलहन	एम.टी. या उसका भाग		
	(i). बल्क		15.00	9.00
	(ii). ब्रेक बल्क		9.00	5.40
3	सीमेंट और क्लिंकर	एम.टी. या उसका भाग	22.50	13.50
4	अयस्क और खनिज (हर प्रकार के)	एम.टी. या उसका भाग	16.88	10.13
5	ग्रेनाइट और मार्बल	एम.टी. या उसका भाग	22.50	13.50
6	धातुएं (फेरस/नान फेरस तथा धातु कबाड, पाइप, पिग लौह, कॉयल शीट व कोयला सहित)	एम.टी. या उसका भाग	37.50	22.50
7	पशु, कुक्कुट, भेड़ और बकरा सहित	प्रत्येक	6.52	3.91
8	पशु (उक्त को छोड़कर)	प्रत्येक	15.64	9.39
9	पशु उत्पाद अस्थि चूर्ण खल तथा चर्म	एम.टी. या उसका भाग	9.78	5.87
10	खली और चारा	एम.टी. या उसका भाग	15.00	9.00
11	रद्दी कागज और अखबारी कागज	एम.टी. या उसका भाग	30.00	18.00
12	निर्माण सामग्री और बालु	एम.टी. या उसका भाग	16.88	10.13
13	कोयला और कोक (जलावन सहित)	एम.टी. या उसका भाग	25.20	15.12
14	लकड़ी, टिम्बर और बांस	सीयू.एम.	30.00	18.00
15	जूट व जूट उत्पाद तथा कॉयर उत्पाद	एम.टी. या उसका भाग	22.50	13.50
16	कपास और कपास कबाड	एम.टी. या उसका भाग	22.50	13.50
17	लवण	एम.टी. या उसका भाग	15.00	9.00
18	शर्करा	एम.टी. या उसका भाग	15.00	9.00
19	एस्बस्टॉस	एम.टी. या उसका भाग	-	-
20	संश्लेषित रेजिन और काष्ठ लुग्दी	एम.टी. या उसका भाग	45.00	27.00
21	शस्त्र, गोला, बारूद विस्फोटक और रक्षा भंडार	एम.टी. या उसका भाग	97.50	58.50
22	शुष्क रसायन सोडा ऐश एचडीपीई आदि सहित	एम.टी. या उसका भाग	22.50	13.50

23	अन्य अनिर्दिष्ट सामान	एम.टी. या उसका भाग	52.50	31.50
च.	अनुसूची V – सामान्य कार्गो के लिए डंडारण प्रभार			
1	खुले स्थान के लिए	दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका भाग प्रति माह या उसका भाग (रु. में)	कच्चा भूखंड	पक्का भूखंड
	0 – 60 दिन		23.34	144.00
	61 – 90 दिन		46.68	288.00
	91 – 180 दिन		58.35	360.00
	180 दिन से अधिक		70.03	432.00
2	कवर्ड स्थान के लिए			
	0 – 60 दिन			279.00
	61 – 90 दिन			558.00
	91 – 180 दिन			697.50
	180 दिन से अधिक			837.00
3	ऑन बोर्ड टिम्बर भंडारण	दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका भाग प्रति माह या उसका भाग (रु. में)		1.96
छ.	अनुसूची VI – ट्राली किराया प्रभार	दर प्रति दिर या उसका भाग (रु. में)		19.55

#### सामान्य टिप्पणियां:

- (i). जब कभी कोई विशिष्ट दर उपलब्ध न हो, तो उसके समकक्ष मदों के लिए कांडला में निर्धारित दर लागू होगी बशर्ते तूना पत्तन पर प्रदान की जा रही संबंधित सेवाएं। सुविधाएं कांडला के समान ही हों।
- (ii). तूना पत्तन में प्रदान की जा रही सेवाओं के निबंधन और शर्तें वही होंगी जा तुलनात्मक सेवाओं के लिए कांडला में यथानिर्धारित हैं बशर्ते तुलनीय सेवाएं/सुविधाएं प्रदान की जा रही हो, नीचे दी जा रही हैं:-
  - (क). लाइसेंस (भंडारण) शुल्कों की गणना के प्रयोजन के लिए अवधि खुले और ढके हुए दोनों क्षेत्रों के लिए कार्गो के विराम की अवधि को ध्यान में रखते हुए गणना की जाएगी।
  - (ख). भंडारण स्थानों के लिए आवेदन पत्र केपीटी अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी की समानों के भंडारण से पहले देना होगा। भंडारण स्थानों का कोई अनाधिकृत अधिग्रहण शास्ति के रूप में दोगुने किराये के भुगतान के लिए देय होगा।
  - (ग). लाइसेंस (भंडारण) शुल्क अग्रिम रूप में अदा किए जाएंगे। दंडात्मक ब्याज, अध्याय 1 में 1.2 सामान्य निबंधन एवं शर्तें में बिंदु सं. (viii) (ख) में यथा निर्धारित, देय राशि पर प्रभार्य होगा परंतु उस तारीख से भुगतान नहीं करना होगा जब राशि देय हो जाती है से भुगतान की वास्तविक तारीख तक जो किसी भी स्थिति में 7 दिनों से अधिक नहीं होगी। यदि, किसी कारण से, भुगतान देय अधिग्रहण किए जाने की तारीख को देय राशि के दिन से 7 दिनों के बाद विलंब से भुगतान किया जाता है तो इसे अनाधिकृत माना जाएगा।

- (घ). आवरित किया गया स्थान केपीटी अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी से नोटिस प्राप्त होने पर खाली करना होगा ऐसा नहीं करने पर इसे अनाधिकृत अभिग्रहण माना जाएगा; और पत्तन प्राधिकारी अन्य कार्रवाई, जैसा ठीक समझा जाएगा, की जाएगी।
- (ङ). केपीटी के पास, किराया आधार पर आवरित, ऐसे स्थानों को पत्तन परिवहनों के हित में बिना पूर्ण नोटिस के वापस लेने का अधिकार होगा जो अधिग्रहीन नहीं हो/ खाली हो। ऐसे मामलों में, किराये में अनुपालित कटौती स्वीकार की जाएगी।
- (च). भंडारण प्रभारों की वसूली के प्रयोजन के लिए दिन की गणना 08.00 बजे से 08.00 तक होगी।
- (छ). यदि परिचालनात्मक क्षेत्र उपयोक्ताओं को किराये पर पट्टे पर दिया जाता है तो उसमें कंटेनरों पर भंडारण प्रभार/भंडारित कार्गो पर विलंबशुल्क दोबारा वसूल नहीं किया जाएगा।

(iii). बिल की कुल राशि को अगले उच्चतम रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा। ”

- (ii). मौजूदा अध्याय - V - डीपीटी के वर्तमान दरमानों में तूना/तेकरा स्थित एकेबीटीपीएल द्वारा प्रचालित शुष्क बल्क टर्मिनल पर डीपीटी द्वारा प्रदान की जा रही नौचालन संबंधी सेवाओं के प्रशुल्क का अध्याय V के रूप में पुनः संख्यांकित करना।
- (iii). अध्याय- I परिभाषाएं और सामान्य निबंधनों और शर्तों में डीपीटी के वर्तमान दरमानों में टिप्पणी संख्या (xv) को विलुप्त कर दिया जाए।

15.2. डीपीटी को उनके दरमानों में उपरोक्त उपबंधों को उपयुक्त रूप से अंतर्विष्ट करने की सलाह दी जाती है।

15.3. उक्त प्रभार 11 अगस्त, 2016 से प्रभावी होंगे, डीपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित, और उनकी वैधता डीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता के साथ सह-समाप्य होगी यानी 30 सितंबर, 2019 को। दिया गया अनुमोदन स्वतः ही व्यपगत हो जायेगा, तब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा इनका विशेष रूप से विस्तार नहीं कर दिया जाता।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./136/19]

अनुलग्नक

तूना पत्तन के 2011 आदेश के अनुसार दरें, 2016 आदेश के अनुसार दरें और डीपीटी द्वारा तूना पत्तन के लिए अब प्रस्तावित दरों तथा 2016 आदेश और 2011 आदेश के संदर्भ से प्रतिशत वृद्धि /कमी की तुलनात्मक स्थिति														
क.सं.	विवरण	यूनिट	2011 आदेश मे अनुमोदित दरें (आदेश संख्या टीएएमपी/18/2019-केपीटी दिनांक 18.01.2011)		2016 आदेश मे अनुमोदित दरें (आदेश संख्या टीएएमपी/61/2016-केपीटी दिनांक 21.06.2016) *		13 मार्च 2018 के प्रस्ताव में डीपीटी द्वारा अब प्रस्तावित दरें।		2016 (सानी मौज़दा) के अनुसार % वृद्धि / कमी 2011 के संदर्भ में		2011 के संदर्भ से प्रस्तावित दर में वृद्धि % /कमी		2016 के संदर्भ से (यानी मौज़दा) प्रस्तावित दर में % वृद्धि/ कमी	
			विदेशगामी पोत (अमरीकी डॉलर में)	तटीय पोत (रु. में)	विदेशगामी पोत (अमरीकी डॉलर में)	तटीय पोत (रु. में)	विदेशगामी पोत (अमरीकी डॉलर में)	तटीय पोत (रु. में)	तटीय पोत		तटीय पोत		तटीय पोत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7-5)/5		11=(9-5)/5		12=(9-7)/7	
क.सं.	अनुसूची 1 – पत्तन देयताएं													
1	10 जीआरटी वे उससे अधिक के पोतों (मछली पकड़ने की नावों को छोड़कर)	दर प्रति जीआर टी प्रति घंटा या उसका एक भाग	0.0750	1.0500	0.4255	10.5175	0.0978	1.3687	901.67%		30.35%		-86.99%	
2	सेलिंग पोत 10 जीआरटी वे उससे अधिक के पोतों (मछली पकड़ने की नावों को छोड़कर)	दर प्रति जीआर टी प्रति घंटा या उसका एक भाग	0.0450	0.9000	0.4255	10.5175	0.0587	1.1732	1068.61%		30.36%		-88.85%	
ख.	अनुसूची II – बर्थ किराया प्रभार													
1	10 जीआरटी तक पोत	दर प्रति जीआर टी प्रति घंटा या उसका एक भाग	Free	Free										



2	10 जीआरटी से अधिक के पोत	दर प्रति जीआर टी प्रति घंटा या उसका एक भाग	0.0019	0.03	0.0092	0.23	0.0025	0.0391	666.67%		30.33%		-83.00%	
ग.	<b>अनुसूची III – बीचिंग प्रभार</b>													
1	बीचिंग प्रभार	दर प्रति जीआर टी प्रति घंटा या उसका एक भाग	0.015	0.3	0.105	2.6066	0.0196	0.3911	768.87%		30.37%		-85.00%	
	लंगरगाह प्रभार													
	सागरगामी मशीनीकृत बोदक पोत													
	भीतरी लंगरगाह (पोत जीआरटी)	दर प्रति 1 घंटा या उसका एक भाग	-	-	0.001	0.0255	0.001	0.0255	-		-		0.00%	
घ.	<b>अनुसूची IV – घाटशुल्क प्रभार</b>													
क.	<b>तरल (बल्क में)</b>													
1	कच्चे तेल को छोड़कर बल्क में पीओएल उत्पाद	एम.टी. या उसका भाग	15.00	9.00	50.00	50.00	50.00	50.00	455.56%		455.56%		0.00%	
2	बंकर सहित अन्य तरल कार्गो	एम.टी. या उसका भाग	15.00	9.00	50.00	30.00	50.00	30.00	233.33%		233.33%		0.00%	
ख.	<b>शुष्क कार्गो</b>													
1	सल्फर सहित उर्वरक और	एम.टी.	15.00	9.00	33.60	20.16	33.60	20.16	124.00%		124.00%		0.00%	

	कच्चा माल	या उसका भाग												
2	खाद्यन्न, उनाज दाले और तिलहन	एम.टी. या उसका भाग												
	(i). बल्क		7.50	4.50	15.00	9.00	15.00	9.00	100.00%		100.00%		0.00%	
	(ii). ब्रेक बल्क				9.00	5.40	9.00	5.40	20.00%		20.00%		0.00%	
3	सीमेंट और क्लिंकर	एम.टी. या उसका भाग	12.00	7.20	22.50	13.50	22.50	13.50	87.50%		87.50%		0.00%	
4	अयस्क और खनिज (हर प्रकार के)	एम.टी. या उसका भाग	11.25	6.75	16.88	10.13	16.88	10.13	50.07%		50.07%		0.00%	
5	ग्रेनाइट और मार्बल	एम.टी. या उसका भाग	15.00	9.00	22.50	13.50	22.50	13.50	50.00%		50.00%		0.00%	
6	घातुएं (फेरस/नान फेरस तथा धातु कबाड, पाइप, पिग लौह, कॉयल शीट व कोयला सहित)	एम.टी. या उसका भाग	15.00	9.00	37.50	22.50	37.50	22.50	150.00%		150.00%		0.00%	
7	पशु, कुक्कुट, भेड़ और बकरा सहित	प्रत्येक	5.00	3.00	15.00	9.00	6.52	3.91	200.00%		30.33%		-56.56%	
8	पशु (उत्त को छोड़कर)	प्रत्येक	12.00	7.20	30.00	18.00	15.64	9.39	150.00%		30.42%		-47.83%	
9	पशु उत्पाद अस्थि चूर्ण खल तथा चर्म	एम.टी. या उसका	7.50	4.50	15.00	9.00	9.78	5.87	100.00%		30.44%		-34.78%	

		भाग												
10	खली और चारा	एम.टी. या उसका भाग	7.50	4.50	15.00	9.00	15.00	9.00	100.00%		100.00%		<b>0.00%</b>	
11	रद्दी कागज़ और अखबारी कागज़	एम.टी. या उसका भाग	13.50	8.10	30.00	18.00	30.00	18.00	122.22%		122.22%		<b>0.00%</b>	
12	निर्माण सामग्री और बालु	एम.टी. या उसका भाग	11.25	6.75	16.88	10.13	16.88	10.13	50.07%		50.07%		<b>0.00%</b>	
13	कोयला और कोक (जलावन सहित)	एम.टी. या उसका भाग	12.00	7.20	25.20	15.12	25.20	15.12	110.00%		110.00%		<b>0.00%</b>	
14	लकड़ी, टिम्बर और बांस	एम.टी. या उसका भाग	10.50	6.30	30.00 Cu. m.	18.00 Cu. m.	30.00 Cu. m.	18.00 Cu. m.	185.71%		185.71%		<b>0.00%</b>	
15	जूट व जूट उत्पाद तथा कॉयर उत्पाद	एम.टी. या उसका भाग	10.50	6.30	22.50	13.50	22.50	13.50	114.29%		114.29%		<b>0.00%</b>	
16	कपास और कपास कबाड	एम.टी. या उसका भाग	9.00	5.40	22.50	13.50	22.50	13.50	150.00%		150.00%		<b>0.00%</b>	
17	लवण	एम.टी. या उसका भाग	2.50	1.50	15.00	9.00	15.00	9.00	500.00%		500.00%		<b>0.00%</b>	

18	शर्करा	एम.टी. या उसका भाग	7.50	4.50	15.00	9.00	15.00	9.00	100.00%		100.00%		0.00%	
19	एस्बस्टॉस	एम.टी. या उसका भाग	9.00	4.50	-	-	-	-	-		-		-	
20	संक्षेपित रेजिन और काष्ठ लुग्दी	एम.टी. या उसका भाग	15.00	9.00	45.00	27.00	45.00	27.00	200.00%		200.00%		0.00%	
21	शस्त्र, गोला, बारूद विस्फोटक और रक्षा भंडार	एम.टी. या उसका भाग	18.00	10.80	97.50	58.50	97.50	58.50	441.67%		441.67%		0.00%	
22	शुष्क रसायन सोडा ऐश एचडीपीई आदि सहित	एम.टी. या उसका भाग	10.50	6.30	22.50	13.50	22.50	13.50	114.29%		114.29%		0.00%	
23	अन्य अतिरिष्ट सामान	एम.टी. या उसका भाग	15.00	9.00	52.50	31.50	52.50	31.50	250.00%		250.00%		0.00%	
ड.	अनुसूची V – सामान्य कार्गो के लिए डांडारण प्रभार				कच्चा भूखंड	पक्का भूखंड	कच्चा भूखंड	पक्का भूखंड	कच्चा भूखंड	पक्का भूखंड	कच्चा भूखंड	पक्का भूखंड	कच्चा भूखंड	पक्का भूखंड
1	खले स्थान के लिए													
	0 – 60 दिन	"दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका भाग	7.50		84.00	144.00	23.34	144.00	1020.00%	1820.00%	211.20%	1820.00%	-72.21%	0.00 %

		प्रति माह या उसका भाग (रु. में)"												
	61 – 90 दिन				168.00	288.00	46.68	288.00	2140.00%	3740.00%	522.40%	3740.00%	-72.21%	0.00%
	91 – 180 दिन				210.00	360.00	58.35	360.00	2700.00%	4700.00%	678.00%	4700.00%	-72.21%	0.00%
	180 दिन से अधिक				252.00	432.00	70.03	432.00	3260.00%	5660.00%	833.73%	5660.00%	-72.21%	0.00%
2	क्वर्ड स्थान के लिए													
	0 – 60 दिन		48.00		279.00		279.00		481.25%		481.25%	481.25%	0.00%	
	61 – 90 दिन				558.00		558.00		1062.50%		1062.50%	1062.50%	0.00%	
	91 – 180 दिन				697.50		697.50		1353.13%		1353.13%	1353.13%	0.00%	
	180 दिन से अधिक				837.00		837.00		1643.75%		1643.75%	1643.75%	0.00%	
3	ऑन बोर्ड टिम्बर भंडारण	दर प्रति 10 वर्ग मीटर या उसका भाग प्रति माह या उसका भाग (रु. में)	1.50		--		1.96		--		30.67%	30.67%	--	
च.	अनुसूची VI – ट्राली किराया प्रभार	दर प्रति दिर या उसका भाग (रु. में)	15.00		--		19.55		--		30.33%	30.33%	--	
* 2016 आदेश में डीपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित एक टिप्पणी प्रस्तावित की गई थी कि कांडला पत्तन की दरे तूना पोर्ट भी लागू होंगी। तदनुसार, उक्त सारणी में कांडला भूमि के लिए लागू दर को 2016 दरों के साथ तुलना के लिए तूना पत्तन के अंतर्गत दर्शाया गया है।														
आकलित % वृद्धि /कमी तटीय दर पर आधारित है जो तूना पत्तन से संबंधित है।														

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****NOTIFICATION**

Mumbai, the 3rd July, 2019

**No.TAMP/20/2018-DPT.**—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the Deendayal Port Trust (DPT) for incorporating a separate tariff schedule for Tuna port as Schedule V in the existing Scale of Rates (SOR) of DPT, as in the Order appended hereto.

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****Case No.TAMP/20/2018-DPT****Deendayal Port Trust**

- - -

**Applicant****QUORUM**

- (i). Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri Rajat Sachar, Member (Economic)

**ORDER**(Passed on this 14<sup>th</sup> day of June 2019)

This case relates to the proposal received from Deendayal Port Trust (DPT) for incorporating a separate tariff schedule for Tuna port as Schedule V in the existing Scale of Rates (SOR) of DPT.

2.1. This Authority had vide its Order No.TAMP/18/2016-KPT dated 21 June 2016 disposed of the general revision of SOR proposal of DPT and approved revised SOR. The revised SOR and Performance Standards approved by this Authority vide Order dated 21 June 2016, were notified vide Gazette No.287 dated 12 July 2016. Subsequently, a speaking order was notified vide Gazette No.319 dated 10 August 2016. The SOR came into force after expiry of 30 days from the date of notification of the SOR and Performance Standards in the Gazette of India i.e. from 11 August 2016. The validity of SOR is prescribed till 31 March 2019. The validity of said existing SOR of DPT is extended upto 30 September 2019 and communicated to all Major Port Trusts including DPT vide our letter No.TAMP/39/2005-Misc. dated 29 March 2019.

2.2. The DPT has now vide its letter dated 13 March 2018 submitted its proposal to incorporate a separate tariff Schedule for Tuna Port as Schedule V in the existing SOR of DPT. The main points made by DPT are summarized below:

- (i). Earlier there used to be separate SOR for Tuna Port and the rates were fixed keeping in view the type of crafts, nature of cargo being handled, draft requirement etc. However, in the revision in the SOR of DPT (w.e.f. 11 August 2016), under Chapter I - General Terms and Condition No.1.2, note (xv) stipulates as follows:

*“Kandla rates shall be applicable to Tuna port.”*

This has resulted into exorbitant increase in port charges leviable at Tuna.

- (ii). A representation dated 09 September 2016 was received from Salaya Sailing Vessels Owners' Association (SSVOA) regarding Review of Port Charges of Tuna Port of DPT. The Association has stated that as per the new SOR, different types of port charges have increased by about 22% to 36% for other vessels except Indian Sailing Vessels (Indian Country Craft). Port charges have increased for sailing vessels upto 700%, which is injustice to the poor Indian Sailing Vessels.
- (iii). Further, the Association has pleaded that such high charges are not affordable by the poor industry and this will impact the trade as well as Indian Sailing Vessels Industry.
- (iv). TAMP had also forwarded the representation of SSVOA vide letter No.TAMP/18/2016-KPT dated 12 September 2016 for comments of DPT.

[We have, however, not heard from the DPT in this regard.]

- (v). M/s.Adani Kandla Bulk Terminal Private Limited (AKBTPL) has also represented on applicability of Kandla Rates to Tuna rates and hence exorbitant hike in License Fee payable. M/s.AKBTPL has represented that there is steep increase of 2700% in license fee due to applicability of Kandla rate to Tuna rate, which put their facilities into unviable propositions.

- (vi). TAMP vide letter No.TAMP/42/2009-KPT dated 21 September 2016, had forwarded a copy of representation received from the AKBTPL dated 16 August 2016 on deletion of Chapter-V of the then existing SOR relating to rates for Tuna port as proposed by the DPT and had requested to file a suitable proposal towards rental for the lands at Tuna port following the applicable Guidelines. Again TAMP vide email dated 10 October 2017 had forwarded copy of email dated 27 September 2017 received from M/s.AKBTPL on the same matter, requesting to file a suitable proposal towards rentals for lands at Tuna port following the applicable Guidelines.
- (vii). It is justified to review of SOR for Tuna Port on the following grounds:
- There has been increase to the tune of about 200% in wharfage charges, 150% in Berth Hire Charges and 500% in Port Dues for Tuna Port, which is exorbitantly high.
  - No expenditure is incurred towards dredging at Tuna by DPT.
  - Bare minimum staff is posted at Tuna, as such, the cost of manpower is very less.
  - Livestock is handled at Tuna which hardly cause any damage to the wharf etc.
  - Livelihood of the village of Tuna, Vandi and other nearby village is dependent upon export of Livestock from Tuna.
  - Mechanized craft owners are not so rich and are dependent upon loans from Bank / Financial Institutes.
- (viii). Accordingly, a Committee comprising of Traffic Manager, Deputy Conservator, Chief Engineer and Financial Advisor and Chief Accounts Officer had been constituted for reviewing the SOR for Tuna Port.
- (ix). The Committee in its meeting held on 22 November 2016 (copy furnished as Annexure-A) had expressed that DPT is not incurring any expenditure on dredging or navigational aids for Tuna Port and the rates prescribed for DPT may not be applied to Tuna Port.
- (x). Regarding Vessel Related Charges of Tuna Port, the Committee, after deliberation, decided that all Vessel Related Charges will be increased from old rates, which were approved in 2011, with an appropriate escalation with 100% Wholesale Price Index (WPI) and the rate shall be fixed accordingly.
- (xi). Regarding Cargo Related Charges of Tuna Port, the Committee discussed that DPT has invested considerable amount on creation of infrastructural facilities at that port such as roads, berth, barge jetty, backup area, lighting, etc. and as such reducing the Cargo Related Charges is not appropriate. However, as requested by port users viz. M/s.SSVOA, a reduced rate for 'livestock' and other cargo being handled by country craft be considered favorably and may be worked out based on escalation to be given to the 2011 rate.
- (xii). Further, the Committee recommended that the storage charges may be bifurcated into two categories viz. Pucca Plots and Kutchha Plots. For Pucca plots the rate applicable to Kandla Port will apply and for Kutchha Plots, the rate will be as per latest valuation given by the Valuer for Tuna Port area and approved by the Land Allotment Committee (LAC) in its meeting held on 20 January 2016. The recommendation of the LAC to consider the highest rate arrived at by the valuer is given in the following table:

Sr. No.	Particulars	CRZ Zones	Suitable for purpose	Developed / Undeveloped	High Tide / Creek area	Valuation	(-) less (25%) for lease hold land	Lease rent @ 6% of final valuation amount (₹) per M <sup>2</sup>
1	Land on east side of approach road leading to Barge Handling jetty	CRZ-III	Salt production, CFS, Tank farms Industries, warehouses	Undeveloped but having approach from 10 km road	Open undeveloped land	₹.2,645/-	983.75	119.03

	at Tuna (from NH no. 8A to Tuna in length of 10 kms)							
2	Land beyond half kilometer from the bank of creek	CRZ III	Suitable for warehouses, salt production CFZ Tank Farms	Undeveloped	Open land	₹.2,300/-	725.00	103.50
3	Land within half kilometer from the Creek of Barge Handling, jetty having no waterfront	CRZ-II	Suitable for warehouses, CFZ Tank Farms	Undeveloped	High tide area	₹.1,955/-	466.25	87.98
4	Land having waterfront and upto half kilometer from the Barge Handling Jetty i.e. on North side	CRZ-I	Suitable for jetty, Logistic operation & CFZ	Undeveloped	High tide area	₹.1,725/-	293.75	77.63 #

[# ₹84.03 proposed by DPT is arrived by the port by taking ₹77.63 and applying 2% escalation per annum from 2013 to 2016.]

[The DPT has subsequently vide its letter dated 11 April 2018 clarified that while proposing storage charges for Kutchha plots of Tuna Port, reliance is placed only for determining the rates on latest land valuation given by valuer under amended LPG, 2014. However, the proposed rate is covered under cargo related charges under Tariff Policy, 2015.]

- (xiii). The port has stated that License fee for land at Tuna, payable by AKBTPPL was ₹9.00 per sq. mtr. p.a. as per 2011 Order. This had increased to ₹302.40 per sq. Mtr. p.a. on account of Revision of SOR w.e.f. 11 August 2016. Now, as per the recommendation of the Committee, the license fee is pitched at ₹84.03 per sq. Mtr. p.a. The above figures in tabular form is placed as below:

(Total Area of 1066345.007 Sq. mtr.)

License fee before Revision of SOR as per 2011 SOR	License fee as per Revision of SOR as per 2016 SOR	Rates recommended by Committee (as on 2016)
Per sq. mtr. p.a.	Per sq. mtr. p.a.	Per sq. mtr. p.a.
9.00 #	302.40 @	84.03 \$

- (xiv). The financial implication of reduced rates applicable at Tuna Port will be approximately ₹129.53 lakhs (i.e. reduction) in revenue from Cargo related and Vessel related charges. As regards License fees recoverable from M/s.AKBTPPL, since same has not been considered in ARR as per Tariff Guidelines, 2015, being Public Private Partnership (PPP) project, hence there is no financial implication.

[As per clause 2.9 of Working Guidelines issued by TAMP, the Major Port Trusts need to make detailed working of revenue estimation indicating each of the tariff items in the proposed SOR for corresponding traffic as in clause 2.8 above and establish itself that the



sum of the revenue so determined from all the tariff items in the SOR is within the ceiling of the indexed ARR determined in clause 2.7. above duly certified by a practicing Chartered Accountant/ Cost and Management Accountant. Thus, the TAMP Guidelines do not require port to estimate revenue from Licence fees.

The ARR estimated by the DPT in the last tariff revision under Tariff Policy 2015 for Licence (storage) fees is ₹24.11 lakhs. The total revenue estimated at ₹83,551.58 lakhs includes Licence (storage) fees then proposed by DPT.]

(xv). The proposal was placed before the Board in its meeting held on 26 December 2017 and the Board of Trustees of DPT has approved the following:

(a). To add a separate tariff rate for Tuna Port as Schedule V of the Scale of Rate of DPT furnished as Annexure – D and to obtain approval of TAMP.

(b). To rename existing Chapter V as Chapter VA.

2.3. To summarise, the DPT has proposed for incorporation of following Chapter V – Rates for Tuna Port in the existing SOR of DPT:

#### CHAPTER V - RATE FOR TUNA PORT

Sr. No.	Particulars		Foreign Going Vessel (in US \$)	Coastal Vessel (in ₹)
<b>A.</b>	<b>Schedule 1 - Port Dues</b>			
1	Vessels of 10 GRT & Upwards (except fishing boats)	Rate per GRT or part thereof	0.0978	1.3687
2	Sailing Vessels of 10 GRT & Upwards (except fishing boats)	Rate per GRT or part thereof	0.0587	1.1732
<b>B.</b>	<b>Schedule II - Berth Hire Charges</b>			
1	Vessels above 10 GRT	Rate per GRT per hour or part thereof	0.0025	0.0391
<b>C.</b>	<b>Schedule III - Beaching Charges</b>			
1	Beaching Charges	Rate per NRT per MTH or part thereof	0.0196	0.3911
	<b>Anchorage Charges</b>			
	Sea going mechanically propelled vessels			
	(a). Kandla OTB		*	*
	(b). Inner Anchorage (per GRT)	Rate per 1 hour or part thereof #	0.0010	0.0255
			<b>Foreign Going Vessel (in ₹)</b>	<b>Coastal Vessel (in ₹)</b>
<b>D.</b>	<b>Schedule IV - Wharfage charges</b>			
<b>A.</b>	<b>Liquid (in bulk)</b>			
1	POL products in bulk other than crude oil	M.T. Or part thereof	50.00	50.00

2	Other liquid cargo including bunkers	M.T. Or part thereof	50.00	30.00
B.	Dry Cargoes			
1	Fertilizer and raw material including sulphur	M.T. Or part thereof	33.60	20.16
2	Foodgrains, cereals, pulses and oilseeds	M.T. Or part thereof		
	(i). Bulk		15.00	9.00
	(ii). Break Bulk		9.00	5.40
3	Cement and clinker	M.T. Or part thereof	22.50	13.50
4	Ores and minerals (in all forms)	M.T. Or part thereof	16.88	10.13
5	Granites and marbles	M.T. Or part thereof	22.50	13.50
6	Metals (Ferrous/non-ferrous & metals scrap including pipes, pig iron, coil sheet & cokes.	M.T. Or part thereof	37.50	22.50
7	Animals including chicken, sheep & goats	Each	6.52	3.91
8	Animals (other than above)	Each	15.64	9.39
9	Animal products, bone meal, hides and skin	M.T. Or part thereof	9.78	5.87
10	Oil cakes and fodder	M.T. Or part thereof	15.00	9.00
11	Waste paper and newsprint	M.T. Or part thereof	30.00	18.00
12	Construction material and sand	M.T. Or part thereof	16.88	10.13
13	Coal and coke (including firewood)	M.T. Or part thereof	25.20	15.12
14	Wood, timber and bamboo	M.T. Or part thereof **	30.00	18.00
15	Jute & jute products and coir products	M.T. Or part thereof	22.50	13.50
16	Cotton including cotton waste	M.T. Or part thereof	22.50	13.50
17	Salt	M.T. Or part thereof	15.00	9.00
18	Sugar	M.T. Or part thereof	15.00	9.00
19	Asbestos	M.T. Or part thereof	-	-
20	Synthetic resin and wood pulp	M.T. Or part thereof	45.00	27.00
21	Arms, ammunition, explosives and defence stores	M.T. Or part thereof	97.50	58.50

22	Dry chemicals including soda ash, HDPE, etc.	M.T. Or part thereof	22.50	13.50
23	Other unspecified goods	M.T. Or part thereof	52.50	31.50
<b>E.</b>	<b>Schedule V - Rental fees</b>			
1	For open space	Rate per 10 sq. Mtr. or part thereof per month or part thereof (in ₹)		
	(i) Kutchha Plots			84.03
	(ii) Pucca Plots			432.00
2	For covered space			837.00
3	Storage of timber on board	Rate per 10 sq. Mtr. or part thereof per day or part thereof (in ₹)		1.96
<b>F.</b>	<b>Schedule VI - Trolley Hire Charges</b>	Rate per day or part thereof (in ₹)		19.55

[# The port has not prescribed unit of levy for Anchorage charges for Inner Anchorage for Tuna port. Since the rate proposed for Anchorage charges for Inner Anchorage for Tuna port is same as rate proposed for Kandla land in SOR of 2016 Order under schedule 3.3 – Schedule of Anchorage charges, same unit of levy is proposed in above table.

\* As regards to Anchorage charges for Kandla OTB, DPT has subsequently vide its email dated 20 November 2018 clarified that same may be treated as NIL.

\*\* As regards to Wharfage charges for Wood, timber and bamboo, DPT has subsequently vide its email dated 30 November 2018 clarified that unit of levy for the said item may be read as Cu. M. as approved in 2016 Order instead of M.T. Or part thereof.]

2.4. In this backdrop, the DPT has requested to approve the proposed SOR for Tuna Port at Chapter V as given in para No.2.3 above. Consequently, the existing Chapter V relating to tariff for Marine related services provided by DPT at Dry bulk terminal operated by AKBTPPL at Tuna / Tekra is proposed to be renamed as Chapter VA.

3.1. The DPT has furnished a copy of the Minutes of the Meeting of the Committee to review the SOR of Tuna Port and lease rent at Tuna Port held on 22 November 2016, Minutes of the Meeting of the LAC held on 20 January 2016 for fixation of rate structure of Tuna Land alongwith a copy of the Land Valuation Report (year 2012) of port estate at Tuna Port, a copy of the Board Approval dated 26 December 2017 and a copy of the draft Chapter - V - Rate for Tuna Port for insertion in the existing SOR of DPT.

3.2. It is relevant here to state that in the LAC minutes dated 20 January 2016 in the first para it is recorded that the LAC recommended that the 2012 valuation (report furnished in 2013) may be returned back to the Valuer for review, particularly considering the differences between Leasehold Land and Freehold Land. Accordingly, the matter was referred by DPT to the valuer vide DPT letter dated 28 December 2015. The LAC minutes states that the valuer has submitted the revised valuations Report on 19 January 2016. There is no further mention of the 2016 valuation report. Moreover, from the LAC minutes it is seen that the valuation done in the year 2012 (report furnished in 2013) is considered by the LAC. The 2012 valuation report is furnished by the DPT. The DPT has not furnished a copy of revised valuations report dated 19 January 2016.

4.1. It is relevant here to mention that, prior to existing SOR of DPT approved vide Order No.TAMP/18/2016-DPT dated 21 June 2016, the then SOR prescribed separate schedule of rates in respect of vessel related charges and wharfage related charges for Tuna port.

4.2. In the said last revision of SOR, the DPT had done away with a separate schedule of rates for Tuna port. Instead, the port had proposed to insert a note stating that the tariff applicable for Kandla port is applicable for Tuna Port also as against separate schedule of rates for Tuna port in the pre-revised SOR justifying that Services provided at Tuna port are at par with Kandla. The DPT responded that Tuna port has been provided with all the infrastructural facilities like road and rail connectivity, etc. and DPT had confirmed

that the services, infrastructure, equipment and facilities provided at Tuna are comparable to those rendered at Kandla division. Subsequently, the DPT has also stated that the revenue impact of the proposed applicability of Kandla port rates to Tuna port has been captured in the revenue estimates. Based on the justification and clarification furnished by the port, the note proposed by DPT about applicability of Kandla rates to Tuna port was approved in the Order No.TAMP/18/2016-KPT dated 21 June 2016 as note No.1.2 (xv) under General Terms and Conditions.

4.3. The DPT has now proposed for separate Schedule of Rates for Tuna Port.

5. On perusal of the DPT proposal dated 13 March 2018, the DPT was requested vide our letter dated 27 March 2018 to furnish information / clarifications on few points by 06 April 2018. The DPT vide its letter dated 11 April 2018 has furnished its reply, after a reminder. A summary of information / clarifications sought by us and reply furnished by DPT is tabulated below:

Sr. No.	Information / clarification sought by TAMP	Reply of DPT
(i).	<p>(a). The subject proposal of DPT seeks approval for separate rates proposed for Vessel Related Charges, Cargo Related Charges and Miscellaneous charges as well as rental for Tuna port. As DPT is well aware, the revision of Vessel Related Charges, Cargo Related Charges and Miscellaneous charges are governed by the Tariff Policy 2015. Whereas, for fixation of revised rental for Kutchha plots and Pucca plots, the port has followed Amended Land Policy Guidelines (LPG), 2014 and has furnished Land Valuation Report, Minutes of meeting of the LAC and approval of the Board of Trustees of DPT which are pre-requisite for revision of rentals under the amended LPG, 2014.</p> <p>(b). With reference to the above proposal of DPT clubbing the rates proposed for Vessel Related Services, Cargo Related Services and Miscellaneous Services governed by the Tariff Policy 2015 with fixation of rentals governed under amended LPG, 2014, it is relevant to state that both these guidelines prescribe different methodology for fixation of rates. More pertinently, the periodicity of revision of Vessel Related Charges, Cargo Related Charges and Miscellaneous charges under Tariff Policy 2015 is every three years. The validity of existing SOR approved by the Authority vide Order No.TAMP/18/2016-KPT dated 21 June 2016 is till 31 March 2019. The DPT has proposed insertion of the proposed rate for Tuna port in existing SOR under Chapter – V which will, therefore, be valid till 31 March 2019. However, as regards revision of rentals, as per Clause 13 (c) of the amended LPG, 2014 revision of SOR (rental) is due once in every five years.</p> <p>(c). Another relevant part is on the annual escalation. As per note (xviii) (a) and (b) under Chapter - 1.2 - General terms and conditions, of existing SOR of DPT, which flows from Clause 2.8, 2.9 and 3.2 of the Tariff Policy 2015, the rates prescribed in the existing SOR are subject to 100% WPI escalation subject to achievement</p>	<p>In the earlier General Revision of SOR approved by TAMP vide its Order No.TAMP/61/2009-KPT dated 18.01.2011, there was a separate Chapter i.e. Chapter – V Rates for Tuna port, which included following Schedules:</p> <p>Schedule – I : Port Dues</p> <p>Schedule – II : Berth Hire Charges</p> <p>Schedule – III : Beaching Charges</p> <p>Schedule – IV : Wharfage Charges</p> <p>Schedule – V : Rental Fees</p> <p>Schedule – VI : Trolley Hire Charges</p> <p>The aforesaid rates were approved by the Authority following the principles of Tariff Guidelines, 2005.</p> <p>In the present proposal, while proposing the Storage Charges Rates for Kutchha plot of Tuna Port, only for determining the rates, reliance was made on latest valuation given by the Valuer for Tuna port area and approved by the LAC. However same is proposed and covered under Cargo related services of the General revision of SOR following the principles of Tariff Guidelines, 2015. Hence there is no clubbing of the provision of amended LPG, 2014 in proposing the Storage charges rates for Kutchha plot of Tuna port and therefore compliance of the provisions of amended LPG, 2014 is not required.</p> <p>It is to state that proposal for revision of Storage charges rates for Kutchha plot of Tuna port is covered under Cargo related services i.e., Storage space is to be allotted for storage of Cargo and charges shall be levied on the basis of stay of cargo, and therefore same is not allotment of land for Lease &amp; License basis as per LPG, 2014. Hence proposed Storage charges rates for Kutchha plot at Tuna are not covered under LPG, 2014, instead same is covered under the General</p>

	<p>of Performance Standards notified by the Authority. Whereas, under amended LPG, 2014, the port based on approval of Board of Trustees of the port can seek minimum 2% annual escalation in the rentals.</p> <p>(d). In view of the above distinction in the Tariff Policy 2015 and amended LPG, 2014, the DPT to clarify as to whether the proposal of DPT of clubbing the proposed rental of Tuna port in the general SOR will comply with the provision of amended LPG, 2014.</p>	revision of SOR following the principles of Tariff Guidelines, 2015 and hence same cannot be delinked.
(ii).	<p>The DPT may consider to delink the proposal for revision of rental for Tuna port from the general revision of SOR of Tuna port and file a separate proposal in this regard. In fact, even the Visakhapatnam Port Trust (VPT) had filed a proposal delinking License fee (Storage charge) based on the area earlier forming part of the general SOR under Tariff Guidelines 2005 to License fee following LPG, 2014 on issue of LPG, 2014 by the Ministry of Shipping (MOS). The Authority has accordingly, based on proposal of VPT approved Order No.TAMP/48/2014-VPT dated 15 January 2016 in this regard under LPG, 2014.</p>	
(iii).	<p>In light of the above points, the DPT is requested to furnish its clarification and respond positively by 06 April 2018.</p>	<p>Hence, TAMP, is once again requested to kindly approve the proposal SOR for Tuna Port, placed as Annexure – D of the proposal sent vide this office letter no.FA/COST/92 dated 13.03.2018, as per Section 48, 49 &amp; 50 of the MPT Act, 1963.</p>

6. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the proposal of DPT dated 13 March 2018 was forwarded vide our letter dated 18 April 2018 to the concerned users/ user organisations as suggested by DPT vide its e-mail dated 20 March 2018 seeking their comments. We have not received any comments from any users / user organisations except AKBTPPL vide its email dated 7 May 2018. The comments received from the AKBTPPL was forwarded to the DPT as feedback information. The DPT has responded to the comments of Adani Kandla Bulk Terminal Private Limited (AKBTPL) vide its email dated 21 May 2018.

7. The DPT while furnishing comments on comments of AKBTPPL has given reference to TAMP letter No.TAMP/42/2009-KPT dated 21 September 2016 forwarding representation dated 16 August 2016 of AKBTPPL and has stated that the TAMP has requested DPT to file the proposal for revision of lease rent for lands at Tuna. In this regard following factual position is brought out for reference:

- (i). The AKBTPPL in its letter dated 16 August 2016 represented regarding payment of differential amount on license fee for land. The main points made by AKBTPPL are as follows:

AKBTPL drawing reference to Article 9.1 of Concession Agreement has stated that whilst the license fee for waterfront is constant at ₹8 crores during entire tenure of Concession, the license fee for land shall be calculated as per the prevailing SOR set by TAMP from time to time.

The License Fee for land notified for this project was as per Chapter V, Schedule V - Rental Fees at Serial No.1 for open space. Now, as per new SOR the said item is not notified by TAMP, neither commensurate item is available in the new SOR of DPT. Even otherwise also, in view of the signed Concession Agreement the SOR of DPT for Kandla lands is not applicable for Tuna Dry Bulk Terminal, this view is clearly brought out in the TAMP Notification No.285 dated 2 November 2010 at Clause 11 (viii) (c) which is reproduced below for quick reference.

- “(c) License fee for the 902600 sq. meters land area is estimated by KPT at ₹10.50 per square meter per month based on the rate of storage fees on general cargo prescribed in the existing SOR of KPT (₹105 per 10 square meter for occupation beyond 180 days). The guidelines require License fee for lands to be calculated as per the Scale of Rates of the Port Trusts. It is needless to mention that rate as applicable for the relevant land should be considered. The present proposal of the port is for fixing the upfront tariff applicable to a dry bulk terminal off Tekra near Tuna which will be about 17 kilometres on west of mouth to Kandla creek. The existing SOR of KPT prescribes separate rates for Tuna under chapter-V. Sl. No.(1) of Schedule V specifies rental for open space at ₹7.50 per 10 sq. mtr. per month. The estimated License fee calculated by KPT by adopting License Fee prescribed for Kandla lands is modified accordingly with reference to the specific rate prescribed in the Scale of Rates for Tuna”.

Apart from above, the license fees is considered constant at ₹81 lakhs per annum and thus, cannot increase during entire tenure of Concession Period of 30 years, similar to the constant water front charges as per Concession Agreement.

- (ii). This was followed up by reminder vide its email dated 27 September 2017 by AKBTPL.
- (iii). In response to above, TAMP has vide letters dated 21 September 2016 and 10 October 2017 forwarded each of the communication received from AKBTPL dated 16 August 2016 and 27 September 2017 respectively to DPT stating that the representation received from the AKBTPL has arisen due to deletion of the Chapter – V of the then existing SOR relating to rates for Tuna port as proposed by the DPT. Hence, the DPT was requested to file a suitable proposal towards rental for the lands at Tuna port following the applicable Guidelines.

8. A joint hearing in this case was held on 11 June 2018 at the DPT premises. The DPT made a brief Power Point presentation of its proposal. At the joint hearing, the DPT and the concerned users/ user organizations have made their submissions.

9. As agreed at the Joint hearing, AKBTPL vide its letter dated 15 June 2018 has given further written submissions. The written submissions received from the AKBTPL was forwarded to DPT as feedback information vide our letter dated 22 June 2018 to furnish its comments. This was followed by the reminders dated 28 June 2018 and 13 July 2018. The DPT vide its letter dated 21 July 2018 has responded.

10. Based on the preliminary scrutiny of the proposal dated 13 March 2018, the DPT was requested to furnish information / clarification on a few points vide our letter dated 28 June 2018. This was followed by reminder dated 13 July 2018. The DPT vide its letter dated 21 July 2018 and subsequent letter dated 18 October 2018 and emails dated 19 November 2018 and 20 November 2018 has responded to the information/ clarifications sought by us. A summary of the information/ clarifications sought by us and the response of DPT is tabulated below:

Sl. No.	Information/ Clarifications sought by us	Response from DPT
I	<b>General:</b>	
(i).	In the first para of the LAC minutes dated 20 January 2016 it is recorded that the LAC recommended that the 2012 valuation (report furnished in 2013) may be returned back to the Valuer for review, particularly considering the differences between Leasehold Land and Freehold Land. Accordingly, the matter was referred by DPT to the valuer vide DPT letter dated 28 December 2015. The LAC minutes states that the valuer has submitted the revised valuations Report on 19 January 2016. There is no further mention of the 2016 valuation report.	Revised Valuation report dated 19.01.2016 shall be sent shortly. Further, the land valuation considered by LAC is based on Revised Valuation Report of Valuer dated 19.01.2016, with revised rates for the year 2012 and by due escalation, rates for 2016 are arrived at.

	<p>Moreover, from the LAC minutes it is seen that the valuation done in the year 2012 (report furnished in 2013) is considered by the LAC. A copy of the 2012 valuation report has been furnished by the DPT. The DPT has not furnished a copy of revised valuation report dated 19 January 2016.</p> <p>The DPT to furnish a copy of the Valuation Report, 2016. The DPT to also confirm whether the Land Valuation considered by the LAC appointed by DPT is based on 2012 Valuation Report or 2016 Valuation Report as valuation of Land as per LAC report refers to 2012 Valuation. If the Valuation Report of 2012 is considered, the DPT may examine the relevance of Land Valuation of 2012 for arriving at the rate in the year 2018.</p>	<p>[Subsequently, DPT vide its letter dated 18 October 2018 has furnished a copy of revised valuation report dated 19 January 2016.]</p> <p>As desired Revised Valuation Report dated 19 January 2016 is furnished. Hence, TAMP is once again requested to kindly approve the proposed modified Scale of Rates for Tuna Port of reply letter No.FA/COST/1021-I/285 dated 21 July 2018, as per Section 48, 49 and 50 of the MPT Act, 1963.</p>																		
(ii).	<p>DPT has not furnished a copy of Annexure – IV to Minutes of meeting of LAC held on 20 January 2016. Further, Annex I to III referred in the minutes of the LAC are also not attached to the proposal. The DPT to furnish a copy each of Annexures - I to IV to Minutes of meeting of LAC held on 20 January 2016.</p>	<p>Copies of following Annexures – I to IV of the Minutes of the meeting of the LAC held on 20.01.2016 are furnished:</p> <p>Annexure-I: Rates mentioned for village Tuna, Bharapar and Kidana as per Government of Gujarat's ready reckoner.</p> <p>Annexure-II: Highest rate at which Government sold land at Kidana Village.</p> <p>Annexure-III: Market value and lease rent for all four categories adopting same methodology as adopted by the valuer.</p> <p>Annexure-IV: A statement showing the market rate and lease rent as per various factors mentioned in 13 (c) of the amended Land Policy Guidelines, 2014 as on 01.01.2012.</p>																		
II	<b>Proposed Rental fees for Tuna Port:</b>																			
(i).	<p>The proposal of DPT states that the rate proposed for Kutcha Plot is based on the recommendation of the Committee appointed by the DPT to review the rates for Tuna Port and based on approval of the Board of the DPT. Neither in the Committee Report nor in the Report of LAC nor in the minutes of the Board approval, there is mention of ₹84.03 / Sq. Mtr. / annum for Kutcha Plot. The DPT to explicitly give reference of the Committee / LAC recommending the rate of ₹84.03 / Sq. Mtr. / annum for Kutcha Plot and reference of the Board approval for the same for Kutcha Plot.</p>	<p>As per the minutes of the LAC held on 20.1.2016, last para of page No. 5 which is reproduced as under:</p> <p>“Considering all above, the LAC after detailed discussions and deliberations recommended to considered the highest rate mentioned by the valuer in valuation report as shown at (ii) on Page 3 above i.e. actual transaction of sale of land by Government at nearby Kidana village during the year 2012, for deriving the rates of Tuna land only for land as and where basis which is mentioned below:</p> <table><tr><th>Sl. No.</th><th>Particulars</th><th>CRZ Zone</th><th>Suitable for purpose</th><th>Developed/ Un-developed</th><th>High Trade/ Creek area</th><th>Valuation</th><th>(-) less 25% for leasehold land</th><th>Lease rent @ 6% of Final valuation amount (₹ Per Sq. mtr p.a.)</th></tr><tr><td>1</td><td>*</td><td>CRZ-III</td><td>Salt production, CISF, Tank farms,</td><td>Undeveloped but having approach from 10 km</td><td>Open Undeveloped land</td><td>2645</td><td>1983.75</td><td>119.03</td></tr></table>	Sl. No.	Particulars	CRZ Zone	Suitable for purpose	Developed/ Un-developed	High Trade/ Creek area	Valuation	(-) less 25% for leasehold land	Lease rent @ 6% of Final valuation amount (₹ Per Sq. mtr p.a.)	1	*	CRZ-III	Salt production, CISF, Tank farms,	Undeveloped but having approach from 10 km	Open Undeveloped land	2645	1983.75	119.03
Sl. No.	Particulars	CRZ Zone	Suitable for purpose	Developed/ Un-developed	High Trade/ Creek area	Valuation	(-) less 25% for leasehold land	Lease rent @ 6% of Final valuation amount (₹ Per Sq. mtr p.a.)												
1	*	CRZ-III	Salt production, CISF, Tank farms,	Undeveloped but having approach from 10 km	Open Undeveloped land	2645	1983.75	119.03												

			Industries, warehouses.	road				
2	**	CRZ-III	Suitable for Warehouse, salt production on CFZ. Tank farms.	Undeveloped	Open land	2300	1725.00	103.50
3	***	CRZ-II	Suitable for Warehouse, CFZ Tank Farms	Undeveloped	High tide area	1955	1466.25	87.98
4	****	CRZ-I	Suitable for Jetty, Logistic operation & CFZ	Undeveloped	High tide area	1725	1293.75	77.63

\* Land on East side of approach road leading to Barge handling Jetty at tuna (from NH. No. 8A to tuna in length of 10 kms.

\*\* Land beyond half kilometer from the bank of Creek.

\*\*\* Land within half kilometer from the Creek of Barge handling, Jetty having no waterfront.

\*\*\*\* Land having waterfront and upto half kilometer from the Barge handling Jetty i.e. on the North side.

The proposed land allotted to M/s.AKBTPPL falls under category 4 i.e. Land having waterfront and upto half kilometer from the Barge handling jetty i.e. on North side and its Lease rent as on 2012 is ₹77.63 per sq. mtr. P.a. and considering 2% escalation, the rate for the year 2016 works out to ₹84.03 per. sq. mtr. p.a.

Further, as per Para 2 on page 2 of the Minutes of the Committee held on 27.11.2016, it has been recommended as "... for Kutchha plots, the rate will be as per latest valuation given by the Valuer for Tuna Port area and approved by the LAC."

Also, the Board of Trustees of DPT vide Resolution No. 109 of the Board meeting held on 26.12.2017 has resolved to approve the Proposal:

(i). "To add a separate tariff rates for the Tuna port as Schedule V of the Scale of Rates of DPT, placed as (Annexure – 60), and to obtain approval from the Tariff Authority for Major Ports under Section 48, 49, and 50 of the MPT Act, 1964;..."

**E SCHEDULE V- RENTAL FEES**

1. For Open space

(I) Kutchha plots	Rate per 10 Sq. Mtr. Or part thereof Per month or part Thereof (In ₹)	₹84.03 *
-------------------	---	-------------

Thus, from the above, it can be construed that the rate of ₹84.03 per. Sq. mtr. p.a. has been recommended by LAC meeting held on 20.1.2016, by Committee in its meeting held on 27.11.2016 and approved by the Board vide B.R. No. 109 in the Board meeting held on 26.12.2017.

[\* The rate proposed is ₹84.03 per sq. mtr. p.a. as per the calculation furnished by DPT and not ₹84.03 per 10 sq. mtrs. per month or part thereof.]



(ii).	Apart from point (i) above, the following rates given in the proposal do not match or could not be correlated:									
(a).	The rate of License fee before Revision of SOR as per 2011 SOR given in the table under Para 13 of the proposal dated 13 March 2018 at ₹9.00 per sq. mtr. p.a. does not match with rate approved in 2011 Order vide Order No.TAMP/61/2009-KPT dated 18.01.2011. The rate prescribed in 2011 Order for Kutcha Plot at Tuna is ₹ 7.50 per 10 sq. mtr. p. a. basis.	<p>The rate for Kutchha plot at Tuna as per rate approved in 2011 Order vide Order No. TAMP/61/2009-KPT dated 18.01.2011 is "₹7.50 per 10 sq. mtr. or part thereof per month or part thereof" and not "₹7.50 per 10 Sq. mtr. or part thereof <u>p.a.</u> or part thereof".</p> <p>Further, as regards to the rate of License fee before Revision of SOR as per 2011 SOR at "₹9 per sq. mtr. p.a." under Para 13 of the proposal dated 13.03.2018, it is to state that this rate of "₹9 per Sq. mtr. p.a." has been worked out on yearly basis considering the rate approved in 2011 Order of "₹7.50 per 10 Sq. mtr. or part thereof <u>per month</u> or part thereof".</p> <p>(7.50/10* 12 months = 9.00 p.a.)</p>								
(b).	The rate of License fee for Kutcha Plot at Tuna Port as per 2016 SOR indicated in the table under Para 13 of the proposal dated 13 March 2018 of ₹302.40 per sq. mtr. p. a. also does not match with rate approved in 2016 Order vide Order No.TAMP/18/2016-KPT dated 21.06.2016. The rate approved in 2016 Order for Kutcha Plot is slab wise and basis for levy is per 10 sq. mtr. p. a. basis. Please refer the Annex attached.	The rate of License fee for Kutchha plot as per 2016 SOR indicated in the table under para 13 of the Proposal dated 13.03.2018 of "₹302.40 per sq. mtr. p.a." is also worked out on yearly basis from the Schedule 2.5 License (Storage fees on General cargo (A) For Open space for the period of occupation of Beyond 180 days of "₹252.00 per 10 sq. mtr. or part thereof <u>per month</u> or part thereof", i.e. 252/10*12 months = ₹302.40 per sq. mtr. p.a.								
(c).	<p>The proposed rates of ₹84.03 per Sq. mtr. p. a. in the said table under Para 13 of the proposal dated 13 March 2018 neither matches with LAC recommendation nor with the rate proposed in SOR. Further, the rate proposed in the table at Para 13 is ₹84.03 per sq. mtr. p.a. whereas in the draft SOR the rate proposed is ₹84.03 per 10 sq. mtr. per day.</p> <p>The DPT is requested to examine and make necessary corrections in line with the correct position.</p>	Please refer clarification furnished vide Para II (i) above. Further, the rate proposed in the table at Para 13 of "₹84.03 per. Sq. mtr. p.a." may be considered and accordingly modified draft SOR is furnished.								
(iii).	<p>The DPT has stated that for Pucca plots, the rent prescribed in existing SOR of DPT is proposed. The existing SOR of DPT prescribes slab-wise licence (storage) fee for general cargo for storage at Pucca plot. Likewise, slab-wise licence (storage) fee is prescribed for covered space as well as open space as given below:</p> <p><b>2.5. LICENCE (STORAGE) FEES ON GENERAL CARGO</b></p>	<p>Necessary correction have been made in proposed draft SOR by incorporating slab wise License (storage) fee for general cargo for storage at Pucca plot both for Open space and for Covered space. The slab wise rates proposed by DPT in draft SOR are given below:</p> <p style="text-align: right;">(in ₹)</p> <table border="1" data-bbox="651 1854 1433 2056"> <tr> <th data-bbox="655 1854 965 1928" rowspan="2">Schedule V - Rental fees</th><th colspan="2" data-bbox="965 1854 1428 1928">Rate per 10 sq. Mtr. or part thereof per month or part thereof</th></tr> <tr> <th data-bbox="965 1928 1125 2011">Kutchha Plots</th><th data-bbox="1125 1928 1428 2011">Pucca Plots</th></tr> <tr> <td data-bbox="655 2011 965 2056">For open space</td><td data-bbox="965 2011 1125 2056"></td><td data-bbox="1125 2011 1428 2056"></td></tr> </table>	Schedule V - Rental fees	Rate per 10 sq. Mtr. or part thereof per month or part thereof		Kutchha Plots	Pucca Plots	For open space		
Schedule V - Rental fees	Rate per 10 sq. Mtr. or part thereof per month or part thereof									
	Kutchha Plots	Pucca Plots								
For open space										

	<b>(A). FOR OPEN SPACE:</b>		0 – 60 days	23.34	144.00
	Period of occupation	Rate per 10 sq. mtr. or part thereof per month or part thereof	61 – 90 days	46.68	288.00
		Pucca Plots (cemented asphalted) (in ₹)	91 – 180 days	58.35	360.00
			Beyond 180 days	70.03	432.00
			<b>For covered space</b>		
	0 – 60 days		279.00		
	61 – 90 days		558.00		
	91 – 180 days		697.50		
	Beyond 180 days		837.00		
<b>(B). FOR COVERED SPACE</b>		Subsequently, DPT vide its email dated 19 November 2018 has furnished a comparative position of the rate for License (storage) fee applicable for Tuna Port as per 2011 Order, 2016 Order and the rates now proposed by the DPT for Tuna Port.			
Period of occupation	Rate per 10 sq. mtr. or part thereof per month or part thereof (in ₹)	Further, DPT vide its email dated 20 November 2018 has furnished basis for arriving at above proposed rates, which is as follows:			
		The Rate for Kutchha plot as recommended by LAC and as approved by Board of Trustees, DPT, of ₹84.03 per sq mtr p.a. has been converted into rate per 10 sq. mtr per month to ₹70.03, to bring at par with the then existing unit of rate for storage of cargo i.e. Licence fees i.e. ₹84.03 *10/12= ₹70.03 per 10 sq. mtr per month.			
		[₹70.03 per 10 sq. mtr. per month is proposed by DPT for last slab beyond 180 days.]			
		The slab rates proposed for Kutchha plots for different segments of period of stay is proposed on the same analogy as approved for kandla rates i.e.			
		(₹ per 10 sq. mtr. per month or part thereof)			
		Period of occupation	Kandla rates	Proposed Tuna rates	
		0 – 60 days	84.00	23.34	
		61 – 90 days	168.00	46.68	
		91 – 180 days	210.00	58.35	
		Beyond 180 days	252.00	70.03	
	However, rent proposed by DPT for Tuna port is single rate at ₹432 / 10 sq. mtr. / month adopting the highest rate of the last slab prescribed in the existing SOR of DPT. The proposed rate of DPT for Tuna Port is not found to be in line with the recommendation of the Committee dated 22 November 2016 that the rate applicable for Pucca plot at DPT will apply for Tuna Port. The DPT may examine and, if necessary, make corrections in the proposed rate.				
(iv).	The terminology prescribed in the existing SOR of DPT is Licence (Storage) fees on general cargo for storage of cargo. The DPT to, therefore, consider to modify the terminology prescribed in the Chapter – V for Tuna Port as “Rental Fees” to “Licence (Storage) fee” to fall in line with the existing prescription in DPT SOR.		The terminology prescribed in the Chapter – V for Tuna Port has been modified in line with the existing prescription in DPT SOR.		

III.	<b>Scale of Rates:</b>	
(i).	The SOR approved by the Authority in 2011 Order prescribed separate Chapter V – prescribing Rate for Tuna Port which also contained a few conditionalities governing the tariff prescribed. In the proposed Chapter – V for separate rate for Tuna Port, the port has not proposed any of those conditionalities. The DPT is requested to examine and give reasons for not proposing the conditionalities governing the levy of separate tariff for Tuna Port prescribed in 2011 Order.	The proposed Chapter – V for separate rate for Tuna Port has been modified by incorporating the conditionalities governing the levy separate tariff for Tuna port.  [The conditionalities for Tuna Port proposed to be incorporated by DPT is brought out in the subsequent paragraphs.]
(a).	A statement giving comparison of the rates approved for Tuna Port vide Order No.TAMP/61/2009-KPT dated 18.01.2011, rate applicable as per the last SOR revision vide Order No. TAMP/18/2016-KPT dated 21 June 2016 and rate now proposed by DPT in its proposal along with percentage increase in rate in 2016 Order and proposed rate in comparison to rate prescribed in 2011 Order is done by us and is attached as Annex. The DPT may go through it and confirm that it is in order.	It is confirmed that the Annex attached to is in order.
(b).	The reasons for proposing reduced rates for Vessel related charges (Port dues, berth hire and beaching charges) and cargo related charges (Wharfage on Animal and Animal products as compared to the Kandla rates to be furnished.	The reason for proposing reduced rates for Vessel related charges (port, dues, berth hire and beaching charges) and cargo related charges (Wharfage on Animal and Animal Products) as compared to the Kandla rates has already been furnished vide Para 7 to 11 of the proposal dated 13.3.2018. [Brought out in para 2.2 (vii) above.]
(ii).	At the joint hearing, the DPT has stated that approximately additional revenue of ₹129.63 lakh is estimated from cargo related and vessel related charges at the proposed rates for Tuna Port. The DPT to indicate what was the revenue from Tuna Port estimated while revising the last SOR of 2016. Furnish the detailed working for the additional income of ₹126.33 lakh indicating the unit rate, traffic, income estimated during 2016 Order and income now estimated at the proposed rate for each of the tariff items. The DPT is requested to confirm that additional annual estimated	There is financial implication of reduced rates applicable to Tuna Port of approximately ₹126.53 lakhs and this has been indicated vide Para 14 of the proposal dated 13.03.2018, hence there is no additional revenue from the proposed rates for Tuna port of ₹129.63 lakhs. The revenue estimated from Tuna Port in last revision of SOR 2016 was ₹253.34 lakhs. The statement showing Revenue as per SOR 2011, as per SOR 2016 and as per proposed SOR is furnished.  Hence, TAMP is once again requested to kindly approve the proposed modified SOR for Tuna Port, placed as Annexure-I, as per Section 48, 49 & 50 of the MPT Act, 1963.

revenue from the subject proposal is well within the differential ARR ₹700.26 lakhs left uncovered in the last tariff Order and also confirm that the total revenue expected is within total estimated ARR of ₹84,251.84 lakhs.	
---	--

11. The modified rates for Licence (storage) fees and general notes which are newly inserted as proposed by DPT are given below:

(in ₹)

Schedule V - Rental fees	Rate per 10 sq. mtr. or part thereof per month or part thereof	
	Kutchha Plots	Pucca Plots
<b>For open space</b>		
0 – 60 days	23.34	144.00
61 – 90 days	46.68	288.00
91 – 180 days	58.35	360.00
Beyond 180 days	70.03	432.00
<b>For covered space</b>		
0 – 60 days		279.00
61 – 90 days		558.00
91 – 180 days		697.50
Beyond 180 days		837.00

**General Notes:**

- Whenever no specific rate is available, the rate prescribed for the corresponding items at Kandla will apply provided the relevant services offered / facilities provided at tuna port are at par with those at Kandla.
- The terms and conditions of rendering the services at Tuna will be same as prescribed for corresponding services at Kandla provided for comparable services offered / facilities provided.
- The aggregate amount of bill shall be rounded off to the next higher rupee.

12.1. Subsequent to above, the DPT vide our letter dated 13 December 2018 was requested to furnish further additional information / clarification by 15 December 2018 on following points:

- The proposal of DPT is silent about the effective date of the revised tariff proposed for Tuna Port. The DPT to clarify whether the revised tariff proposed for Tuna port is to be given retrospective effect from the date the last general revision of SOR of DPT came into effect i.e. from 11 August 2016 or prospective effect from the date of effect of the Order to be passed by the Authority on the subject proposal filed by DPT.
- In the original proposal dated 13 March 2018, the nomenclature of rate proposed for Tuna port at Sr. No.E is "Rental fees" as approved by the Board of Trustees of DPT and as prevailing in the pre-revised SOR approved by the Authority in 2011.  
  
In the light of the clarification furnished by DPT vide its letter dated 11 April 2018 that this item is a cargo related charge i.e., Storage space to be allotted for storage of Cargo and also since port in its revised proposal dated 21 July 2018 has proposed slab wise rate for stay of cargo, the port may examine and clarify whether the nomenclature needs to be modified as "Rental fees for storage of cargo".

- (b). In the existing SOR, under schedule 2.5 - prescribing Licence (Storage) fees for General Cargo for Kandla division, various conditionalities governing the rate are prescribed. The port may examine to include relevant conditionalities for levy of rental fees for storage of cargo for Tuna port as well.

12.2. In response, the DPT vide its letter dated 19 December 2018 have made following submissions:

- (i). With regard to 12.1 (i) above, the issue of the effective date of the revised rate proposed for Tuna Port, the port has stated that the matter has been referred to Indian Ports Association (IPA) and their report is expected shortly. It has, thus, requested to keep the subject case on hold. As soon as report from IPA is received, TAMP shall be informed accordingly.
- (ii). With regard to above 12.1 (ii) (a), the nomenclature of the proposed service may be modified as "License (storage) fee on General Cargo".
- (iii). With regard to above 12.1 (ii) (b), the conditionalities in the existing SOR under schedule 2.5 – "License (Storage) fees on General Cargo" for Kandla division, may be prescribed for storage of cargo for Tuna Port.

12.3. However, since no further response from DPT was received with regard to above para 12.2 (i), it was followed up with DPT by reminders dated 25 January 2019, 07 March 2019 and 01 April 2019.

12.4. In response, the DPT vide its email dated 06 June 2019 has stated that the Board vide Resolution No.22 in its meeting held on 28 May 2019 has approved the effective date of the revised rate proposed for Tuna Port as 11 August 2016 i.e. the effective date of the last General revision of SOR of DPT. A copy of the Board Resolution is furnished by the DPT.

13. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to them. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

14. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i). The proposal filed by the DPT flows from the representation made by concerned users / user association in view of steep hike in the Vessel Related Charges (VRC) and Cargo Related Charges (CRC) including storage charges of Tuna Port in the last General Revision of Scale of Rates (SOR) of Deendayal Port Trust (DPT) approved by this Authority vide Order No.TAMP/18/2016-KPT dated 21 June 2016. During the revision of the said SOR, DPT had proposed for deletion of separate Schedule of Rates then prevailing for Tuna Port in the SOR of the DPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/61/2009-KPT dated 18 January 2011. The port during the revision of 2016 had proposed to apply the rate of Kandla port for Tuna Port by way of prescription of a note under general notes.

The SOR of DPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/61/2009-KPT dated 18 January 2011 prescribed vessel related charge, wharfage related charges, rental fees and trolley hire charges separately under Chapter V for Tuna port as then proposed by DPT taking into consideration the type of crafts, nature of cargo being handled, draft requirement etc. at Tuna Port.

During the last general revision of DPT in the year 2016 under the Tariff Policy, 2015, the port had proposed to do away with a separate schedule of rates for Tuna port. Instead, the port proposed to insert a note stating that the tariff applicable for Kandla port is applicable for Tuna Port. With reference to the proposed note during the processing of the proposal of DPT which culminated into Order dated 21 June 2016, DPT was specifically requested to justify whether the services provided at Tuna Port is at par with Kandla division of DPT. In this context, DPT had then justified that Tuna port has been provided with all the infrastructural facilities like road and rail connectivity, etc. and had confirmed that the services, infrastructure, equipment and facilities provided at Tuna are comparable to those rendered at Kandla division. Based on the justification and clarification furnished by the port, the separate schedule of rates for Tuna port then prevailing at Chapter-V was deleted as proposed by DPT and the note proposed by DPT about applicability of Kandla rates to Tuna port was prescribed as a note no.(xv) under General Terms and Conditions No.1.2. The current proposal of the DPT is for reverting back and prescription of separate schedule of rate for Tuna Port based on representation made by few users/ user association.

The submission made by the Adani Kandla Bulk Terminal Private Limited (AKBTPL), the Bulk Terminal Operator at Tuna Port of DPT (governed under the upfront Tariff Guidelines of 2008) that the rate for Tuna Port was inadvertently missed out in SOR approved in 2016 Order is not factually correct. As brought out in the preceding para and for reasons brought out in para 20(xii)(c) of the tariff Order dated 21 June 2016 as proposed by DPT the then Schedule of rate for Tuna Port was done away in the revised SOR and the note no.(xv) under General terms and conditions No.1.2 stating that Kandla rates shall be applicable to Tuna port was prescribed in the SOR of the DPT as proposed by the port.

- (ii). Now, coming to the current proposal of the DPT, based on representations made by Salaya Sailing Vessels Owners' Association (SSVOA) to DPT for review of port charges of Tuna Port, in view of exorbitant increase in port charges for Indian Sailing Vessel at Tuna Port arising due to application of the rates of Kandla division to Tuna Port and also in view of the points made by the AKBTPL about steep hike arising in license fees for Tuna Port as per the SOR approved in Order of June 2016, the DPT has mooted the current proposal for incorporation of a separate tariff schedule of rates for Tuna port as Chapter-V in the existing SOR of DPT. This is following the arrangement prevailing prior to the June 2016 Order in the pre-revised SOR approved by this Authority in the January 2011.

Though the existing SOR of the DPT is valid till 31 March 2019, the DPT has justified its proposal seeking approval of this Authority for separate schedule of rates for Tuna Port in the existing SOR of the DPT citing the following main reasons:

- (a). There has been exorbitant increase to the tune of about 200% in wharfage charges, 150% in Berth Hire Charges and 500% in Port Dues for Tuna Port.
- (b). No expenditure is incurred towards dredging at Tuna by DPT.
- (c). Bare minimum staff is posted at Tuna, as such, the cost of manpower is very less.
- (d). Livestock is handled at Tuna which hardly cause any damage to the wharf etc.
- (e). Livelihood of the village of Tuna, Vandi and other nearby village is dependent upon export of Livestock from Tuna.
- (f). Mechanized craft owners are not so rich and are dependent upon loans from Bank / Financial Institutes.

In view of representation made by relevant user association and AKBTPL, the DPT has constituted a Committee comprising of Traffic Manager, Deputy Conservator, Chief Engineer and Financial Advisor and Chief Accounts Officer for reviewing the SOR of Tuna Port of DPT. The current proposal filed by DPT is based on the recommendation of the Committee constituted by DPT for review of rate for Tuna Port and approval of the Board of Trustees of the DPT.

Thus, in view of the above position brought out by DPT, there is a case to consider the current proposal filed by the DPT for review of rates for Tuna Port in the existing SOR of DPT under the Tariff Policy, 2018 though the existing SOR of DPT is valid till 30 September 2019. It is relevant here to state that recently, this Authority has, based on the proposal of the Mormugao Port Trust (MOPT) and VPT revised the rates for a few items in their respective SOR during the currency of the SOR

A joint hearing in this case was held on 11 June 2018 at the DPT premises. Information / clarification was sought vide our letter dated 28 June 2018 with reference to its proposal giving time upto 05 July 2018. After regular follow up, the port has furnished the requisite information / clarification along with modified draft SOR and conditionalities vide its letters dated 21 July 2018 and subsequent letter dated 18 October 2018 and emails dated 19 November 2018, 20 November 2018, 30 November 2018, 19 December 2018 and 06 June 2019. This case could be processed by this Authority for finalisation only after receipt of complete response from the port which was last received on 06 June 2019.

The proposal of DPT was filed under the Tariff Policy, 2015 and the entire processing was done under the said Tariff Policy, 2015 which was valid till issue of new Tariff Policy, 2018 made effective from 26 December 2018. The broad framework of Tariff Policy, 2018 issued by the MOS is same as Tariff Policy, 2015 except few minor amendments. Since the Tariff

Policy, 2015 is superseded by Tariff Policy, 2018 with effect from 26 December 2018, this case is finalized by this Authority under Tariff Policy, 2018.

- (iii). Before proceeding to analysis of this case, it is relevant here to state that for arriving at the proposed rate of License (storage) fee for Kutchha plot, the port has followed the different methods prescribed in the amended Land Policy Guidelines (LPG) 2014 for valuation of land.

In this regard, the DPT has clarified that only for determining the rate for Kutchha plot, reliance was made by the port on land valuation given by approved valuer and approved by LAC. The port has categorically stated that proposal for revision of License (Storage) fee for Kutchha plot of Tuna port is covered under CRC. The port allots storage space for storage of Cargo and charges shall be levied on the basis of stay of cargo. The port has categorically stated that it is not allotment of land for Lease and License basis as per amended LPG, 2014 and hence proposed Storage charges for Kutchha plot at Tuna are not covered under amended LPG, 2014. The port has emphasised that the rate sought for Kutchha plot is covered under the General revision of SOR following the principles of Tariff Guidelines, 2015 which is revised to Tariff Policy, 2018.

As regards objection raised by AKBTPPL that the proposal of DPT is untenable, unreasonable, bad in law and unjustified as it is clubbing two guidelines Tariff Policy 2015 and LPG, 2014 for an existing project during the currency of License, the port has reiterated that there is no clubbing of two guidelines i.e. Tariff policy 2015 and LPG, 2014. The AKBTPPL has also objected on the valuation of land considered by DPT to arrive at proposed License (Storage) fee. The port has categorically stated that the current proposal has been framed within the ambit of Tariff Policy, 2015 only which has been revised to Tariff Policy, 2018 keeping the same framework. While proposing the License (Storage) fee for Kutchha plot of Tuna port, only for determining the rates, reliance has been made by the Committee constituted by the port to review the rates for land at Tuna Port on latest valuation given by the Valuer for Tuna port area and approved by the LAC. These rates are covered under Cargo Related Services of the General revision of SOR following the principles of Tariff Policy, 2015 and hence as such in proposing the above rates, DPT has not applied LPG, 2014. The port further clarified that current proposal is outside the ambit of LPG, 2014 and has no relevance with the same.

In the revised proposal dated 21 July 2018, the DPT has proposed slab wise License (Storage) fee for stay of cargo of 0-60 days, 61-90 days, 91-180 days and beyond 180 days. The revised rate proposed by DPT strengthens argument of DPT that the rates for License (Storage) fee linked to duration of stay of cargo is proposed under Cargo Related Services as part of general revision of SOR. In view of the above position and keeping in view the clarification and justification furnished by the DPT, this Authority considered the entire proposal of DPT under Tariff Policy, 2018. The Tariff Policy, 2015 and the revised Tariff Policy, 2018 already give flexibility to the Port Trust to propose rates in the Scale of Rates within the ARR.

- (iv). (a). The Schedule of Rates for Tuna Port proposed by DPT is based on the recommendation of Committee constituted by the port.
- (b). The Committee has recommended the VRC i.e. Port dues, Berth hire charges, Beaching charges for Tuna Port taking the pre-revised rates prescribed for Tuna Port in the general SOR of the DPT approved by this Authority in Order dated 18 January 2011 as the base and applying WPI escalation of 30.35% from 2011 to 2016. Tariff Policy, 2018 gives flexibility to Major Port Trusts to propose SOR within the ARR.

A comparative statement showing the rates applicable for Tuna Port as per the pre-revised Order of 2011 (Order No.TAMP/61/2009-KPT dated 18 January 2011), Order of June 2016 (Order No.TAMP/18/2016-KPT dated 21 June 2016), and the rates now proposed by the DPT for Tuna Port alongwith percentage increase arising in 2016 Order on account of applicability of DPT rate to Tuna Port, percentage increase/decrease at the proposed separate rate for Tuna Port as against the rates applicable as per the tariff Order of 2016 and percentage increase / decrease over the then prevailing rate as per the 2011 Order is attached as **Annex**.

It can be seen from the comparative statement attached at Annex (Column no.10) that as rightly stated by SSVOA, the prescription of the note to apply Kandla rates to Tuna port in the tariff Order of 2016 led to steep increase in VRC i.e. 901% to 1069%

increase in port dues, 667% increase in Berth Hire charges and 769% increase in Beaching charges.

The revised proposed rate is arrived by the DPT applying 30.35% WPI, increase over the then prevailing rates of 2011 which were applicable till 10 August 2016 till the revised SOR was made effective from 11 August 2016. At revised proposed rate in the VRC, the increase over the 2011 Order rate works out to be 30.33% to 30.37%. The proposed rate shows 83% to 87% reduction over the rates applicable as per the tariff Order of 2016.

In the instant proposal, recognising that the revised VRC proposed by DPT for Tuna Port is based on recommendation of the Committee and approved by the Board flowing from representation made by relevant association to DPT about steep hike arising for Tuna Port by applying the rates of Kandla Port, this Authority is inclined to approve the revised rate proposed by DPT for Tuna Port. Since the proposal is for reduction in the existing rate, the revenue at the revised proposed rate is not expected to exceed the ARR estimated in the last tariff revision of 2016 Order.

The SOR of DPT approved in 2011 did not prescribe rate for anchorage charges for Tuna Port. The port has now proposed to prescribe anchorage charge for Tuna Port at par with the existing rate at Inner anchorage for Kandla Division approved in the Tariff Order of 2016 applicable. The proposed rates are approved.

- (c). The increase in wharfage (CRC) at the rates applicable as per tariff Order of 2016 over the pre-revised rate is in the range of 20% to 233% for most of the cargo items and 456% for POL products.

As regards CRC, the said Committee constituted by the DPT held that port has invested considerable amount on creation of infrastructural facilities at Tuna port such as roads, berth, barge jetty, backup area, lighting, etc. Hence, reducing the CRC is not found appropriate by the Committee. However, in view of request by M/s.SSVOA, wharfage rate for livestock is proposed for reduction from the existing rates applicable as per Order of 2016. The proposal of DPT states that revised rate for livestock viz. Animals including chicken, sheep & goats, Animals (other than Animals including chicken, sheep & goats) and Animal products, bone meal, hiders & skin is arrived applying WPI escalation of 30.35% over the wharfage rates approved in 2011 Order based on the recommendation of the Committee. The increase in wharfage rate works out to 30.33%, 30.42% and 30.44% for the above livestock categories respectively over the pre-revised rates of 2011 Order. As compared to existing rates applicable as per 2016 Order, the revised wharfage rates proposed by DPT results in 56.56% reduction in the wharfage rate for Animals including chicken, sheep & goats, 47.83% reduction for Animals (other than Animals including chicken, sheep & goats) and 34.78% for Animal products, bone meal, hiders & skin. For other items, the DPT has proposed to retain the wharfage rate as presently applicable as per 2016 Order.

The DPT proposed to include separate wharfage schedule for Tuna port as prevailed in SOR approved by this Authority in 2011. Recognising that the proposal of DPT is based on recommendation of the Committee and approved by the Board of Trustees of DPT, the proposed wharfage schedule for Tuna port is approved as proposed by DPT. Since the proposal is for reduction in the existing wharfage rate for 3 items, the revenue at the revised proposed rate is not expected to exceed the ARR estimated in the last tariff revision of Order of 2016.

- (d). The existing SOR approved in 2016 do not prescribe any tariff for storage of timber on board and for trolley hire charges. The pre-revised SOR approved in 2011 prescribed rate for trolley charges at ₹15 per day and ₹1.5 per 10 sq. mtr. per day for storage of timber on board for Tuna port. The rate proposed in current proposal at ₹19.55 per day and ₹1.96 per 10 sq. mtr. per day for the said two items respectively are arrived by the DPT applying 30.35% WPI, increase over the then prevailing rates of 2011 as done for revised VRC for Tuna port. The proposed rates are for miscellaneous services and may not have any significant impact. Hence, the proposed rate for these two items are approved.
- (e). The SOR approved in the tariff Order of 2011 prescribed rental for open space at ₹7.50 per 10 sq. mtr. per month or part thereof (i.e. ₹9.00 per sq. mtr. Per annum [i.e.



₹7.50 / 10 sq. mtr. \* 12 months]). For covered space, the rate prescribed in 2011 Order is ₹48 per 10 sq. mtr. per month or part thereof i.e. 57.60 per sq. mtr. p.a. (i.e. ₹48 / 10 sq. mtr. \* 12 months).

Applicability of the Licence (Storage) fees as per Kandla division to Tuna Port in the SOR approved in the tariff Order of 2016 based on the proposal of DPT led to steep increase of 1020% to 3260% for Kutchha plots in open space, 1820% to 5660% for Pucca plots in open space and 481% to 1644% for covered space.

In the earlier SOR of 2011, the License (Storage) fee for Tuna port was prescribed as a single rate for each of Open Space and Covered Space as stated earlier as the proposed by DPT.

The DPT has, based on recommendation of Committee, originally proposed Licence (Storage) fees for open area by bifurcating into two categories viz. Kutchha plots and Pucca plots. The Licence (Storage) fees for Pucca plots under open space and for covered space are proposed by the DPT slab wise at par with the Licence (Storage) fees prescribed in the existing SOR of DPT at schedule 2.5 in the tariff Order of 2016.

As regards Kutchha plots, the DPT had earlier proposed rate of ₹84.03 per sq. mtr. or part thereof per annum. This works out to ₹70.03 per 10 sq. mtr. per month (₹84.03 / 12 months \* 10 sq. mtr.). Subsequently, the DPT has proposed slab wise rate and unit of levy is proposed on per 10 sq. mtr. per month or part thereof basis as applicable for Kandla. The rate proposed by DPT for the first slab is ₹23.34 per 10 sq. mtr. per month or part thereof for 0-60 days, ₹46.68 per 10 sq. mtr. per month or part thereof for 61-90 days, ₹58.35 per 10 sq. mtr. per month or part thereof for 91-180 days and ₹70.03 per 10 sq. mtr. per month or part thereof beyond 180 days. The slab wise structure proposed by DPT for Kutchha plots for different segments of period of stay is on the same analogy as approved by this Authority for Kandla Division.

At the proposed rates, there is reduction in rates for Kutchha plots for Open Space by 72.21% for each of the slabs as against the rate applicable as per the 2016 Order. The rates proposed for Pucca plots in Open Space and for Covered Space are proposed to be prescribed at par with rates of Kandla. Recognising that the proposal of the DPT is based on the recommendation of the Committee appointed by DPT to review the rates for Tuna port and has been approved by the Board of Trustees of DPT, the revised Licence (Storage) fees proposed for Tuna port is approved.

The port has subsequently requested to prescribe the nomenclature as Licence (Storage) fees for general cargo. Since the charges are for storage of cargo, it may suffice if the nomenclature is mentioned as "Storage charges for general cargo".

As per Clause 2.6 of Tariff Policy 2015, the Major Port Trusts have the flexibility to determine the rates to respond to the market forces based on commercial judgment and draw the SOR within the ceiling of indexed ARR. In the last revision of the SOR of DPT approved vide Order No.TAMP/18/2016-KPT dated 21 June 2016, the ARR estimated by this Authority is ₹84,251.84 lakhs per annum and the revenue estimated by DPT at the SOR then proposed and approved in the said Order was ₹83,551.58 lakhs. The differential of ₹700.26 lakhs (₹84,251.84 lakhs less ₹83,551.58 lakhs) was left uncovered by this Authority which the port was allowed to take care from the tariff items and conditionalities for which the DPT could not capture the revenue impact at that point of time.

The port has estimated reduction in revenue to the tune of ₹129.53 lakhs per annum on account of proposed reduction in VRC and wharfage charges of few items at the proposed rates for Tuna Port.

As regards Storage charges, the port has clarified that no financial implication to ARR is estimated as same has not been considered in ARR, as per Tariff Policy, 2015. Working Guidelines issued by TAMP, require Major Port Trusts to estimate revenue for each of the tariff items in the proposed SOR. Hence, the point made by DPT that Tariff Policy, 2015 does not require to estimate revenue from Storage charges is not correct. In this regard, it is to state that, in the last tariff revision Order of 2016 under Tariff Policy 2015, the revenue estimated by the DPT at the proposed SOR includes revenue estimate from Storage charges at ₹24.11 lakhs. The revenue estimated by

DPT does not show separate estimate for Storage charges for Kandla port and for Tuna port. Now, the port has proposed to retain the Storage charges as in 2016 Order for Pucca plot for Open Space and for Covered Space. Hence, there may not be any revenue impact. As regards, Storage charges for Open Space for Kutchha plots, the DPT has proposed reduction in the rate from the rate applicable as per 2016 Order. Hence, in this scenario, the revenue estimated in tariff Order of 2016 which included Storage charges is likely to reduce and not increase. Recognising that the Major Port Trusts have the flexibility to determine the rates to respond to the market forces based on commercial judgment and draw the SOR within the ceiling of indexed ARR, the revised Storage charges proposed by the DPT are approved.

- (f). Thus, to summarise the proposal of the DPT for insertion of separate Schedule of rate for Tuna port as Chapter-V is approved as proposed by the DPT. Consequent to above, the existing Chapter-V relating to tariff for Marine related services provided by DPT at Dry bulk terminal commissioned by AKBTPPL at Tuna / Tekra is renumbered as Chapter-VA as proposed by DPT.

In view of the approval accorded to the proposal of the DPT, the existing note No.(xv) prescribed under General terms and conditions in the existing SOR is found to be infructuous and hence deleted.

- (v). One of the points made by AKBTPPL is that LPG, 2014 is applicable only for allotment of fresh land leases and / or at the time of renewal of expired leases whereas land allotted to them at Tuna port is not fresh allotment of lease, hence, valuation exercise done by DPT does not apply. The AKBTPPL has also stated that the valuation report takes clue from land deals done in villages of Kidana & Bharpap, which are more than 14-18 kms away from the area of AKBTPPL and completely ignores the nearby villages of Tuna & Vandri. In this context, as stated earlier, DPT has categorically stated that revision in Storage charges for Tuna port is not under LPG, 2014 but under Tariff Policy, 2015. Only for arriving at the rate for Kutchha plot for Tuna port, DPT has relied on land valuation given by approved valuer. The Tariff Policy, 2015 and the Tariff Policy, 2018 effective from 26 December 2018 gives this flexibility to Major Port Trusts to draw the SOR within the ARR. In the last revision of SOR under Tariff Policy, 2015 the ARR estimated by this Authority is ₹84,251.84 lakhs per annum and the revenue estimated by DPT at the SOR then proposed and approved in the said Order was ₹83,551.58 lakhs. The differential of ₹700.26 lakhs (₹84,251.84 lakhs less ₹83,551.58 lakhs) was left uncovered by this Authority which the port was allowed to take care from the tariff items and conditionalities for which the DPT could not capture the revenue impact at that point of time. As stated earlier revenue from the proposed tariff item is within the ARR estimated in the Tariff Order of 2016.
- (vi). The port has proposed notes stating that whenever no specific rate is available, the rate prescribed for the corresponding items at Kandla will apply to Tuna port provided the relevant services offered / facilities provided at Tuna port are at par with those at Kandla. The another note proposed by the DPT is that the terms and conditions of rendering the services at Tuna will be same as prescribed for corresponding services at Kandla provided for comparable services offered / facilities provided. The proposed notes are as prescribed for Tuna Port in the SOR approved by this Authority in 2011 Order and hence approved to be included in the existing SOR while prescribing separate Chapter for rates of Tuna Port.
- (vii). (a). The AKBTPPL has objected the Storage charges proposed by the DPT. The AKBTPPL has opposed the Land Valuation Report considered as the basis of determination of land rates of Tuna. The AKBTPPL has viewed that market Value of Land Rates which are considered is Industrial developed Land which is not in Tuna village but in Bharpap & Kidana which is located behind Kandla Special Economic Zone and around 14-18 Km away from Tuna Terminal. As already stated, the port has clarified that in the present proposal, for proposing the Storage charges for Kutchha plot of Tuna port, only for determining the rates, reliance has been made on latest valuation given by the Valuer for Tuna port and approved by the LAC. These rates are covered under Cargo related services of the General revision of SOR following the principles of Tariff Policy, 2015 and hence the DPT has clarified that in proposing the Storage charges for Kutchha plot, it has not applied LPG, 2014. This clarification given by DPT is accepted. The Tariff Policy, 2015 under which this proposal is filed and the subsequent Tariff Policy, 2018 in place of Tariff Policy, 2015 gives flexibility to Major

Port Trust to draw SOR within the estimated ceiling ARR. As stated earlier, at the proposed rates for Kutchha plot, there will be reduction of 72.21% from the rates applicable as per the existing SOR approved by this Authority in 2016 Order and hence revenue estimate is within the citing ARR.

- (b). The AKBTPL has signed Concession Agreement (CA) with the DPT for operating Bulk Cargo terminal on 26 June 2012 for a period of 30 years. As per Article 9.1 (a) of the CA, Licence fees payable by AKBTPL is ₹81,23,400 for land (i.e. 9,02,600 sq. mtrs. X ₹0.75 X 12 months). The CA stipulates that the amount of Licence fees for land shall be calculated as per prevailing SOR set by TAMP from time to time. The AKBTPL has stated that Licence fee of ₹81.23 lakhs in CA is applying the Licence (Storage) fees of 7.50 per 10 sq. mtrs. / month) as per then prevailing rate for Tuna port. The AKBTPL has viewed that any rise in Licence (Storage) fees for land allotted for the Public Private Partnership (PPP) project of AKBTPL can either be at 60% of WPI indexation or at 2% as provided in LPG, 2014 on the base Licence (Storage) fees as mentioned in Article 9.1 (a) of the Concession Agreement. The AKBTPL has requested this Authority to give guidelines to DPT and to AKBTPL on issues arising from the notification of upfront tariff Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 relating to upfront tariff approved by this Authority for the Dry Bulk Terminal off Tekra near Tuna at Port of Kandla to be developed under PPP mode at DPT.

With reference to above points made by AKBTPL, it is to state that the reasons and the basis of considering ₹7.50 per 10 sq. mtr. per month as applicable for Tariff Policy, 2015 for estimating Licence (Storage) fees for upfront tariff approved by this Authority vide Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 is elaborately dealt with in para 11 (viii) (c) of the said Order. The current proposal before this Authority is to approve rates for Tuna Port under a separate Chapter as per the arrangement prevailing prior to the existing SOR approved in June 2016. This Authority is to approve rate for services at Tuna port provided by DPT for the use of property and on common user basis and not restricted for any individual user/ BOT operator operating at Tuna port. The matter referred by AKBTPL appears to flow from the CA entered between the DPT with the individual BOT operator i.e. AKBTPL. This Authority does not like to interfere in the matter arising from individual Concession Agreements entered by the concerned Port Trust with the individual operator / lessees as it is beyond the mandate of this Authority.

This Authority likes to make it abundantly clear that the Bulk Terminal Project awarded by the DPT to the AKBTPL is based on the upfront tariff fixed by this Authority Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 under the Upfront Tariff Guidelines of 2008. The DPT and AKBTPL are governed by the said Upfront Tariff approved by this Authority following the Upfront Tariff Guidelines of 2008 issued by the MOS. As per clause 2.8. of the upfront tariff fixation guidelines of 2008 and para 11.1 of the said Order, the tariff fixed upfront are subject to only annual indexation to the extent of 60% of the variation in WPI. The 2008 Guidelines do not provide for enhancement of upfront tariff prescribed for the PPP projects whenever revised lease rentals are notified. The upfront tariff approved by this Authority, however, shall qualify for annual indexation to the extent of 60% of the variation in WPI as per clause 2.8 of the upfront tariff guidelines of 2008 to meet inflation.

It is also relevant here to state that a Committee constituted by MOS under Indian Ports Association (IPA) has given the report on stressed project evolving a mechanism to all the Major Port Trusts to bring out such stressed projects. The said IPA Committee Report issued by the MOS to all Major Port Trusts also includes other issues. One of the issues dealt in the IPA report relates to License fee provisions in the CA. The DPT and AKBTPL may, therefore, like to explore the possibility of resolving this matter based on the recommendations contained in the said report.

- (c). As regards the request made by AKBTPL requiring this Authority to issue suitable direction to DPT for devising new escalation methodology for escalating the Licence (Storage) fees for Tuna Dry Bulk Terminal at 60% of WPI as applicable to PPP project of as per amended LPG, 2014, it is to state that issuing direction to DPT for devising new escalation methodology for escalating the Licence (Storage) fees for Tuna Dry Bulk Terminal for arriving at rate is beyond the mandate of this Authority.

Annual escalation factor applicable / methodology for annual tariff escalation on the tariff being approved by this Authority is already prescribed in the relevant guidelines applicable to the Major port Trusts / BOT operators. The Major Port Trusts / BOT operators and this Authority are governed by same.

- (viii). As regards conditionalities governing the proposed rate, the DPT has sought prescription of the conditionalities as prescribed in schedule 2.5 for Kandla division. That being so, the same are incorporated in the schedule of Storage charges for Tuna Port.
- (ix). Ordinarily the rate approved by this Authority shall come into force after expiry of 30 days from the date of notification of the Scale of Rates in the Gazette of India. However, the Board of Trustees of DPT vide Resolution No.22 in its meeting held on 28 May 2019 has resolved to give effect to the separate tariff for Tuna Port retrospectively with effect from 11 August 2016 i.e. the effective date of the last General revision of SOR of DPT, the separate tariff approved by this Authority shall be made effective from 11 August 2016 and included in the existing SOR of DPT which is valid till 30 September 2019.

15.1 In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the following rates for Tuna port in the existing SOR of DPT:

- (i). **Insert the following as Chapter V – Rate for Tuna Port in the existing Scale of Rates of DPT:**

**“CHAPTER V - RATE FOR TUNA PORT**

Sr. No.	Particulars	Unit of levy	Foreign Going Vessel (in US \$)	Coastal Vessel (in ₹)
<b>A.</b>	<b>Schedule 1 - Port Dues</b>			
1	Vessels of 10 GRT & Upwards (except fishing boats)	Rate per GRT or part thereof	0.0978	1.3687
2	Sailing Vessels of 10 GRT & Upwards (except fishing boats)	Rate per GRT or part thereof	0.0587	1.1732
<b>B.</b>	<b>Schedule II - Berth Hire Charges</b>			
1	Vessels above 10 GRT	Rate per GRT per hour or part thereof	0.0025	0.0391
<b>C.</b>	<b>Schedule III - Beaching Charges</b>			
1	Beaching Charges	Rate per NRT per MTH or part thereof	0.0196	0.3911
<b>D.</b>	<b>Anchorage Charges</b>			
	Sea going mechanically propelled vessels	--	--	--
	Inner Anchorage (per GRT)	Rate per 1 hour or part thereof	0.0010	0.0255
			<b>Foreign Going Vessel (in ₹)</b>	<b>Coastal Vessel (in ₹)</b>
<b>E.</b>	<b>Schedule IV - Wharfage Charges</b>			
<b>I.</b>	<b>Liquid (in bulk)</b>			
1	POL products in bulk other than crude oil	M.T. Or part thereof	50.00	50.00

2	Other liquid cargo including bunkers	M.T. Or part thereof	50.00	30.00
<b>II.</b>	<b>Dry Cargoes</b>			
1	Fertilizer and raw material including sulphur	M.T. Or part thereof	33.60	20.16
2	Foodgrains, cereals, pulses and oilseeds	M.T. Or part thereof		
	(i). Bulk		15.00	9.00
	(ii). Break Bulk		9.00	5.40
3	Cement and clinker	M.T. Or part thereof	22.50	13.50
4	Ores and minerals (in all forms)	M.T. Or part thereof	16.88	10.13
5	Granites and marbles	M.T. Or part thereof	22.50	13.50
6	Metals (Ferrous/non-ferrous & metals scrap including pipes, pig iron, coil sheet & cokes.	M.T. Or part thereof	37.50	22.50
7	Animals including chicken, sheep & goats	Each	6.52	3.91
8	Animals (other than above)	Each	15.64	9.39
9	Animal products, bone meal, hides and skin	M.T. Or part thereof	9.78	5.87
10	Oil cakes and fodder	M.T. Or part thereof	15.00	9.00
11	Waste paper and newsprint	M.T. Or part thereof	30.00	18.00
12	Construction material and sand	M.T. Or part thereof	16.88	10.13
13	Coal and coke (including firewood)	M.T. Or part thereof	25.20	15.12
14	Wood, timber and bamboo	Cu. M.	30.00	18.00
15	Jute & jute products and coir products	M.T. Or part thereof	22.50	13.50
16	Cotton including cotton waste	M.T. Or part thereof	22.50	13.50
17	Salt	M.T. Or part thereof	15.00	9.00
18	Sugar	M.T. Or part thereof	15.00	9.00
19	Asbestos	M.T. Or part thereof	-	-
20	Synthetic resin and wood pulp	M.T. Or part thereof	45.00	27.00
21	Arms, ammunition, explosives and defence stores	M.T. Or part thereof	97.50	58.50
22	Dry chemicals including soda ash,	M.T. Or part	22.50	13.50

	HDPE, etc.	thereof		
23	Other unspecified goods	M.T. Or part thereof	52.50	31.50
<b>F.</b>	<b>Schedule V – Storage Charges for general cargo</b>			
1	For open space	Rate per 10 sq. mtr. or part thereof per month or part thereof (in ₹)	Kutchha Plots	Pucca Plots
	0 – 60 days		23.34	144.00
	61 – 90 days		46.68	288.00
	91 – 180 days		58.35	360.00
	Beyond 180 days		70.03	432.00
2	For covered space			
	0 – 60 days			279.00
	61 – 90 days			558.00
	91 – 180 days			697.50
	Beyond 180 days			837.00
3	Storage of timber on board	Rate per 10 sq. mtr. or part thereof per day or part thereof (in ₹)		1.96
<b>G.</b>	<b>Schedule VI - Trolley Hire Charges</b>	Rate per day or part thereof (in ₹)		19.55

**General Notes:**

- (i). Whenever no specific rate is available, the rate prescribed for the corresponding items at Kandla will apply provided the relevant services offered / facilities provided at tuna port are at par with those at Kandla.
- (ii). The terms and conditions of rendering the services at Tuna will be same as prescribed for corresponding services at Kandla provided for comparable services offered / facilities provided and are as given below:
  - (a). Period for the purpose of calculation of Storage charges shall be counted taking into account the period of stay of the cargo, both for open and covered areas.
  - (b). Application for storage spaces shall be made before storage of goods to the DPT or its authorised official. Any unauthorised occupation of storage spaces shall be liable for payment of double the rent, as a penalty.
  - (c). Storage charges shall be paid in advance. Penal interest, as prescribed in point no. (viii) in 1.2. General Terms and Conditions in Chapter I shall be levied on the amount due but not paid from the date on which the amount becomes due till the date of actual payment which shall in no case exceed 7 days. If, for any reason, payment is delayed beyond 7 days from the date of the amount becoming due occupation will be treated as unauthorised.
  - (d). The space allotted shall be vacated on notice from the DPT or its authorised official failing which it will be treated as unauthorised occupation; and, the Port Authorities shall take other action, as deemed fit.
  - (e). The DPT shall have the right to take over the spaces, allotted on rental basis, which are unoccupied/empty without any prior notice in the interest of the

Port operation. In such cases, proportionate reduction in rent shall be allowed.

- (f). The day for the purpose of levy of storage charges will be from 08.00 hrs to 08.00 hrs.
- (g). If operational area is leased on rental to users, storage charges on containers/demurrage on cargo stored therein shall not be levied again.
- (iii). The aggregate amount of bill shall be rounded off to the next higher rupee. ”
- (ii). **Renumber the existing Chapter-V - Tariff for Marine related services provided by DPT at Dry bulk terminal commissioned by AKBTPPL at Tuna / Tekra' in the existing SOR of DPT as Chapter-VA**
- (iii). Delete the note no.(xv) prescribed in the existing SOR of DPT under Chapter I - Definitions and General Terms and Condition.

15.2 The DPT is advised to suitably incorporate the above provision in its SOR.

15.3. The said charges shall be effective from 11 August 2016 as proposed by DPT and its validity is made co-terminus to the validity of the existing SOR of DPT i.e. upto 30 September 2019. The approval accorded shall automatically lapse unless, specifically extended by this Authority.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./136/19]

[illegible]



	Inner Anchorage (per GRT)	Rate per 1 hour or part thereof	-	-	0.001	0.0255	0.001	0.0255	-		-		0.00%	
<b>D.</b>	<b>Schedule IV - Wharfage Charges</b>													
<b>A.</b>	<b>Liquid (in bulk)</b>													
1	POL products in bulk other than crude oil	M.T. Or part thereof	15.00	9.00	50.00	50.00	50.00	50.00	455.56%		455.56%		0.00%	
2	Other liquid cargo including bunkers	M.T. Or part thereof	15.00	9.00	50.00	30.00	50.00	30.00	233.33%		233.33%		0.00%	
<b>B.</b>	<b>Dry Cargoes</b>													
1	Fertilizer and raw material including sulphur	M.T. Or part thereof	15.00	9.00	33.60	20.16	33.60	20.16	124.00%		124.00%		0.00%	
2	Foodgrains, cereals, pulses and oilseeds	M.T. Or part thereof												
	(i). Bulk		7.50	4.50	15.00	9.00	15.00	9.00	100.00%		100.00%		0.00%	
	(ii). Break Bulk				9.00	5.40	9.00	5.40	20.00%		20.00%		0.00%	
3	Cement and clinker	M.T. Or part thereof	12.00	7.20	22.50	13.50	22.50	13.50	87.50%		87.50%		0.00%	
4	Ores and minerals (in all forms)	M.T. Or part thereof	11.25	6.75	16.88	10.13	16.88	10.13	50.07%		50.07%		0.00%	
5	Granites and marbles	M.T. Or part thereof	15.00	9.00	22.50	13.50	22.50	13.50	50.00%		50.00%		0.00%	
6	Metals (Ferrous/non-ferrous & metals scrap including pipes, pig iron, coil sheet & cokes.	M.T. Or part thereof	15.00	9.00	37.50	22.50	37.50	22.50	150.00%		150.00%		0.00%	
7	Animals including chicken, sheep & goats	Each	5.00	3.00	15.00	9.00	6.52	3.91	200.00%		30.33%		-56.56%	
8	Animals (other than above)	Each	12.00	7.20	30.00	18.00	15.64	9.39	150.00%		30.42%		-47.83%	
9	Animal products, bone meal, hiders and skin	M.T. Or part thereof	7.50	4.50	15.00	9.00	9.78	5.87	100.00%		30.44%		-34.78%	
10	Oil cakes and fodder	M.T. Or part thereof	7.50	4.50	15.00	9.00	15.00	9.00	100.00%		100.00%		0.00%	
11	Waste paper and newsprint	M.T. Or part thereof	13.50	8.10	30.00	18.00	30.00	18.00	122.22%		122.22%		0.00%	

12	Construction material and sand	M.T. Or part thereof	11.25	6.75	16.88	10.13	16.88	10.13	50.07%		50.07%		0.00%	
13	Coal and coke (including firewood)	M.T. Or part thereof	12.00	7.20	25.20	15.12	25.20	15.12	110.00%		110.00%		0.00%	
14	Wood, timber and bamboo	M.T. Or part thereof	10.50	6.30	30.00	18.00	30.00	18.00	185.71%		185.71%		0.00%	
					Cu. m.	Cu. m.	Cu. m.	Cu. m.						
15	Jute & jute products and coir products	M.T. Or part thereof	10.50	6.30	22.50	13.50	22.50	13.50	114.29%		114.29%		0.00%	
16	Cotton including cotton waste	M.T. Or part thereof	9.00	5.40	22.50	13.50	22.50	13.50	150.00%		150.00%		0.00%	
17	Salt	M.T. Or part thereof	2.50	1.50	15.00	9.00	15.00	9.00	500.00%		500.00%		0.00%	
18	Sugar	M.T. Or part thereof	7.50	4.50	15.00	9.00	15.00	9.00	100.00%		100.00%		0.00%	
19	Asbestos	M.T. Or part thereof	9.00	4.50	-	-	-	-	-		-		-	
20	Synthetic resin and wood pulp	M.T. Or part thereof	15.00	9.00	45.00	27.00	45.00	27.00	200.00%		200.00%		0.00%	
21	Arms, ammunition, explosives and defence stores	M.T. Or part thereof	18.00	10.80	97.50	58.50	97.50	58.50	441.67%		441.67%		0.00%	
22	Dry chemicals including soda ash, HDPE, etc.	M.T. Or part thereof	10.50	6.30	22.50	13.50	22.50	13.50	114.29%		114.29%		0.00%	
23	Other unspecified goods	M.T. Or part thereof	15.00	9.00	52.50	31.50	52.50	31.50	250.00%		250.00%		0.00%	
E.	<b>Schedule V - Storage Charges for general cargo</b>				<b>Kutchha Plots</b>	<b>Pucca Plots</b>	<b>Kutchha Plots</b>	<b>Pucca Plots</b>	<b>Kutchha Plots</b>	<b>Pucca Plots</b>	<b>Kutchha Plots</b>	<b>Pucca Plots</b>	<b>Kutchha Plots</b>	<b>Pucca Plots</b>
1	<b>For open space</b>													
	0 – 60 days	Rate per 10 sq. Mtr. or part thereof per month or part	7.50		84.00	144.00	23.34	144.00	1020.00%	1820.00%	211.20%	1820.00%	-72.21%	0.00%

		thereof (in ₹)												
	61 – 90 days				168.00	288.00	46.68	288.00	2140.00%	3740.00%	522.40%	3740.00%	-72.21%	0.00%
	91 – 180 days				210.00	360.00	58.35	360.00	2700.00%	4700.00%	678.00%	4700.00%	-72.21%	0.00%
	Beyond 180 days				252.00	432.00	70.03	432.00	3260.00%	5660.00%	833.73%	5660.00%	-72.21%	0.00%
2	<b>For covered space</b>													
	0 – 60 days		48.00		279.00		279.00		481.25%		481.25%	481.25%	0.00%	
	61 – 90 days				558.00		558.00		1062.50%		1062.50%	1062.50%	0.00%	
	91 – 180 days				697.50		697.50		1353.13%		1353.13%	1353.13%	0.00%	
	Beyond 180 days				837.00		837.00		1643.75%		1643.75%	1643.75%	0.00%	
3	Storage of timber on board	Rate per 10 sq. Mtr. or part thereof per day or part thereof (in ₹)	1.50		--		1.96		--		30.67%	30.67%	--	
F.	<b>Schedule VI - Trolley Hire Charges</b>	Rate per day or part thereof (in ₹)	15.00		--		19.55		--		30.33%	30.33%	--	
* In 2016 Order a note as proposed by DPT was prescribed stating that rates for Kandla Port will be applicable for Tuna Port. Accordingly, in the above table, the applicable rate for Kandla land is shown for Tuna port for comparison as 2016 rates.														
% increase / decrease estimated based on coastal rates which is relevant for Tuna port.														